हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 फरवरी, 2020

खण्ड–1 अंक–3

अधिकृत विवरण

सील

विषय सूची

सोमवार, 24 फरवरी, 2020

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने के संबंध में सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं/स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करना

गैर–सरकारी दिवस से संबंधित मामला उठाना

विभिन्न मामले/मांगे उठाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 24 फरवरी, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र□न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

To Check the Problem of Stray Cattles

***1 Dr. Abhe Singh Yadav:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

(a) the steps taken or likely to be taken by the Government to check the problem of stray cattles in Mahendergarh District;

(b) whether damage of crops caused due to stray cattles has ever been assessed by the Government in Mahendergarh District; and

(c) immediate plan of the Government to save the present Rabi crop from this menace?

Deputy Chief Minister (Dushyant Chautala) : Sir,

(a) Following steps have been taken to check the problem of stray cattle in Mahendergarh District :-

(i)Government has already initiated the process of setting up of Gaushalas, Cattle pound and Cow Abhyaran in the State. 11 Gaushalas/Cattle pounds have been setup in District Mahendergarh to accommodate stray cattle.

(ii)All the Deputy Commissioners have been instructed to get the Gau Ghar and Cattle pounds constructed in villages as per requirement and as per provision under section 21 (XXVI) of Haryana Panchayati Raj Act 1994.

(iii)As per the provision in the Haryana Municipal Ownerless and Stray Cattle Bye-laws 1976, authorized officers of the Municipal Committees, are seizing ownerless animals found straying within the limit of Municipality.

(iv)A provision has been made in Panjab Village Common Land (Regulation) Rules, 1964 for lease of Shamilat lands for setting up of Gaushalas in rural areas;

(b) No, Sir;

(c) The Government is committed to resolve the problem of stray cattle. While the measures taken or proposed to be taken will yield

results in time, in the meanwhile, stray cattle will be shifted to Gushalas where feasible.

डॉ. अभय सिंह यादव : सर, उप–मुख्यमंत्री द्वारा मेरे प्रश्न का जवाब यह आया है कि सरकार द्वारा आवारा पशुओं को गऊशालाओं में बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, यह एक गम्भीर समस्या है क्योंकि किसान के खेत में एक बार में 20 से 30 गायों का झुण्ड घुसता है और किसान की पूरी फसल को नष्ट कर देता है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस प्रश्न के ऊपर आपका सप्लीमेंट्री क्या है?

डॉ. अभय सिंह यादव : सर, मेरा सप्लीमेंट्री यही है कि जो उप–मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि सरकार आवारा पशुओं के लिए प्रबंध कर रही है। उसमें मैं समझता हूं कि केवल प्रबंध करना काफी नहीं है क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में 50–50 गायों के झुण्ड घूम रहे हैं और वे किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं इसलिए मैं मंत्री जी से केवल इतना आश्वासन चाहता हूं कि वे कम से कम जब तक रबी की फसल की कटाई न हो तब तक महेंद्रगढ़ जिले की सारी गायों को गौशालाओं में भिजवा देंगे तो फिर मैं इनके जवाब से सहमत हो जाउंगा।

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर 538 गऊशालाएं हैं जिनमें 4 लाख से अधिक गायें हैं । इसमें पंचायती राज विभाग अपनी ओर से ग्राम पंचायतों को अधिकार देता है जिसके अन्दर ग्राम पंचायत योजना बनाई है जिसमें सरकार ग्राम पंचायतों को 5100, 7100 रुपये प्रति गाय के हिसाब से पैसा देगी। म्यूनिसिपल कमेटी व कॉरपोरेशंज द्वारा भी अपनी ओर से रोहतक में साढ़े सात एकड़ जमीन में, हिसार में 12 एकड़ जमीन में, सिरसा में 47 कनाल जमीन में एक–एक गऊशालाएं खोली गई हैं और गुरूग्राम में लगभग 12 एकड़ जमीन में 2 गऊशालाएं खोली गई हैं। मैं कह सकता हूं कि यह सामाजिक तौर पर बहुत जरूरी चीज है कि हम गऊ सेवा के अन्दर पूरी तौर से अपने आप को समर्पित करें। सरकार ने उसके ऊपर पंचायती राज विभाग द्वारा पहले ही योजना बना रखी है। इसके साथ–साथ माननीय सदस्य का जो सवाल है उसके ऊपर मैं इनको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से प्रदेश के अन्दर वैसे तो पशु मेले लगने बन्द हैं लेकिन फिर भी तीस ऐसी निर्धारित जगह हैं जहां पर प्रदेश में 300 से अधिक पशु

मेले लगते हैं। अगर आने वाले समय में किसी भी ब्लॉक से पशु मेले लगाने के लिए कोई प्रस्ताव आएगा तो विभाग उस पर जरूर विचार करेगा।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो उप मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार आवारा पशुओं के संबंध में प्रयास कर रही है यह बड़ी अच्छी बात है कि सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रही है लेकिन उप–मुख्यमंत्री जी मुझे इस संबंध में केवल मात्र छोटा सा एक आश्वासन दे दें कि अगले दो महीने में महेंद्रगढ़ जिले की सारी आवारा गायं गऊशाला में होंगी। अगर उप–मुख्यमंत्री जी ऐसा करवा देंगे तो मैं इनका बड़ा आभारी रहूंगा।

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल मात्र महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जितने भी विधायक साथी यहां बैठे हुए हैं वे सभी एक संकल्प लें कि वे अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर जहां भी ग्राम पंचायत हमें पशु फाटक या गऊ गृह के लिए जमीन दे सकती है तो उसके लिए हम प्रस्ताव लाकर उनकी आर्थिक सहायता भी करेंगे और हम वहां पर पशु फाटक व गऊ गृह बनाने का काम भी करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दे दीजिए। एक सदस्य दो सप्लीमेंट्री से ज्यादा नहीं पूछ सकता।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, एक सदस्य दो सप्लीमेंट्री पूछ सकता है और वे दोनों ही सप्लीमेंट्री अभय सिंह जी ने ही पूछी हैं क्योंकि यह प्रश्न उन्हीं का है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, हमें भी सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) यह तो बिल्कुल गलत बात है।

श्री अध्यक्षः किरण जी, जिस सदस्य का प्रश्न होता है वह उस प्रश्न के संबंध में दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। माननीय सदस्य ने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछा है और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब भी दे दिया है। इसलिए अब आप प्रश्न काल को सुचारू रूप से चलने दें और अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जिस सदस्य का प्रश्न होता है वह अपने प्रश्न पर दो सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछ सकता है लेकिन इसके साथ ही दूसरे सदस्य भी

तो संबंधित प्रश्न पर अपने सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं? अगर आप विपक्ष को सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देंगे तो प्रश्न काल का क्या फायदा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विपक्ष को भी सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत दी जानी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, प्रश्न काल के दौरान 20 प्रश्नों के लिए एक घंटे की समयावधि नियत होती है। यदि एक प्रश्न पर विभिन्न सदस्य बारी–बारी से सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछने लग गए तो फिर प्रश्न काल का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा? यदि आप भी सेम नेचर के प्रश्न को पूछना चाहते थे तो आप सबको भी संबंधित प्रश्न के नेचर वाला अपना प्रश्न अलग से सदन की कार्यवाही में शामिल करने के लिए लगाना चाहिए था। अतः आप प्लीज सभी बैठिए और सदन की कार्यवाही को चलने दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो लगा देते लेकिन आप तो प्रश्न भी लॉटरी से निकाल रहे हैं जिसकी वजह से भी हम चाहकर भी अपना प्रश्न नहीं लगा पा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से विपक्ष को सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत न देकर एक गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, मैं कोई गलत परंपरा शुरू नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियमों के हिसाब से ही सदन की कार्यवाही को चला रहा हूँ। हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के रूल 53 के भाग (2) में लिखा हुआ है किः–

> **"कोई भी सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर किसी भी ऐसे तथ्य के विषय के, जिसके बारे में कोई उत्तर दिया गया है, स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए कोई अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है:"**

आप सभी इस रूल के हिसाब से बात कर रहे हैं लेकिन यदि आप इसी रूल में आगे पढेंगे तो इसमें यह भी लिखा हुआ पायेंगे किः–

"परन्तु अध्यक्ष, किसी भी अनुपूरक प्रश्न को अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में, वह प्रश्न संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है।"

ये सभी बातें रूल्ज में लिखी हुई हैं और इन रूल्ज को मैंने नहीं लिखा है। मैं जिस रूल की बिनाह पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ उस रूल को आप सब भी नियमावली में देख सकते हैं। अतः आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से में मुझे सहयोग दें।

.....

Construction of Sports Stadium

***41. Smt. Nirmala Chaudhary:** Will the Minister of Sports & Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct sports stadiums in villages Khubru and Purkhas of Ganaur Assembly Constituency; if so, the details thereof?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। गांव पुरखास में पहले से एक स्टेडियम निर्मित है।

श्रीमती निर्मल रानीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः मेरा प्रश्न स्टेडियम के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, के संदर्भ में है। मेरे क्षेत्र में जो पुरखास गांव में स्टेडियम है वहां पर सुविधाओं का अभाव है। इस गांव से 40–50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होकर निकले हैं। उनको अर्जुन अवार्ड तथा एकलव्य अवार्ड तक मिल चुके हैं। कोई भी स्टेडियम महज चारदीवारी से नहीं बनता बल्कि तमाम प्रकार की अनेकों खेल सुविधाओं का समावेश करके ही कोई स्टेडियम अपना मूर्त रूप धारण कर पाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पुरखास गांव के स्टेडियम की सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाये और साथ ही मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि वे एक बार हमारे पुरखास गांव का दौरा करने जरूर आयें ताकि हमारे खिलाड़ियों को और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिले। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन में यह पहला प्रश्न है और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय खेल मंत्री जी भी सदन में आज जो अपना जवाब दे रहे हैं, यह भी उनका पहला जवाब है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से हमारे माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी मंत्री बने

हैं उस दिन से हमारे खिलाड़ियों में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है और उन सभी खिलाड़ियों का भी बहुत दिल है कि माननीय खेल मंत्री जी पुरखास का दौरा जरूर करें।

सरदार संदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेल भावना की बात है तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमें स्टेडियम की अपेक्षा खेलों को ज्यादा बढ़ावा देने की दिशा में अपना ध्यान देना चाहिए। हमारे पास जो आलरेडी स्टेडियम मौजूद हैं, हमें उनको अच्छी तरह से मैंटेन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश में कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ है। हमें इस दिशा में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारी जो आने वाली जैनरेशन है उनकी खेलों में और ज्यादा रूचि बढ़े और उनको दूसरे युवा अपना आइडल समझकर खेलों में और ज्यादा दिलचस्पी लें। हमें खेलों में नई प्रतिभाओं व खेल नर्सरीज को नित रोज बढ़ाने का काम करना चाहिए। जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं हमारी सरकार उन बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी कार्य करेगी और पुराने खिलाड़ियों को रोल मॉडल बनाकर युवाओं का खेलों के प्रति रूझान पैदा करने का काम भी किया जायेगा।

श्री अध्यक्षः मैडम, क्या आप माननीय मंत्री जी के रिप्लाई से संतुष्ट हैं?

श्रीमती निर्मल रानीः अध्यक्ष महोदय, मैं पुरखास स्टेडियम में समय–समय पर जाती रहती हूँ और यही नहीं मैंने अभी कल ही पुरखास गांव के स्टेडियम का दौरा भी किया था। अध्यक्ष महोदय, वहां पर अभी भी सुविधाओं की बड़ी भारी कमी है।

सरदार संदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस गांव की बात माननीय सदस्या कर रही हैं उसमें आलरेडी एक खेल स्टेडियम है जिसमें 7 खेल खेले जा रहे हैं और यहां पर 4 कोचिज वर्तमान में कार्यरत भी हैं। वैसे माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया था वह खेल स्टेडियम के निर्माण करने के बारे में था। इस प्रश्न में स्टेडियम में मूलभूत सुविधओं को उपलब्ध कराने का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्षः मैडम, माननीय मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अपने प्रश्न में यह लिखा है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के गांव खूबरू तथा पुरखास में खेल स्टेडियमों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आपने अपने प्रश्न में स्टेडियम में सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं पूछा है?

श्रीमती निर्मल रानी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

.....

Payment of Compensation for Cutting of Trees

***54. Shri Shamsher Singh Gogi:** Will the Forests Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that many trees have been cut on Karnal-Kaithal and Karnal-Assandh roads for widening of roads; and

(b) whether it is also a fact that half payment in lieu of compensation for cutting of trees has been paid to farmers; if so, the total amount of compensation of the farmers pending towards Government togetherwith the time by which said compensation is likely to be paid to the farmers?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल सिंह) :

(क) हां, महोदय ।

(ख) महोदय, वृक्ष बंटवारा नियम 1987 के प्रावधान के तहत करनाल–कैथल सड़क के किनारे सरकारी भूमि में खड़े वृक्षों में से 20 वृक्ष एक किसान को 50 प्रतिशत हिस्से के रूप में दिए गए हैं ।

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट माननीय मंत्री जी से यह है कि तीनों मार्गों पर कितने वृक्ष काटे गए हैं और उनका कैसे बंटवारा किया गया है? उस बंटवारे के समय विभाग के कौन–कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद थे? ऐसी कौन सी लूट मची हुई थी कि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक अपना हिस्सा नहीं ले पाये। कहीं ऐसा काम तो नहीं किया गया कि पेड़ की टाहनियों को बालने के लिए किसानों को हिस्से के मुताबिक दे दी गई हों और बाकी का हिस्सा वन विभाग ले गया हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पूर्ण डिटेल के साथ सदन में संबंधित प्रश्न का जवाब दें। करनाल से मूनक जो सड़क जाती है, उस मार्ग पर भी कितने वृक्षों को काटा गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि तीनों मार्गों पर हजारों की संख्या में वृक्ष काटे गए हैं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, करनाल से कैथल सड़क मार्ग–1 को चौड़ा करने के लिए 8170 वृक्षों को काटा गया है और करनाल से कैथल मार्ग–2 सड़क से

11576 वृक्षों को काटा गया है। करनाल से असंध सड़क मार्ग पर 563 वृक्षों को काटा गया है। इस प्रकार से टोटल 20309 वृक्षों को काटा गया है। अध्यक्ष महोदय, यह नियम केवल कृषि उक्त खेती के साथ सड़क के किनारे लगते तीन मीटर सीमा क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में खड़े वृक्षों पर लागू होती है। वृक्ष बंटवारा नियम–1987 के प्रावधान के तहत संबंधित किसान अपना हिस्सा लेने के लिए जमीन का मालिकाना हक के सबूत के साथ अपना प्रार्थना–पत्र वन विभाग के अधिकारियों को देता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन की जरूरत होती है और इस कारण नियम के मुताबिक साईड के पेड़ काटने पड़ते हैं। सड़क के तीन मीटर अंदर तक किसान की हिस्सेदारी भी रहती है। करनाल–कैथल सड़क मार्ग चौड़ी करने के लिए किसान के खेत की साईड की तरफ नहीं बल्कि सड़क के किनारे सरकारी भूमि में खड़े वृक्षों को काटा गया था। केवल एक ही किसान ने अपना हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया था और इस एवेज में 20 वृक्षों को 50 प्रतिशत के हिस्से के मुताबिक दे दिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में वन विभाग को लेकर एक नई घोषण करना चाहता हूँ कि पहले यह नियम हुआ करता था कि किसान को अपना हिस्सा लेने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के पास प्रार्थना–पत्र देना होता था लेकिन आज से किसान की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं वन विभाग के अधिकारी किसान के पास जायेंगे। विभाग पर ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि ऐसी स्थिति में विभाग अच्छे पेड़ तो अपने पास रख लेते हैं और खराब यानी छोटे–मोटे पेड़ हिस्सेदारी के रूप में किसानों को दे देते हैं। सरकार वृक्ष बंटावारा नियम– 1987 में संशोधन करेगी कि वृक्षों का बंटवारा वन विभाग करेगा। जैसे मान लो 50 वृक्ष हैं तो 25–25 वृक्षों के दो हिस्से होंगे उसमें से किसान की पहली मर्जी होगी कि कौन सा हिस्सा अपने पास रखेगा। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, पहले भी वृक्ष बंटवार नियम यही है। यदि वन विभाग किसान की हिस्सेदारी देने में गलती करता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पहले के लगे हुए वृक्षों को काटना जरूरी हो जाता है लेकिन जब विभाग पेड़ काटने जाता है तो क्या वह किसान से पूछता है कि हम आपके खेत से लगते 3 मीटर के एरिया में से पेड़ काटने जा रहे हैं और उनकी संख्या वगैरह चैक करने के लिए आप भी वहां पर आ जाइये । यह विभाग की जिम्मेदारी है । जिस दिन चौधरी देवीलाल जी ने यह नियम बनाया था

उसी दिन से किसानों को पेड़ काटने की जगह पर बुलाना आवश्यक था । अतः मेरा कहना है कि जिस दिन से यह गड़बड़ी हो रही है उस दिन से आज तक उसका विभाग से हिसाब ले लीजिए ।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो इनको दूसरी तरफ बैठे हुए साथियों से पूछनी चाहिए ।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पिछले 5 साल का हिसाब मांग रहा हूं । फिर भी अगर माननीय मंत्री जी को ऐसा ही लगता है कि यह प्रश्न इधर के साथियों से पूछना चाहिए तो आप इधर के साथियों को उधर बैठा दीजिए फिर मैं इन साथियों से यह प्रश्न पूछ लूंगा ।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, पेड़ काटने का अब तक यह नियम था कि पेड़ काटने के समय किसान वहां पर जाएगा और कहेगा कि मेरे खेत के साथ लगते हुए पेड़ काटे जा रहे हैं और इनमें मेरी हिस्सेदारी है । इसके बाद सरकार किसान की हिस्सेदारी का फैसला करती थी । इस प्रक्रिया में किसानों को एतराज था और अब हमने इसको चेंज कर दिया है । इसके अलावा अब हमने इसमें एक फैसला और किया है कि अब हम किसान के खेत के साथ लगती हुई जमीन पर उससे पूछकर ही पेड़ लगाएंगे । हम नहीं चाहते कि हम ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो क्योंकि इससे किसान का फायदा बहुत कम हो जाता है । हम चाहते हैं कि हम जो पेड़ लगाएं उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो और उससे किसानों को भी अच्छा लाभ मिले । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं सुधार की बात कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने के लिए दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, आप सवाल पूछिये बहस मत करिये । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह भी देता । आप अब मुझे बोलने दीजिए नहीं तो मैं अपना प्रश्न ही भूल जाऊँगा ।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, आप अपना सवाल पूछिये ।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें इस संबंध में केवल एक ऐप्लीकेशन प्राप्त हुई है जबकि इस संबंध में सौ आदमी तो अकेले मुझसे मिल चुके हैं । इसी वजह से मैंने विधान सभा में यह प्रश्न लगाया है। मेरी कांस्टीच्युएंसी में जीन्द रोड, मूनक रोड, कैथल रोड पर अनेक पेड़ों को काटा गया है । इसके बावजूद अगर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके विभाग

के पास इस संबंध में सिर्फ एक ऐप्लीकेशन आई है तो इस मामले में गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, आप माननीय मंत्री जी को उन सड़कों की लिस्ट दे देना जिन पर लगे हुए पेड़ों को विभाग ने काटा है।

.....

To Shift The Bus Stand

***17. Dr. Kamal Gupta:** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to shift the Bus stand of Hisar outside the City at Bye-Pass; if so, the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री मूलचन्द भार्मा) : श्रीमान् जी, हाँ। इस संबंध में सिरसा – दिल्ली बाई पास पर स्थित 74 कनाल 15 मरला भूमि जिसकी मलकियत पशु पालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा की है, का चयन किया गया है जिसके स्वामित्व परिवर्तन के लिए परिवहन विभाग का अनुरोध पशु पालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा में विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग से जमीन के स्वामित्व परिवर्तन होते ही इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा ।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में लिखा है कि विचाराधीन है । अतः जब जमीन का चयन कर लिया गया है तो विचाराधीन होने का क्या अर्थ है ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे बस अड्डे का निर्माण कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा ?

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जमीन के स्वामित्व परिवर्तन होते ही इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बस अड्डों पर जो जन–सुविधाएं होनी चाहिए क्या हरियाणा प्रदेश के सभी बस–अड्डों पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बस–अड्डों पर पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, साफ–सफाई आदि सुविधाएं होती हैं । आज से 10 साल पहले बस–अड्डों पर जो सुविधाएं नहीं थी वे सभी सुविधाएं हम जनता को अवश्य देंगे ।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी बस स्टैंड पर सफाई नहीं है और किसी भी बस स्टैंड के गेट पर जाकर देखेगें तो वहां पर आवारा पशु ही बैठे मिलते हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सभी बस स्डैंट्स पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वहां पर आवारा पशु बैठे रहते हैं।

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

.....

Construction Work of Medical College

***35. Dr. Krishan Lal Middha :** Will the Medical Education Minister be pleased to state-

(a) the details of phases of construction work of Medical College, Jind completed till to date; and

(b) the total amount likely to be spent on the above said project togetherwith the total amount spent on it so far?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान् जी,

(क) जींद में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लगभग 3 साल में दो चरणों में पूरे होने की परिकल्पना करती है। प्रथम चरण के निर्माण के लिये 524.23 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगें और शेष राशि 139.63 करोड़ रूपये दूसरे चरण के निर्माण के लिये खर्च की जायेगी।

निर्माण कार्य के अस्थायी निविदा के लिये कार्यकारी एजेंसी हरियाणा राज्य सड़क और पूल विकास निगम लिमिटेड विस्तृत सूचना आमंत्रित निविदा तैयार कर रही है। जींद में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के स्थल के चारों ओर की चारदीवारी पहले ही बन चुकी है।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जींद में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण पर खर्च होने वाली कुल मंजूर राशि 663.86 करोड़ रूपये है।

इस परियोजना के लिये अब तक कुल 6,42,30,131.00 रूपये (छह करोड़ बयालिस लाख तीस हजार एक सौ इक्कतीस केवल) जारी किये गये हैं।

डॉ0 कृष्ण लाल मिड्ढा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि संबंधित वर्क्स की डी.पी.आर. तैयार होने के बाद भी निर्माण कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है और निर्माण कार्य के लिए कब तक टैंडर जारी किये जाने की संभावना है ? प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के स्थान के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली के खम्भे कब तक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि दिनांक 24.5.2015 को इसकी घोषणा की गयी थी। इस कार्य में काफी विलम्ब हो रहा है। इसको जल्दी करवाया जाए ताकि जीन्द जिले की जनता को फायदा मिल सके।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग 4 कॉलेजिज का निर्माण करवाने जा रहा है। इसमें एक कॉलेज जीन्द में, दूसरा कॉलेज भिवानी में, तीसरा कॉलेज नारनौल में और चौथा कॉलेज गुरूग्राम में खोला जाएगा। इन चारों कॉलेजिज के वर्क्स अलॉट कर दिये गये हैं और प्रोसैस में है। इनमें से कुछ वर्क्स के कान्सैप्ट प्लॉन बना रहे हैं, कुछ की डी.पी.आर. बन चुकी है और उन्हीं एजेंसीज के द्वारा संबंधित कॉलेजिज का निर्माण कार्य किया जाना है। लगभग 3 महीने में जीन्द के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे।

डॉ0 कृष्ण लाल मिड्ढा: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जब 6 साल पहले श्रीमती श्रुति चौधरी भिवानी–महेन्द्रगढ सीट से मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गयी थी तो उन्होंने उस दौरान मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था और इसके बारे में तत्कालीन प्रदेश सरकार के पास दिनांक 19.4.2014 को चिट्ठी भी भेजी गयी थी। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि संबंधित कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। पहली बात तो यह है कि उसमें 6 साल का डिले हो चुका है, लेकिन अभी तक यह क्लीयर नहीं हुआ है कि भिवानी

में कहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा ? क्योंकि कभी कहा जाता है कि संबंधित मेडिकल कॉलेज प्रेम नगर में बनेगा और कभी कहा जाता है कि भिवानी में ही बनाया जाएगा। हमें यह कब तक बताया जाएगा कि भिवानी में संबंधित मेडिकल कॉलेज कहां पर बनेगा ? इसके साथ–साथ यह भी बताया जाए कि इसमें कितने पैसे लगाये जाएंगे ताकि वहां की जनता को इसकी जानकारी लग सके। 6 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में संबंधित मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, लेकिन उस पर आज तक सरकार द्वारा एक भी ईंट नहीं लगायी गयी है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सैपरेट क्वैश्चन है। चूंकि इस समय माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री हुड्डा साहब यहां पर उपस्थित नहीं हैं और शायद माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी ही डिप्टी सी.एल.पी. लीडर हैं। माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा और स्पष्ट भी करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में भिवानी के संबंधित मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नहीं किया गया। इस बात के लिए उस समय माननीय सदस्या तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री हुड्डा साहब के साथ लड़ा करती थी और उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी जारी की थी। इसके शिवा कुछ नहीं किया। इसके लिए हमारी सरकार ने ही आगे का कार्य शुरू किया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताएं कि भिवानी में मेडिकल कॉलेज कहां पर बनाने जा रहे हैं ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि वे थोड़ा धैर्य रखें। हम भिवानी जिले के लिए मेडिकल कॉलेज बनाकर देंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार चिकित्सा महाविद्यालय प्रेमनगर में बनाने का काम करेगी या दूसरी जगह बनाने का काम करेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जायें, माननीय मंत्री जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : M/s Bridge and Roof, a Central Public Sector Undertaking को काम दिया है और उन्होंने drawings and the DPR amounting to Rs. 524.95 cr. has been prepared by the Executing Agency. वहां सरकार कॉलेज बनाने जा रहे हैं and the process is on, Sir. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

.....

To Upgrade Civil Hospital

***2. Shri Laxman Singh Yadav:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 50 bedded hospital up to 100 bedded hospital in Kosli; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded?

Health Minister (Shri Anil Vi) : No, Sir.

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 138 गांव हैं और इन गांवों में पूर्व–पश्चिम और उत्तर–दक्षिण दिशाएं लगती हैं। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों के लोगों को बड़े अस्पताल तक जाने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर कनैक्टिविटी पूरी होने के कारण मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल बनाने का काम करे। यदि सरकार अभी हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ा अस्पताल नहीं बनवा सकती तो भविष्य में वहां पर एक बड़ा अस्पताल बनाने का कष्ट जरूर करे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने इसका सर्वे करवाया था और 100 बैड के अस्पताल के लिए पॉपुलेशन की रिक्वायरमैंट वह क्षेत्र पूरी नहीं करता है। अभी इस क्षेत्र की वर्तमान

पॉपुलेशन 1,27,407 आंकी गई है। अगर वहां पर 100 बैड का अस्पताल बनाने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार विचार कर लेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान पापूलेशन तो कई गुणा ज्यादा है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मैडीकल कॉलेजिज को बने हुए 5 साल से ज्यादा का समय बने हो गया है, अभी तक सरकार की तरफ से इनमें डायरैक्टर अप्वॉयंट नहीं किए हैं इसलिए पहले वहां पर डायरैक्टर अप्वॉयंट करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आपका यह अलग सप्लीमैंटरी क्वैश्चन है इसलिए आप प्लीज बैठ जायें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जहां तक मैडीकल कॉलेज का प्रश्न है वह प्रोसैस में है इसलिए माननीय सदस्य हाउस को गुमराह न करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैडीकल कॉलेज में डायरैक्टर लगाने की बात है तो कमेटी ने इन्टरव्यू लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस भर्ती पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय से इस भर्ती से रोक हट जाएगी तो हमारी सरकार डायरैक्टर्ज की भर्ती कर देगी। (शोर एवं व्यवधान)

———————

To Develop Industrial Area

***134. Shri Amarjeet Dhanda :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that there is no Industrial Unit in Julana Constituency; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to develop Industrial Area by the HSIIDC in Julana Assembly Constituency?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) नहीं, श्रीमान् जी, जुलाना विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयॉ चल रही है।

(ख) वर्तमान में जुलाना विधान–सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं सरंचना विकास निगम लिमिटिड़ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अमरजीत ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जुलाना क्षेत्र एन.सी.आर. में आता है। अगर हम आज इस महान सदन में जुलाना क्षेत्र के विकास की बात करें तो वहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन वहां के किसानों के लिए खेती बाड़ी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अधिकतर इलाका तो सूखे की मार झेल रहा है और कुछ इलाके में सेम की बहुत भारी समस्या है। इस इलाके में रोजगार की व्यवस्था भी नाममात्र की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाये।

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 13 उद्योग कुंज स्थापित किए जा रहे हैं और इसमें से एक गांव शादीपुर के अंदर ''उद्योग कुंज योजना'' के माध्यम से उद्योग कुंज स्थापति किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जिसके अंदर 27 छोटे उद्योग कुंज डिवैल्प हो चुके हैं और 8 उद्योग कुंज इम्प्लीमैंटेशन में हैं और वहां पर अभी 14 प्लॉट खाली पड़े हैं इसलिए आने वाले समय में हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आयेंगी उनके माध्यम से इन्डस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा जींद जिला, अमृतसर, कलकत्ता और मुम्बई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का हिस्सा है इसलिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा जींद और नरवाना में भी उद्योग लगाने की व्यवस्था करेंगे।

———————————

To Construct Building Of Sub-Division

***189. Shri Kuldeep Vats :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct building of Sub-Division at Badli; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :

(a) Yes Sir.

(b) The land for construction of building of Sub-Division Badli is being finalised and thereafter, construction of the said building will be taken up.

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2016 के अंदर बादली विधान सभा क्षेत्र में मोटा झोटा नामक रैली की थी जिसमें बादली को सब–डिवीजन बनाया गया था। वहां पर एक पुरानी बिल्डिंग में सब–डिवीजन स्तर के सभी ऑफिसिज को चलाया जा रहा है। जिस पुरानी बिल्डिंग में इन सभी ऑफिसिज को चलाया जा रहा है उसकी हालत बहुत ही जर्जर है। मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चार साल का समय बीत जाने के बाद भी वहां पर नई बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई गई है? इन ऑफिसिज के लिए नई बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे हल्के के मोहम्मदपुर माजरा गांव ने 45 कनाल 18 मरला जमीन भी दी हुई है। क्या सरकार की नीति में खोट है या फिर सरकार की नियत में खोट है जो वहां पर बिल्डिंग के लिए जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अभी तक नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं करवाया गया है?

श्री दुष्यंत चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि अगर रिक्वॉयरमैंट के हिसाब से बादली हल्के में उप–मण्डल कांम्पलैक्स के लिए जमीन उपलब्ध है तो हम अगले तीन महीने के अंदर वहां पर उप–मण्डल कांम्पलैक्स का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे।

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मेरा उपमुख्यमंत्री जी से यह भी निवेदन है कि उप–मण्डल स्तर के सभी कार्यालयों के लिए एक ही स्थान पर बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्द से

जल्द करवाने की मैं एक बार फिर से उपमुख्यमंत्री महोदय से रिकवैस्ट करता हूं। धन्यवाद।

————————

To Re-Include Village in Bhadurgarh Tehsil

***229. Shri Rajender Singh Joon :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that village Daboda Kalan which is just 3.5 K.M. from Bahadurgarh City has been removed from Bahadurgarh Tehsil and included in Badli Tehsil, which is 17 K.M. from said village; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re-include the abovesaid village in Bahadurgarh Tehsil togetherwith the details thereof?

Deputy Chief Minister (Dushyant Chautala) : No, Sir. Revenue Estate (village) Daboda Kalan is part and parcel of Bahadurgarh Tahsil as on date.

श्री राजेन्द्र सिंह जून : स्पीकर सर, मैं उप मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में डाबोदा कलां गांव को तहसील बहादुरगढ़ से निकालकर बादली तहसील में डाल दिया गया था। डाबोदा कलां और मेहंदीपुर गांव मेरे विधान सभा हल्के के आखिरी गांव हैं। इन गांवों की सीमा के बाद बादली तहसील शुरू हो जाती है। अगर किसी को बादली जाना होता है तो उसको दाबोदा कलां से 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके दाबोदा खुर्द में जाना पड़ता और वहां पर उसको बादली जाने के लिए यातायात का कोई साधन मिलता है। दाबोदा खुर्द से बादली की दूरी 17 किलोमीटर है जबकि दाबोदा कलां से बहादुरगढ़ की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी पुनः उप मुख्यमंत्री जी से रिकवैस्ट है कि दाबोदा कलां गांव को फिर से बहादुरगढ़ तहसील के साथ जोड़ दिया जाये ताकि लोगों को इस कारण से हो रही परेशानी से मुक्ति मिले।

श्री दुष्यंत चौटाला : स्पीकर सर, जो आदरणीय विधायक जी ने बात रखी है इस सम्बन्ध में मैं इनके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जब बहादुरगढ़ को सब–डिवीजन से तहसील बनाया गया था उसके बाद जो कार्यवाही हुई। मिनीमम क्राईटेरिया यह था कि 45 गांवों के माध्यम से उसको डिवाईड किया जा सकता

था। इनके सब–डिवीजन के केस के अंदर 39 गांवों को लिया गया था। जिन गांवों का जिक्र माननीय विधायक जी ने स्वयं किया वे रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक अभी भी बहादुरगढ़ तहसील के साथ अटैच हैं। जो मेरे संज्ञान में मामला आया था कि जो कागजी कार्यवाही थी उसी को ही बहादुरगढ़ से बादली शिफ्ट कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में हमने डॉयरैक्शन दे दी है कि उनको भी वापिस बहादुरगढ़ शिफ्ट कर दिया जाये। रेवेन्यू रिकार्ड के अंदर आज भी ये प्रस्तावित गांव बहादुरगढ़ तहसील का ही हिस्सा हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : स्पीकर सर, मेरी उपमुख्यमंत्री जी से यह रिकवैस्ट है कि जिन गांवों का मैंने जिक्र किया उनके सभी काम बहादुरगढ़ में हों ऐसी व्यवस्था करवा दी जाये। धन्यवाद।

.....

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, श्री रामस्वरूप रामा, पूर्व खेल राज्य मंत्री, हरियाणा, विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं । मैं पूरे सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत करता हूँ।

.....

तारांकित प्र□न एंव उत्तर (पुनरारम्भ)

Construction of Building of Government College For Boys Rewari

***25. Shri Chiranjeev Rao :** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Government College for Boys in Rewari; and

(b) If so, the time by which the construction work of the above said building is likely to be started?

शि□क्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): (क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) राजकीय महाविद्यालय, रेवाड़ी के भवन के निर्माण का कार्य वित्त वर्ष 2020–21 मे आंरभ कर दिया जायेगा ।

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि वर्ष 2020–21 में रेवाड़ी में लड़कों के लिए महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे लेकिन अभी तक तो उसके लिए जमीन भी आबंटित नहीं हुई है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उसके लिए कितनी जमीन और कहां पर आबंटित की गई है?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस कॉलेज के लिए 5.32 एकड़ जमीन का प्रावधान था लेकिन जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विभाग को जमीन दी गई वह 5 एकड़ दी गई है तथा सरकार ने इस कॉलेज के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की तरफ से मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं आया है कि इसके लिए जमीन कहां पर ऐलोकेट की गई है तथा मैं दूसरा प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार की पॉलिसी भी है कि एक लाख तक की जनसंख्या पर किसी भी कॉलेज के निर्माण के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए लेकिन रेवाड़ी की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है तो वहां पर 5 एकड़ में कैसे कॉलेज खुल सकता है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पहले यह कॉलेज केवल लड़कों के लिए था लेकिन अब सरकार ने इसको (Co-Ed) यानि लड़कों और लड़कियों के लिए कर दिया है, कॉऐड कॉलेज के लिए 5 एकड़ जमीन बहुत कम है। इस कॉलेज को फुली फंक्शन होने के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि इस पॉलिसी में बदलाव करके कॉऐड कॉलेज के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन का प्रावधान किया जाये ताकि यह कॉलेज फुली फंक्शन हो सके।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय, रेवाड़ी शैक्षणिक सत्र 2017–18 से सांध्यपारी में केवल कला संकाय की 80 छात्रों की एक ईकाई के साथ राजकीय महाविद्यालय, रेवाड़ी के वैकल्पिक भवन में आरम्भ किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2018–19 में महाविद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी (नजदीक भाड़ावास गेट) में कला संकाय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष सहित स्थानान्तरित किया गया। महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में वाणिज्य संकाय भी आरम्भ कर दिया गया था। वर्तमान में महाविद्यालय में कलां एवं वाणिज्य

संकाय चलाई जा रही है। महाविद्यालय में कुल (239 लड़के व 5 लड़कियां) 244 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय, रेवाड़ी के भवन निर्माण हेतु मामला विभाग के सक्रिय विचाराधीन है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा सैक्टर–20 रेवाड़ी में 5.32 एकड़ी भूमि महाविद्यालय हेतु प्रस्तावित की गई है परन्तु 5.32 एकड़ी भूमि में से मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला द्वारा केवल 5.00 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई है। 5.32 एकड़ी भूमि की रूप–रेखा अनुसार महाविद्यालय भवन निर्माण की (ड्राईंग) रेखाचित्र विभाग द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1/5–2011 नि. (2) दिनांक 18.11.2019 को अनुमोदित कर दी गई थी। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा 12.00 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 1/5–2011 निं. (2) दिनांक 20.12.2018 के तहत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) हरियाणा, चण्डीगढ़ के पक्ष में प्रमाणिक आधार पर जारी की जा चुकी है।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य रूप से सवाल ये था कि जिस तरह से कॉलेज खोलने के लिए मिनीमम 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए । मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि क्या 5 एकड़ के अन्दर भी कोई गवर्नमैंट कॉलेज खुल सकता है? लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी वहां वर्तमान में उस महाविद्यालय में 244 स्टुडैंट्स पढ़ते हैं जिसमें (239 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं।) सर, इस संबंध में मंत्री जी मेरा जवाब तो दे ही नहीं पाए। मैंने मंत्री जी से यह पूछा है कि क्या 5 एकड़ जमीन के अन्दर कोई गवर्नमैंट कॉलेज खुल सकता है? मंत्री जी ने कहा है कि अभी वहां पर 244 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या मंत्री जी को लगता है कि आगे भी वहां पर 244 बच्चे ही रहेंगे।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की विधान सभा में 11 कॉलेजिज हैं। वहां पर गवर्नमैंट कॉलेज खोलने के लिए जो जमीन उपलब्ध हुई है और जिसकी हमने मंजूरी दी थी वह 5.32 एकड़ जमीन ही थी और जिस दिन वहां शुरूआत में कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी उस समय भी हमें वहां पर 5.32 एकड़ जमीन ही मिली थी। ऐसा नहीं है कि पहले वहां ज्यादा जमीन मिल रही थी और अब कम मिल रही है। वहां अभी भी बच्चों की संख्या केवल 244 ही है।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वहां जो 5.32 एकड़ जमीन निर्धारित की है वह भी गलत की है और इसके लिए जो बजट आया था वह भी गलत था।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, अर्बन एरिया में 5 एकड़ जमीन में भी कॉलेज बन सकता है।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : चिरंजीव जी, अगर आपने इसमें और कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप उसको लिख कर भेज दीजिए।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि सरकार की पॉलिसी है कि कॉलेज खोलने के लिए 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए लेकिन मंत्री जी का जवाब है कि अभी वहां 244 बच्चे हैं इसलिए 5 एकड़ जमीन पर यह कॉलेज बनाया जाएगा। क्या मंत्री जी यह सोचते हैं कि 5 साल बाद भी वहां 244 बच्चे ही रहेंगे ?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, कॉलेज खोलने के लिए ग्रामीण एरिया में 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए और अर्बन एरिया में 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उस कॉलेज को को–एड कर दिया है जो बड़े शर्म की बात है। अभी वहां (239 लड़के और 5 लड़कियां हैं।)

श्री अध्यक्ष : चिरंजीव जी, मंत्री जी बता रहे हैं कि कॉलेज बनाने का अर्बन में जो कराईटेरिया है वह 5 एकड़ भूमि का है। मंत्री जी ने इतनी बात आपको दो बार बता ली है उसके बाद फिर आप बार–बार कह रहे हैं कि इसके बारे में बताएं।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को पॉलिसी दिखा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : चिरंजीव जी, मंत्री जी पॉलिसी ही बता रहे हैं कि कॉलेज बनाने के लिए अर्बन एरिया के अन्दर 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए और ग्रामीण एरिया में 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में श्री राम बिलास शर्मा जी जब शिक्षा मंत्री थे उन्होंने सदन के पटल पर आश्वासन दिया था कि जहां–जहां कॉलेजिज की जरूरत होगी वहां पर कॉलेजिज बनेंगे क्या मंत्री जी

आप उस आश्वासन को कॉन्टीन्यू करेंगे will you continue the same as was promised by the previous Education Minister Shri Ram Bilas Sharma ji. पिछली बार सदन के पटल पर राम बिलास शर्मा जी ने कॉलेजिज बनाने का आश्वासन दिया था उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के तहत कहा था कि हम तोशाम विधान सभा के जूही के अन्दर लड़कियों के लिए कॉलेज बनाएंगे क्या मंत्री जी उसको अब शुरू करेंगे?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती किरण चौधरी : मंत्री जी, मैं तो यह पूछना चाहती हूं कि अगर अब वहां कॉलेज बनाने का विचार खत्म हो गया है तो अब हम उसके लिए दोबारा से नये सिरे से रिक्वेस्ट शुरू करें।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि वहां पर कॉलेज बनाने का विचार खत्म नहीं हुआ है। हम उसकी जांच करवा लेते हैं।

.....

Detail of Teaching Staff

***111. Shri Mamman Khan:** Will the Education Minister be please to state the school wise and category wise details of teaching staff sanctioned and presently working in the Government school of Ferzepur Jhirka Assembly Constituency togetherwith the time by which vacant posts of teachers in said schools are likely to be filled up?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) :श्रीमान् जी, विवरण विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

श्रीमान् जी, फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 17 राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय, 9 राजकीय उच्च विद्यालय, 107 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 180 राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुचारु रुप से कार्य कर रहे हैं। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापन स्टाफ का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रम संख्या	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत (नियमित) अध्यापकों की संख्या	रिक्तियां / खाली पदों की संख्या
1.	प्रिसिपल / प्राचार्य	17	13	04
2.	मुख्य अध्यापक	09	0	9
3.	पी0जी0टी0	302	160	142
4.	मौलिक षिक्षा हैडमास्टर	132	108	24
5.	प्रषिक्षित ग्रेजुएट अध्यापक / सी0एण्ड0वी0	761	209	552
6.	मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)	117	101	16
7.	जे0बी0टी0 / प्राथमिक अध्यापक	1537	929	608
	कुल जोड़	**2875**	**1520**	**1355**

अध्यापक स्टॉफ के स्वीकृत पद, भरे हुए पदों एवं खाली पदों का विद्यालयवार तथा श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित हैः–

(क) राजकीय वरिश्ठमाध्यमिक / राजकीय उच्च विद्यालय

	पी0जी0टी0			टी0जी0टी0			
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पदों की संख्या**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**
1	राजकीय कन्या वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय अहमदबास	10	5	5	5	2	3
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पदों की संख्या**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**
2	राजकीय कन्या वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर झिरका	20	11	9	7	5	2
3	राजकीय कन्या वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय नगीना	19	8	11	12	8	4
4	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय ऐंगन	8	5	3	8	2	6
5	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय बदरपुर	19	7	12	7	2	5
6	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय बदर	8	4	4	5	3	2
7	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक	10	6	4	5	2	3

	विद्यालय बाजीदपुर						
8	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय भगडोली	12	0	12	8	1	7
9	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय बीवन	11	6	5	5	3	2
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पदों की संख्या**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**
10	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर झिरका	20	14	6	10	4	6
11	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय मंडी खेड़ा	23	15	8	5	4	1
12	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय मुलतान	10	4	6	5	1	4
13	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय नगीना	25	19	6	7	3	4
14	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय पधखोरी	13	3	10	7	5	2
15	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय रनियाला	11	6	5	10	2	8
16	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय रवाली	13	6	7	5	4	1
17	राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक विद्यालय सकरास	15	6	9	7	4	3
18	राजकीय उच्च विद्यालय बेसकखानजादा	7	5	2	5	3	2
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पदों की संख्या**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**
19	राजकीय उच्च विद्यालय भदहास	6	5	1	10	6	4
20	राजकीय उच्च विद्यालय भुभलहेरी	5	2	3	7	3	4

21	राजकीय उच्च विद्यालय दौहा	5	5	0	7	0	7
22	राजकीय उच्च विद्यालय माहुन	5	5	0	7	3	4
23	राजकीय उच्च विद्यालय मरौरा	6	4	2	7	4	3
24	राजकीय उच्च विद्यालय नीमखेड़ा	6	3	3	8	2	6
25	राजकीय उच्च विद्यालय पटकपुर	6	1	5	7	3	4
26	राजकीय उच्च विद्यालय उमरा	6	5	1	8	5	3
		299	**160**	**139**	**791**	**209**	**552**

(ख) राजकीय माध्यमिक विद्यालय

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
27	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अखलीमपुर, नूंह	5	1	4
28	राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणा बी	5	0	5
29	राजकीय माध्यमिक विद्यालय फकरपुर खोरी	4	1	3
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
30	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हमजापुर	5	1	4
31	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खानपुर, नूंह	5	1	4
32	राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोहिगा खुर्द	5	0	5
33	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुठली	5	0	5
34	राजकीय माध्यमिक विद्यालय उमरी	4	1	3
35	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भगौला	5	0	5
36	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बैसमीओ	5	1	4
37	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बिवान–।	6	1	5

38	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बिवान–।।	5	0	5
39	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ढाणा	5	0	5
40	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय दौहा	5	2	3
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
41	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय दौरखी	5	0	5
42	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जैतका	5	1	4
43	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जरखपुरी	5	0	5
44	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय झिरका	7	3	4
45	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कमेदा	5	3	2
46	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कंकरखेडी	5	0	5
47	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खुषपुरी	5	0	5
48	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मण्डी खेड़ा	5	1	4
49	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मुलतान	5	0	5
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
50	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा	5	0	5

51	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय रावली	5	3	2
52	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय रिठत	5	0	5
53	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सुलतानपुर नूंह	5	1	4
54	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय तिगांव	5	0	5
55	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय उमरा	6	0	6
56	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय उमरी	5	0	5
57	राजकीय माध्यमिक विद्यालय ए0एस0 बाद	5	0	5
58	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अहमदवास	6	0	6
59	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अखांका	7	4	3
प्रशिक्षित स्नातक िक्षक (टी0जी0टी0)				
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
60	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अकलीमपुर एफ0पी0	5	0	5
61	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलीपु	5	1	4
62	राजकीय माध्यमिक विद्यालय भगौला	5	2	3
63	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बायखेड़ा	5	1	4
64	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बलाई	5	2	3
65	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनारसी	5	0	5
66	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बसई मयूं	5	3	2
67	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बौद	8	3	5
68	राजकीय माध्यमिक विद्यालयबिवान	5	2	3
69	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुखारा के0जी0	5	2	3

70	राजकीय माध्यमिक विद्यालय डी0एस0पुर	5	1	4
71	राजकीय माध्यमिक विद्यालय धदौली कला	5	1	4
72	राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाला	5	1	4
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
73	राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूगेजा	5	0	5
74	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गन्दूरी	5	1	4
75	राजकीय माध्यमिक विद्यालय घांघस	7	1	6
76	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गठासमसा बाद	5	0	5
77	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोहाना	6	3	3
78	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोकलपुर	10	5	5
79	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुमतबिहारी	5	2	3
80	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हसनपुर	5	1	4
81	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हसनपुर बिलोरा	5	2	3
82	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हीरुवारी	7	2	5
83	राजकीय माध्यमिक विद्यालय इब्राहिमबास	5	0	5
84	राजकीय माध्यमिक विद्यालय इमाम नगर	5	3	2
85	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैतका	4	1	1
प्रशिक्षत स्नातक अध्यापक (टी0जी0टी0)				
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
86	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जलालपुर नूंह	7	0	7
87	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जलालपुर	7	2	5
88	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जरगाली	5	2	3
89	राजकीय माध्यमिक	5	0	5

	विद्यालय जरका सिसवाना			
90	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जेटकाला	8	1	7
91	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जगपुरी	5	2	3
92	राजकीय माध्यमिक विद्यालय के0एम0पुर	5	0	5
93	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कालीबास	5	1	4
94	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कन्साली	7	0	7
95	राजकीय माध्यमिक विद्यालय करहेडा	5	0	5
96	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खानपुर घाटी	7	3	4
97	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेरली कला	6	2	4
98	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेरली खुर्द	5	1	4
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
99	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोलगांव	7	1	6
100	राजकीय माध्यमिक विद्यालय ललीबास	5	0	5
101	राजकीय माध्यमिक विद्यालय माधी	5	1	4
102	राजकीय माध्यमिक विद्यालय माहौली	5	2	3
103	राजकीय माध्यमिक विद्यालय मलहाका	5	1	4
104	राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोहलका	5	1	4
105	राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदबास	5	0	5
106	राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदनगर	5	2	3
107	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहरीका	7	0	7
108	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाई नगलां	5	0	5
109	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नगल मुबारिकपुर	8	5	3
110	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंगला षाहपुर	5	1	4

111	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नवाली	8	2	6
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
112	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नोटकी	5	2	3
113	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पढला षाहपुरी	5	0	5
114	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पटान उदयपुरी	5	2	3
115	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पथराली	7	2	5
116	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रजाका	8	2	6
117	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रंगला राजपुर	5	1	4
118	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रानिका	5	2	3
119	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रानिका	5	2	3
120	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रावां	7	2	5
121	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रिथट	5	3	2
122	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सकरस	7	1	6
123	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरल	5	2	3
124	राजकीय माध्यमिक विद्यालय षखावारी	5	2	3
125	राजकीय माध्यमिक विद्यालय षेखपुर	5	1	4
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
126	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिदरावत	5	0	5
127	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुखपुरी	5	0	5
128	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुलेला	5	2	3
129	राजकीय माध्यमिक विद्यालय ठेक	4	1	3
130	राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिगांव	5	1	4

131	राजकीय माध्यमिक विद्यालय उलेटा	5	2	3
132	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिमरावठ	5	0	5
133	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हमजापुर	0	0	0
	कुल योग	**761**	**209**	**552**

(ग) राजकीय प्राथमिक पाठ□ाला

प्राथमिक अध्यापक/मुख्य □िक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
134	राजकीय कन्या प्राथमिकपाठशाला भादस	11	9	9
135	राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बिवान	12	4	8
136	राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बिवान	12	6	6
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य □िक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
137	राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मण्डी खेडा	7	5	2
138	राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला रावली	7	6	1
139	राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला सकरस	11	4	7
140	राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला उमरी	6	5	6
141	राजकीय प्राथमिक पाठशाला अगोन	17	11	6
142	राजकीय प्राथमिक पाठशाला अहमदबास	7	5	2
143	राजकीय प्राथमिक पाठशाला एन्चक्वारी	8	5	3
144	राजकीय प्राथमिक पाठशाला उखलीमपुर, नूहं	8	4	4
145	राजकीय प्राथमिक पाठशाला उखलीमपुर, फिरोजपुर	7	5	2
146	राजकीय प्राथमिक पाठशाला अखांका	11	6	5

147	राजकीय प्राथमिक पाठशाला अलीपुर टिगरा	7	4	0
148	राजकीय प्राथमिक पाठशाला अमका	7	4	3
149	राजकीय प्राथमिक पाठशाला असाई षीका	3	3	0
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
150	राजकीय प्राथमिक पाठशाला अटेरना समसाबाद	13	7	6
151	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बदरपुर	11	10	1
152	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडेड	12	6	6
153	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडोपुर	4	3	1
154	राजकीय प्राथमिक पाठशाला भगौला	15	11	4
155	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बहरीपुर	3	2	1
156	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाई खेड़ा	6	5	1
157	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बजीदपुर	8	5	3
158	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बलाई	9	2	7
159	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बनारसी	9	4	5
160	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसई खानजदा	8	5	3
161	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसई मयुं	20	7	13
162	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बवनथेडी	10	6	4
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
163	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडास	9	8	1
164	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बखोजी	17	12	5
165	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बौंद	14	7	7
166	राजकीय प्राथमिक पाठशाला भोदबास	4	3	1

167	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिलकपुर	5	3	2
168	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिवान	14	4	10
169	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बुबलहेडी	16	8	8
170	राजकीय प्राथमिक पाठशाला बुखारका	9	8	1
171	राजकीय प्राथमिक पाठशाला चैकरगांला (शाखा)	4	4	0
172	राजकीय प्राथमिक पाठशाला चैनपुरी	16	4	12
173	राजकीय प्राथमिक पाठशाला चन्दराका	7	5	2
174	राजकीय प्राथमिक पाठशाला चितौडा	5	3	2
175	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धनीवास	5	3	2
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
176	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धगौला	8	6	2
177	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धडौली कला	9	6	3
178	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धडौली खुर्द	6	5	1
179	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धमाला	8	5	3
180	राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढाणा बी0	16	8	8
181	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धौदं कला	8	5	3
182	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धौंद खुर्द	5	4	1
183	राजकीय प्राथमिक पाठशाला दौहा	18	11	7
184	राजकीय प्राथमिक पाठशाला डोडल	9	5	4
185	राजकीय प्राथमिक पाठशाला दोराखी	12	5	7
186	राजकीय प्राथमिक पाठशाला दौगरा षाहजादपुर	9	4	5
187	राजकीय प्राथमिक पाठशाला डूगेजा	9	6	3

188	राजकीय प्राथमिक पाठशाला फिरोजपुर झिरका	8	6	2
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
189	राजकीय प्राथमिक पाठशाला फिरोजपुर झिरका बी0	12	6	6
190	राजकीय प्राथमिक पाठशाला फकरपुर खोरी	7	3	4
191	राजकीय प्राथमिक पाठशाला फिरोजपुर ढहक	6	5	6
192	राजकीय प्राथमिक पाठशाला फौडाबास	5	3	2
193	राजकीय प्राथमिक पाठशाला गन्डूरी	12	7	5
194	राजकीय प्राथमिक पाठशाला धागंस			
195	राजकीय प्राथमिक पाठशाला घाटा समसाबाद	10	5	5
196	राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोहाना	9	4	5
197	राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोकुलपुर	11	10	1
198	राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुजर नंगना	12	6	6
199	राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोमुर बिहारी	9	5	4
200	राजकीय प्राथमिक पाठशाला यासीनाबास	6	3	3
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
201	राजकीय प्राथमिक पाठशाला हबीतका	7	6	1
202	राजकीय प्राथमिक पाठशाला हमजापुर	4	3	1
203	राजकीय प्राथमिक पाठशाला हसनुपर बिलोदा	8	7	1
204	राजकीय प्राथमिक पाठशाला हसनुपर,	8	4	4

	नूंह			
205	राजकीय प्राथमिक पाठशाला हीरवारी	11	9	2
206	राजकीय प्राथमिक पाठशाला हु–हुका	2	2	0
207	राजकीय प्राथमिक पाठशाला इब्राहिमवास	8	3	5
208	राजकीय प्राथमिक पाठशाला ईलीबास	8	6	2
209	राजकीय प्राथमिक पाठशाला ईमामनग	7	6	1
210	राजकीय प्राथमिक पाठशाला इन्द्रा कालोनी ़फिरोजपुर)	4	2	2
211	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जैतका	6	5	1
212	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जैटलका	12	7	5
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
213	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जलालपुर एफ0पी0	10	6	4
214	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जलालपुर नूंह	8	5	3
215	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जलीखौरी (शाखा)	3	3	0
216	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जरगली	5	4	1
217	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जैटका सिसवाना	8	4	4
218	राजकीय प्राथमिक पाठशाला जरपुरी	11	6	5
219	राजकीय प्राथमिक पाठशाला झिमरावत	7	3	4
220	राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलाखेडा	5	4	1
221	राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलियावास	6	3	3
222	राजकीय प्राथमिक पाठशाला कमेडा	7	4	3
223	राजकीय प्राथमिक पाठशाला कनसाली	18	7	11

224	राजकीय प्राथमिक पाठशाला करहेडा	10	5	5
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
225	राजकीय प्राथमिक पाठशाला करहेडी	4	4	0
226	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खानमोहमदपु	7	5	2
227	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खानपुर घाटी	12	5	17
228	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खानपु नूंह	7	6	1
229	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खेरला कला	6	3	3
230	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खेरला खुर्द	4	4	0
231	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खेरली कला	10	9	1
232	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खेरली खुर्द	9	5	4
233	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खेली नूंह	6	6	0
234	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोरी मलहाका ;षाखाद्ध	3	2	1
235	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुखपुरी	8	6	2
236	राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोलगांव	13	7	6
237	राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोलटाजपुर	4	4	0
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
238	राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुल डेरा	5	4	1
239	राजकीय प्राथमिक पाठशाला लोहिगां खुर्द	11	6	5
240	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंडापुर	7	6	1

241	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मांडी	6	3	3
242	राजकीय प्राथमिक पाठशाला माहौली	9	5	4
243	राजकीय प्राथमिक पाठशाला माहू	5	3	2
244	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मेहुन	14	8	6
245	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मलहाका	10	4	6
246	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंडी खेडा	7	6	1
247	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मरोरा	15	9	6
248	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोहम्मदबास	9	6	3
249	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोहम्मदबास बोचाका	10	4	6
250	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोहम्मद नगर	8	5	3
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
251	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोहलका	9	4	5
252	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुलथान	11	7	4
253	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुडाका	3	3	0
254	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगीना (हरीजन बस्ती)	9	6	3
255	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगीना सह षिक्षा	32	17	15
256	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नहरीका	10	6	4
257	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाई नगंला	8	3	5
258	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगल मुबारिकपुर	15	5	10
259	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगल षाहपुर	5	3	2
260	राजकीय प्राथमिक	6	2	4

	पाठशाला नंगला सबट			
261	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नांगली	9	4	5
262	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नसीजबास	7	4	3
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
263	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नवली	12	8	4
264	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नीमखेडा बी0	11	6	5
265	राजकीय प्राथमिक पाठशाला नोटकी	7	3	4
266	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पढला षाहपुरी	6	4	2
267	राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्रतापबास	3	3	0
268	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पटखोरी	13	6	7
269	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पटकपुर फिरोजपुर	5	4	1
270	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पटकपुर रानियाला	5	4	1
271	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पटन उदयपुरी	3	2	1
272	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पथराली	8	7	1
273	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पिठोरपुरी	4	3	1
274	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पोल षाखा	3	2	1
275	राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुठली	6	5	1
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
276	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रजाकां	15	9	6
278	राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजौली	3	2	1
278	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रंगला	10	6	4

	राजपुर			
279	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रानियाला पटकपुर	12	10	2
280	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रानिका	7	4	3
281	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रानियाला	13	7	6
282	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रानीयाली	7	5	2
283	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रानौटा	6	2	4
284	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रावा	14	4	10
285	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रावली	7	6	1
286	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रिगढ़	16	8	8
287	राजकीय प्राथमिक पाठशाला रिथक	13	8	5
288	राजकीय प्राथमिक पाठशाला साईमीर वास	7	5	2
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
क्रम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
289	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सकरपुरी	3	3	0
290	राजकीय प्राथमिक पाठशाला साका वास (शाखा)	2	2	0
291	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सकरस	12	9	3
292	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सकरस ()शाखा	11	6	5
293	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सरल	5	3	2
294	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सारूपा वास खोरी	3	2	1
295	राजकीय प्राथमिक पाठशाला षादीपुर	5	5	0
296	राजकीय प्राथमिक पाठशाला षाहापुर	4	3	1
297	राजकीय प्राथमिक पाठशाला षाहपुर	4	2	2
298	राजकीय प्राथमिक पाठशाला षाहपुरी	6	4	2

299	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सतावरी	9	6	3
300	राजकीय प्राथमिक पाठशाला षेख पुर	8	5	3
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
301	राजकीय प्राथमिक पाठशाला षिव कालौनी (एफ0पी0)	10	5	5
302	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिधरावत	6	3	3
303	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोलपुर (शाखा)	4	2	2
304	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुभाश कालौनी (एफ0पी0)	5	4	1
305	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुगेरपुर	3	2	1
306	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुखपुरी	7	1	6
307	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुलेला	6	4	2
308	राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुलतानपुर, नूह	8	5	3
309	राजकीय प्राथमिक पाठशाला तिगांव	13	11	2
310	राजकीय प्राथमिक पाठशाला उलेटा	8	6	2
311	राजकीय प्राथमिक पाठशाला उमरी	5	4	1
312	राजकीय प्राथमिक पाठशाला उमरा	15	8	7
प्राथमिक अध्यापक/मुख्य शिक्षक (प्राथमिक)				
कम संख्या	**विद्यालय का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
313	राजकीय प्राथमिक पाठशाला यनुसका वास (शाखा)	7	5	2
	कुल जोड़	**1537**	**929**	**608**

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्राधानाचार्यो, राजकीय उच्च विद्यालयों मे हैड मास्टर और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य शिक्षक ों के पद पदोन्नति पद है। इन पदो को भरने के लिये मामले आमंत्रित किये गये

है जो कि तीन महीने में पूरा होने की सम्भावना है। पी0जी0टी0, टी0जी0टी0 के पद सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते है। इन श्रेणियो के लिए पदोन्नति के मामले पहले से ही आमंत्रित किये जा चुके है और तीन महीनों में पदोन्नति के पद भरे जाने की सम्भांवना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पी0जी0टी0, टी0जी0टी0 और पी0आर0टी0/जे0बी0टी0 श्रेणियों की रिक्तियां दो महीने के अन्दर सीधी भर्ती हेतु भेज दी जायेंगी।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेवात एक ऐसा जिला है जो नीति आयोग के सर्वे में भी देश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। हमारे यहां जो बच्चे स्कूल्ज में पढ़ने के लिए जाते हैं वे कुर्सी व मेज को ही मास्टर समझ कर अपने घर वापिस आ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे मेवात में हैड मास्टर की 9 पोस्टें हैं जो सारी खाली पड़ी हुई हैं। हमारे यहां पी.जी.टी. की 60 प्रतिशत पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। हमारे एलीमेंट्री स्कूल हैड की 18 प्रतिशत पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। हमारे वहां टी.जी.टी. की 72 प्रतिशत पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और जे.बी.टी अर्थात प्राईमरी टीचर्स की 40 प्रतिशत पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उर्दू टीचर्स की पोस्टों की इसमें कोई डिटेल नहीं दी है जबकि मैंने वह डिटेल मांगी थी क्योंकि उर्दू टीचर्स की भी ज्यादातर पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं । हमारा मुस्लिम एरिया है इसलिए वहां पिछली सरकार ने उर्दू टीचर्स की सीटें फिल की थी लेकिन आज तक उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि There is not a single PGT Teacher in the subjects like Computer Science, Physical Education, Fine Arts and Psychology. कम्प्यूटर में टोटल 12 पोस्टें हैं जोकि सभी खाली पड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ प्रधान मंत्री देश को डिजिटल बनाने के लिए अग्रसर हैं वहीं मेवात के झिरका विधान सभा में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी पी.जी.टी. कम्प्यूटर टीचर नहीं है। मैं फिजिक्स की बात करता हूं । आज देश में साईंस बहुत आगे जा चुकी है। 12 सीट्स में से सिर्फ 2 ही सीट्स ऐसी हैं जिन पर फिजिक्स के टीचर्स अवेलेबल हैं। ऐसा लगता है कि साइंस एंड टैक्नोलोजी के आधुनिक युग में आज भी मेवात के विद्यार्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि कहा गया है कि रिक्त पड़े पदों को तीन महीने की समयावधि में भर दिया जायेगा, उस संदर्भ में मैं एक बात जरूर

कहना चाहूंगा कि मान लो एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और उसको एग्जाम के समय पेपर दिया जाता है तो क्या वह बच्चा एग्जाम में लिख सकता है कि जब तीन महीने के बाद मास्टर जी एप्वॉयंट हो जायेंगे और उनके पढ़ने के बाद ही वे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे पायेंगे। यदि ऐसा संभव हो सकता है तो इसके बारे में मुझे जरूर बताया जाये? (विघ्न)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानचार्यों, राजकीय उच्च विद्यालयों में हैडमास्टर और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य शिक्षकों के पद पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पद हैं। इन पदों को भरने के लिए विभागीय प्रक्रिया जारी है जो कि तीन महीने में पूरा होने की संभावना है। पी.जी.टी. व टी.जी.टी. के पद सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। इन श्रेणियों के लिए पदोन्नति से भरने वाले पदों की प्रक्रिया जारी है और तीन महीनों में पदोन्नति के पद भरे जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पी.जी.टी., टी.जी.टी. और पी.आर.टी./जे.बी.टी. श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए रिक्विजेशन दो महीने के अंदर भेज दी जायेंगी।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, तीन महीने बाद रिक्त पदों को भरने वाला आश्वासन एक तरह से आदत का रूप ले चुका है। जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके मां–बाप ने अपना सब कुछ लगा दिया है तथा बच्चों ने अपना पूरा एक साल लगा दिया है, और टीचर के अभाव में बच्चों की तैयारी नहीं है तो ऐसी अवस्था में यह बच्चे किस प्रकार से अपना एग्जाम दे पायेंगे? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मामन जी, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन तो दे दिया है कि तीन महीने की समयावधि में रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। अतः आप प्लीज बैठिए। ईश्वर सिंह जी अब आप अपनी बात रखें।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि यदि किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या कम है तो उस स्कूल को मिडिल स्कूल के स्तर तक अपग्रेड नहीं किया जायेगा। अतः इस प्रकार जिस प्राइमरी स्कूल में 10–12 बच्चे ही रह गए हैं तो वह प्राइमरी स्कूल तो मिडिल स्कूल के स्तर तक अपग्रेड हो ही नहीं सकेगा और इस प्रकार इनमें पढ़ने

वाले बच्चे तो अपनी आगामी पढ़ाई से वंचित ही रह जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल के तहत अपग्रेड करने का कोई विषय विचाराधीन है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, टीचर्ज की कमी वास्तव में बहुत ज्यादा है। जहां तक क्राइटेरिया की बात है तो इस संबंध में पहले से जो क्राइटेरिया निश्चित है, वह तो वैसे ही रहेगा लेकिन जो मूल विषय है अर्थात टीचर्ज की कमी, के संदर्भ में पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले समय में प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में टीचर्ज की पोस्टें भर दी जायेंगी और इसके बाद प्रदेश में टीचर्ज की कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसमें कोई ढ़ील नहीं दी जा सकती है। बिना बच्चों के स्कूल को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है? (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पांच किलोमीटर एरिया में कोई मिडल स्कूल नहीं है और प्राइमरी स्कूल में बच्चे कम हो गए हैं तो बताओ इसमें बच्चों का क्या कसूर है? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मूल प्रश्न का जवाब दे दिया है और आप मूल प्रश्न के संदर्भ में सप्लीमैंट्री प्रश्न के रूप में कुछ अलग प्रश्न पूछ रहे है। इसलिए आप प्लीज बैठिए। (विघ्न)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे है, अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो संभव है कि इस तरह के मामले में पुनर्विचार किया जा सकता है लेकिन जहां तक क्राइटेरिया या नियम फिक्स किए गए हैं या बनाये गए हैं तो इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इनको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जायेगा।

.....

Mining In Yamuna River

***200. Shri Bishan LaL Saini :** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state the total area of land in which the mining is being done in Yamuna River in Yamuna Nagar togetherwith the total amount of

G.S.T. accrued from mining in the State exchequer during the last five years?

खान एवं भू–विज्ञान मंत्री (श्री मूल चंद भार्मा) : श्री मान् जी, जिला यमुनानगर के यमुना नदी तल में 18 खानें हैं जिनका कुल क्षेत्र 1259.97 हेक्टेयर है। वर्तमान में यमुना नदी में 15 खानों में खनन कार्य जारी है जिनका कुल क्षेत्र 1133.42 हेक्टेयर है। जिला यमुनानगर सहित सारे राज्य में खनन गतिविधियाँ 01.03.2010 से लघु खनिजों के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जरूरत बारे मुकदमे की वहज से बंद हो गई थी। जिला यमुनानगर में अक्टूबर, 2016 में फिर से खनन कार्य शुरू हुआ तथा जनवरी, 2020 तक खान एवं भू–गर्भ विभाग ने ठेकेदारों से रूपये 246.85 करोड़ की राशि ठेके के रूप में एकत्रित की तथा जिले के यमुना नदी के ठेकेदारों ने रूपये 23.93 करोड़ जी. एस. टी. के रूप में जमा करवाये।

श्री बि□ान लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी पूरी ईमानदारी और आंकड़ों के साथ सदन में जवाब दे रहे हैं? (विघ्न)

श्री मूल चंद भार्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अवैध खनन की बात है, एन.जी.टी. के तहत लगभग 1 हजार एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं और एन.जी.टी. के तहत ही अवैध माइनिंग करते समय व्हीकल्ज जब्त किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात भी सदन में बताना चाहता हूँ कि 25 खानों के लाइसैंस रद्द कर दिए गए हैं और 5 खानों के लाइसैंस सस्पैंड कर दिए गए हैं। हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में ठेकेदार अवैध खनन करते पाये जायेंगे तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लगभग 1 हजार के करीब डम्पर सरकार ने एन.जी.टी. के तहत जब्त किए हैं।

श्री बि□ान लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, माइनिंग को लेकर जितने भी साधन चल रहे हैं, उनके पास कोई भी पक्का बिल नहीं होता है। इस प्रकार से जी.एस.टी. का कोई भी जिक्र नहीं है। ओवर लोडिंग के कारण सड़कें टूट गई हैं।

श्री मूल चंद भार्मा : अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी पर खनन करने वाले ठेकेदारों ने लगभग 23.93 करोड़ रुपये जी.एस.टी. के रूप में जमा करवायें हैं।

श्री बि□ान लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बिशन लाल जी, कितने सप्लीमैंट्री प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं? (विघ्न) आप कई बार माननीय मंत्री जी से सप्लीमैंट्री पूछ चुके हैं। (विघ्न)

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी प्रदेश में अवैध खनन की जो बात कही है उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जहां भी अवैध खनन होता है हम वहां पर कार्रवाई करते हैं । जहां पर भी हमें ट्रैक्टर, डम्परों से अवैध खनन की जानकारी मिलती है हम एन.जी.टी. के निर्देशों के तहत वे वाहन जब्त कर लेते हैं। अगर विधायक जी को कहीं पर अवैध खनन की जानकारी है तो वे हमें बताएं हम वहां पर उनके साथ जाएंगे और उसको बंद कराएंगे । जैसा कि मैंने पहले बताया है हमने पहले भी अवैध खनन को बंद करवाया है और अगर हमारी जानकारी में कोई नया मामला आएगा तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे ।

श्री धर्म सिंह छौक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में खनन के रिगार्डिंग एक गम्भीर समस्या का जिक्र करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में अवैध खनन नहीं हो रहा है जबकि सबको पता है कि अवैध खनन अपनी चरम सीमा पर है । माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय के पास पी.डब्ल्यू. (बी. एंड आर.) विभाग है । अतः वे भी इस ओर ध्यान दें । खनन करने में लगे हुए वाहनों से गांव के लोग बहुत परेशान हैं । गांवों में पूरी–पूरी रात ट्रैक्टर, डम्पर आदि वाहन चलते रहते हैं जिससे ग्रामीणों को बहुत समस्या होती है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्म सिंह जी, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री धर्म सिंह छौक्कर : अध्यक्ष महोदय, इतना तो प्रदेश में जी.एस.टी. कलैक्ट नहीं होता जितना पैसा पी.डब्ल्यू. (बी. एंड आर.) विभाग को उन सड़कों की रिपेयर पर खर्च करना पड़ता है । यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी अवैध खनन को रोकने के लिए रातों को घूमते हैं और इनके विभाग के अधिकारी वाहनों के चालान भी करते हैं । आम गरीब किसान अपने मकान, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे आदि बनाने के लिए रेत की खान से बुग्गी आदि में रेत ले आता है । पुलिस का रवैया ऐसा है कि वह ट्रकों को तो छोड़ देती है और बुग्गी को पकड़ लेती है । अतः माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । वे गरीब लोग ट्रक नहीं ले सकते लेकिन बुग्गी से रेत लाने पर पुलिस उनको पकड़ लेती है ।

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कर लेंगे ।

Election of Gaur Brahman Vidya Pracharni Sabha

***96. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the administrator has been appointed for Gaur Brahaman Vidya Pracharni Sabha, Rohtak on 31.03.2014; and

(b) if so, the reasons for which the elections of the said Institution have not been held so far?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) श्रीमान् जी, सरकार ने गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा, रोहतक के लिए आदेश दिनांक 14.03.2014 के द्वारा प्रषासक नियुक्त किया है।

(ख) गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा, रोहतक के चुनाव लम्बी मुकदमेबाजी के कारण नहीं हुए। सदस्यता विवादों/ चुनाव संबंधी मुद्दों में सभा के सदस्यों ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिकाएं और जिला रजिस्ट्रार, फर्म एवं समितियां, रोहतक के समक्ष याचिकाएं दायर की थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गौड़ ब्राहमण विद्या प्रचारिणी सभा, रोहतक में पिछले 5 साल तक अलग–अलग स्तर के प्रशासक नियुक्त किये गये थे । इसके चुनाव न होने का कारण श्रीमती संजू शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा और श्री कमल शर्मा के तीन मैटर्स का सब–ज्यूडिश होना था । अब इन तीनों केसिज का जिला रजिस्ट्रार, फर्म एवं समितियां, रोहतक ने निर्णय कर दिया है । दिनांक 4 फरवरी, 2020 को इस सोसाइटी में 76,081 मैम्बर्ज को प्रस्तावित किया गया है । हम अखबार में इनकी ऐडवर्टिजमैंट निकालकर चुनावी प्रक्रिया को आगे ले जाने का काम करेंगे ।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इनके विभाग ने गलत फीड किया हुआ है । सरकार डैमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशंज को फलने–फूलने देना नहीं चाहती । वहां के लिए 5 साल से ज्यादा समय तक कोई एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं किया जा सकता । मैं पूछना चाहता हूं कि किस कैपेसिटी से वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया हुआ है ? Sir, as per the provision of Section 68(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012, period of appointment of Administrator shall not

exceed 5 years in continuity but Sector 69(2) provides that if it is not feasible to hold election of the Governing Body for whatever reasons, it shall be competent for Government to dissolve Society. This is not the proper reply before the House. So far as litigation in the High Court is concerned अगर लिटिगेशन 10 साल तक चलती रहेगी तो क्या सरकार तब तक वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाए रखेगी ? अगर सरकार को लगता है कि वह इस सोसाइटी को रन नहीं कर सकती तो सोसाइटी को डिजॉल्व कर देना चाहिए । सरकार ने वर्ष 2014 में वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था और अब वर्ष 2020 आ चुका है । In which capacity Dy. Chief Minister are justifying it? How can he justify it कि आप एक सोसाइटी का चुनाव नहीं करवा रहे

15:00 बजे

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी खुद एक वकील भी हैं और उन्होंने बात रखी है कि संबंधित सोसायटी को डिजॉल्व कर दें। यह एक ऐतिहासिक सामाजिक सोसायटी है और मुझे लगता है कि आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन ऐतिहासिक सामाजिक संस्थाओं को स्ट्रैन्थन करें। माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि किस कैपेसिटी में यह काम किया है ? इसमें Under Societies Act, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक साल के एक्सटैंशन की पॉवर है।

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, इसमें not exceeding five years का भी प्रावधान है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह मामला माननीय हाई कोर्ट में पैंडिंग है।

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में मामला पैंडिंग होने का क्या मतलब है ? हाई कोर्ट में तो कोई भी लिटिगेशन कर सकता है। मैं भी हाई कोर्ट में लिटिगेशन कर सकता हूं, परन्तु क्या सोसायटी के चुनाव नहीं करवाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसमें पब्लिक सर्वैंट द्वारा disobeying of law हुआ है। This is a disobeying of law. इसमें संबंधित कर्मचारी के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए and there is provision of imprisonment also. This is 161 of the IPC. इस तरह तो कोई कानून का पालन नहीं करेगा और कानून के बिना सरकार नहीं चलेगी। यह कानून है और कोई कानून का पालन नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट आई.पी.सी. की धारा 161 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाएं। इसमें संबंधित के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। वहां पर erring official कौन है and why the action has not been taken ?

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी जिस एक्ट की धारा की बात कर रहे हैं। मुझे उसकी कॉपी जरूर दे दें और वहां पर कोई भी erring offical है तो उसकी डिटेल भी दे दें। इसमें आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र□नों के लिखित उत्तर

Problem of Stray Cattles

***50. Shri Paredeep Chaudhary**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that stray Cattles are damaging the crops of farmers and also causing fatal accidents in the area of Kalka Constituency ; and

(b) if so, the steps taken by the Government to solve the problem of stray cattles together with the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : (a) & b) श्रीमान् जी, यह सत्य है कि कभी–कभी आवारा पशु फसलों को नुक्सान पंहुचाते है और दुर्घटना का कारण बनते है। आवारा पशुओ की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः–

(i) सरकार ने राज्य मे गौशालाओ , पशुफाटक और गौ अभ्यारण्य की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की है।

(ii) सभी उपायुक्तों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 21 (XXVI) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार गॉवों मे निर्मित गौ घर और पशुफाटक निर्माण करवाने के निर्देश दिये गये है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों मे गौशालाओ की स्थापना के लिए शामलात भूमि पटटे् पर देने के लिए पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 में प्रावधान किया गया है।

(iv) हरियाणा नगरपालिका स्वामित्व और आवारा पशु उप कानून, 1976 में किये गये प्रावधान अनुसार, नगरपालिका के अधिकृत अधिकारी, नगरपालिका की सीमा के भीतर भटके पाए गए मालिक रहित पशुओ को जब्त कर रहे हैं।

(v) रायपुर रानी ब्लॉक के गॉव रायपुर रानी और बरवाला ब्लॉक के गॉव रेहोड़ मे गौशालाओं/नंदीशालाओं का निर्माण किया गया है।

.....

Construction work of Yamuna Bridge

***235. Shri Jagdish Nayar:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of Hasanpur Yamuna bridge is likely to be started togetherwith the time by which it is likely to be completed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) :श्रीमान् जी, हसनपुर में यमुना नदी पर पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है। इस समय इसकी कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

To Construct Gaushala

***248. Shri Jogi Ram Sihag :** Will the Deputy Chief Minister, Haryana be pleased to state-

Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Gaushalas in the Gaucharad land available in the villages of the State; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized?"

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान् जी, गांवों में गऊचरांद की भूमि पर गऊषाला का निर्माण करने के लिए पहले से ही पॉलिसी दिनांक 4 फरवरी, 2019 को जारी की जा चुकी है।

.....

Shortage of Medicines

***157. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that there is acute shortage of medicines in Medical College at village Khanpur Kalan of Gohana Assembly Constituency; if so the time by which the shortage of medicines in said medical college is likely to be met out?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान् जी, मुख्यमन्त्री मुफ्त ईलाज योजना के तहत सभी रोगियों को मुफ्त में दवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस उद्देश्य के लिये वित्तिय वर्ष 2019–20 में भगत फूल सिंह राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत के लिये 11.00 करोड़ रूपये का संशोधित बजट का प्रावधान है। इसके अलावा, चिकित्सा महाविद्यालयों की मांग/आवश्यकता अनुसार दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से खरीदा जा रहा है। दवाओं की निरंतर आपूर्ति में एक विराम की अस्थायी स्थिति को कम करने के लिये निदेशक, चिकित्सा महाविद्यालय को ई–टेंण्डर के माध्यम से दवाओं एवं उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिये 5 लाख रूपये तक की क्षमता है। इसके अलावा, संस्थान में अमृत फार्मेसी और जन–औषधि केन्द्र खोलने से, कम कीमत पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता से दवाओं की उपलब्धता के कुल प्रतिशत में सुधार हुआ है।

Number of New Primary Schools

***72. Shri Varun Chaudhary :** Will the Education Minister be pleased to state the number of new Government Primary Schools opened in State together with the number of Government Primary Schools closed in State during the period from year 2013 to 2019?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, हरियाणा राज्य में वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान खोले गए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार से है–

वर्ष	नए खोले गए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
2013	---
2014	---
2015	---
2016	---
2017	03
2018	37
2019	---

कुल	**40**

छात्रो की संख्या कम होने के कारण इस अवधि के दौरान बन्द किए गए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**बन्द किए गए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या**
2013	---
2014	---
2015	---
2016	---
2017	---
2018	62
2019	62
कुल	**124**

To Setup Tomato Procession Unit

***216. Shri Naina Singh Chautala :** Will the Ariculture and Farmars welfars Minister be pleased to state the time by which a tomato processing unit is likely to be set up in Badhra Assembly Constituency?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : राज्य सरकार हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 के प्रावधान के अनुसार हरियाणा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। सरकारी बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए प्रचार और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध समूहों में टमाटर शामिल है।

.....

To Open a Medical College

***125. Shri Leela Ram :** Will the Medical Education Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that there is no Medical College in Kaithal district and other adjacent districts like Jind and Kurukshetra; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Medical College in Kaithal district togetherwith the time by which it is likely to be opened?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : क और ख श्री मान जी, यद्यपि कैथल जिले में कोई चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, तथापि सरकार गांव हैतबपुर जिला जींद में सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना कर रही है। इसके अलावा जिला कुरूक्षेत्र में 150 एम0बी0बी0एस0 छात्रों के साथ एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय आदेश चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कार्यरत है। वर्ष 2016 में मिरी– पीरी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एंड रिसर्च, शाहबाद, कुरूक्षेत्र की स्थापना के लिए एल0 ओ0 आई0 जारी किया गया था।

जिला कैथल में एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार के विचार में एक प्रस्ताव है, जिसके लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है।

.....

अतारांकित प्र□न उत्तर

To Lay Down Pipeline

1. Shri Mewa Singh : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down pipeline from newly installed tubewell upto the Bhallar Colony in Bhallar village of Ladwa Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the said pipeline is likely to be laid down ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :(क) हां, श्री मान जी ।

(ख) भलार गांव में नव स्थापित टयूबवैल से भलार कॉलोनी तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य एक अनुमान के अन्तर्गत प्रगति पर है जिसकी अनुमानित लागत 14.55 लाख रूपए है, तथा यह कार्य 31.03.2020 तक पूरा होने की संभावना है।

.....

Detail of Cases

10. Shri Bharat Bhushan Batra : will the Home Minister be pleased to state-

The year-wise and crime wise data in tabular form for cases of murder, dacoity, attempt of murder, abduction, rape, robbery, theft, dowry death, public violence, eve teasing and cruelty against women registered in State in the years 2017, 2018 and 2019 togetherwith the year-wise and crime wise percent change in rate of above mentioned crimes ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सारणीय तालिका में नीचे दर्शाई गई हैं–

शीर्ष	**2017**	**2018**	**अन्तर**	**% 2017 & 2018**	**2018**	**2019**	**अन्तर**	**% 2018 & 2019**
हत्या	1048	1101	53	5.06	1101	1129	28	2.54
डकैती	198	194	-4	-2.02	194	155	-39	-20.10
हत्या का प्रयत्न	956	986	30	3.14	986	900	-86	-8.72
अपहरण	4364	4720	356	8.16	4720	4026	-694	-14.70
बलात्कार	1248	1534	286	22.92	1534	1734	200	13.04
लूट	1247	1299	52	4.17	1299	1359	60	4.62
चोरी	23297	25675	2378	10.21	25675	24532	-1143	-4.45
दहेज हत्या	244	224	-20	-8.20	224	248	24	10.71
सार्वजनिक हिसां	4526	4919	393	8.68	4919	4393	-526	-10.69
छेड़खानी	1018	1194	176	17.29	1194	1079	-115	-9.63
महिला विरुध क्रुरता	3326	4151	825	24.80	4151	4868	717	17.27

.....

Details of Property Tax

3. Shri Jaiveer Singh : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the details of property tax of the villages falling under the Municipal CorporationSonipat?

गृह मन्त्री (श्री अनिल विज) : नगर निगम, सोनीपत के अन्तर्गतकुल 23 गांव आते हैं और 31.03.2020 तक इन गांवों की 18300 इकाइयों के विरूद्ध 9,73,18,209/– रूपये की राशि का सम्पत्ति कर बकाया है।

.....

Construction of Overbridge

4. **Shri Varun Chaudhry :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister for construction of over bridge on Markanda River in Mullana Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यन्त चौटाला) : हाँ, श्रीमान् जी। ग्राम सबगा से सौहाटा सड़क पर मारकण्डा नदी पर ऊपरी पुल का निर्माण कार्य जुलाई 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

.....

Qualification For HTET

11. Shri Ghanshyam Dass Arora : Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) Whether it is a fact that the qualification for applying HTET TGT ENGLISH and the recruitment of TGT ENGLISH (HSSC ADV. 09/2015, CAT.01) is BA with elective English togetherewith the fact that the candidate having compulsory English in B.A. is eligible for TGT ENGLISH recruitment as per memo no. KW8/1-2016 CO(1) dated 21/09/2016 from the office of DSE, Panchkula after the consultation taken by MDU, Rohtak with its opinion letter no. ACS.III/F7/2015/23794 dated 01/09/2016 that compulsory English is equivalent to elective English prior to 2011-2012 session; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to make fresh recruitment of TGT ENGLISH by conducting HTET TGT ENGLISH as per above said memo of DSE?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) जी, हाँ श्रीमान।

(ख) निदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा जारी किए गए यादि क्रमांक के०डब्लयू० 8/1–2016 सी०ओ० (1) दिनांक 21/09/2016 के अनुसार टी०जी०टी० अंग्रेजी की नई भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Total Amount Spent On Replacement of Wires

12. Dr. Krishan Lal Middha : Will the Power Minister be pleased to state the total amount spent on replacement of the wires, transformers and removal of the poles in the Jind district during the financial year 2018-19 and 2019-20 togetherwith the details of work done by the said amount thereof?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, जिला जींद में तारों, ट्रांसफार्मरों और खम्भों को बदलने पर वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 (जनवरी, 2020) के दौरान क्रमशः 1521.49 लाख रुपये और 948.76 लाख रुपये की कुल राशि खर्च की गई है।

.....

Enquiry in Auction of Land

5. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is fact that an enquiry was got conducted by the Housing Board in respect of auction of land adjoining Housing Board Colony of Kalka; if so, the details thereof;

(b) Whether any action has been taken by the Government on the enquiry report; if so, the details thereof?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : (ए एवं बी) नहीं, श्रीमानजी।

.....

Reconstruction of School Buildings

54. Smt. Naina Singh Cahutala: Will the Education Minister be pleased to state-

Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the buildings of Government Schools of village Nandhana, village

Mandi Haria of Badhra Assembly Constituency are in dilapidated condition; if so, the time by which the said school buildings are likely to be reconstructed?

शिक्षा मंत्री (श्री कवंर पाल) : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंदा का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, जबकि राजकीय माध्यमिक पाठशाला मंडी हरिया का भवन अच्छी अवस्था में हैं। राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय नंदा के भवन निर्माण के लिए 356.26 लाख रुपयें की व्यवस्था की गई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निविदांए तैयार की गई है, एवं निर्माण कार्य अप्रैल 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

.....

To Install Upgraded Sewerage System

23. **Shri Kuldeep Bishnoi :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that sewage is mixing in drinking water due to leakage in water supply and sewerage pipe lines of Adampur Mandi; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to install new upgraded sewerage system in Adampur Mandi togetherwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमान जी ।

.....

To Open Polytechnic College

53. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Technical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open any Polytechnic College in Badhra Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Provide the Super Sucker Jetting Machine

32. Shri Amit Sihag : Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) whether it is a fact that the sewerage system of Dabwali is in bad condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Super Sucker Jetting Machines to desilt the sewerage in Dabwali City togetherwith the time by which these machines are likely to be provided ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) व ख) नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Problem of Saline Water

21. Shri Kuldeep Vats : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that there is a problem of saline water in many villages of Badli Assembly Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new canals/diggies to solve the abovesaid problem?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हाँ, श्रीमान जी ।

(ख) नहीं, श्रीमान जी । हालांकि, कुछ अन्य समाधान विचाराधीन हैं ।

.....

Construction of School

33. Shri Amit Sihag : Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Hon'ble Chief Minister of Haryana Government had made an announcement for constructing a school in the memory of 5 years old girl Mahak in Kabir Basti ward no. 5 during a rally in Dabwali in the year 2017; and

(b) if so, the time by which the construction work of said school is likely to be started?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) हां श्रीमान जी

(ख) स्कूल के भवन निर्माण के लिए 90.27 लाख रूपये की राशि का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसकी दिनांक 20.04.2020 तक शुरू होने की संभावना है।

.....

The Construction Work of CHC

51. Smt. Naina Singh Cahutala : Will the Health Minister be pleased to state the time by which the construction work of under construction Community Health Centre in village Gopi of Badhra Assembly Constituency is likely to be completed togetherwith the details thereof ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपी का रिहायशी भवनो सहित निर्माण कार्य 31.03.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपी की रिहायशी भवनों सहित 671.76 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति, सरकार के पत्र क्रमांक 20/47/2019-5HB -111 दिनांक 05.07.2019 के तहत जारी की गई।
- उसके अनुसार 639.05 लाख रूपये के कार्य का टैडंर लोक निर्माण विभाग (भवन व सडक शाखा) द्वारा आवंटित किया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपी का रिहायशी भवनो सहित निर्माण कार्य 31. 03.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

.....

To Fill Up the Posts of Specialist Doctors

34. Shri Amit Sihag : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the posts of specialist doctors and other staff are lying vacant in the 100 bed hospital in Dabwali; and

(b) if so, the time by which the above said posts are likely to be filledup?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) चिकित्सकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त भर लिया जाएगा जो कि विभाग द्वारा पहले ही शुरु की जा चुकी है और पैरा–चिकित्सक अमले की भर्ती के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है।

.....

To increase the Availability of Canal Water

43. Shri Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the availability of canal water in Ateli Constituency keeping in view of the decreasing water level in Southern Haryana?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी ।

.....

To Set up Grain Market

52. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any permanent Grain Market in village Berla and Kadma of Badhra Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be set-up ?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : जी नहीं, श्रीमान्; प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता ।

.....

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण मुझे सदन को सूचित करना है कि आज श्री श्रीकृष्ण हुड्डा जी, विधायक से एक सूचना प्राप्त हुई है कि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे बजट सैशन के दौरान दिनांक 24.2.2020 से 4.3.2020 तक सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आपको सूचित करना है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण चर्चा समय सारणी अनुसार तीन दिन अर्थात 24 फरवरी, 2020, 25 फरवरी, 2020 और 26 फरवरी, 2020 तक चलेगी जिसके लिए लगभग 7 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और आवश्यकतानुसार सभी पार्टियों का अनुपातिक समय भी निकाल लिया गया है, जिसकी प्रति मैं सदन में सभी दलों के नेताओं के पास पहुंचा रहा हूं कि किस सदस्य को कितना समय

प्रदान करना है तथा सभी दलों के नेता मुझे इस बारे में सदस्य के नाम सहित लिखित रूप में सूचित भी कर दें।

ध्यानाकर्शण प्रस्तावों की सूचनाएं/स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्शण प्रस्ताव में परिवर्तित करना

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको सरकार द्वारा 75 प्रतिशत आरक्षण हरियाणा के बेरोजगार युवकों को देने बारे, आबकारी नीति में रह गई कमियों के बारे, राज्य में बढ़ते हुए नशे के इस्तेमाल बारे, ओवरलोडिंग द्वारा पनप रहे भ्रष्टाचार बारे, आवारा पशुओं के उचित प्रावधान बारे, ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने से बचाने बारे, धान खरीद में हुए भ्रष्टाचार के संबंध बारे और अरावली क्षेत्र में अवैध गतिविधियों जैसे कि माईनिंग, अवैध निर्माण आदि गतिविधियों को रोकने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, इनका क्या फेट है क्योंकि इन सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों में प्रदेश से जुड़े हुए बहुत ही अहम मुद्दे हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, वे आज ही मुझे प्राप्त हुए हैं और उन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर आपने कोई सिग्नेचर भी नहीं किए हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सिग्नेचर किए हैं, उन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की एक–एक प्रति मेरे पास भी है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जो बात मेरे संज्ञान में आई है, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मुझे लगता है कि आपने ईमेल के जरिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने ईमेल के जरिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे हैं तब भी मैंने सिग्नेचर जरूर किए हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज ही प्राप्त हुए हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं इसलिए जल्दी से जल्दी विचार विमर्श करके इनको एडमिट कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को अभी तक मैंने देखा नहीं है क्योंकि आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज ही ऑफिस में आये हैं इसलिए इनको देखने के बाद ही विचार किया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको प्रदेश में हो रहे अवैध खनन बारे, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में घोटाले बारे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने (सामाजिक सुरक्षा पेंशन) बारे, भारी वर्षा और मूसलाधार वर्षा से हुए फसलों के नुकसान बारे, प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं और धान की खरीद में घोटाले के बारे में, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं किसानों को गन्ने की पैमेंट न दिए जाने बारे व प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे बारे ऐडजर्नमैंट मोशन दिया था, उनका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : गीता जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक आपका और आपकी पार्टी के सदस्यों की तरफ से जो नशे से संबंधित एडजर्नमैंट मोशन नम्बर–1 आया था उसको मैंने कॉलिंग अटैंशन मोशन नम्बर–21 में परिवर्तित कर दिया है और यह कॉलिंग अटैंशन मोशन दिनांक 27 फरवरी, 2020 को चर्चा के लिए ऐडमिट कर लिया है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, इस कॉलिंग अटैंशन मोशन का क्या विषय है।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे बारे में जो एडजर्नमैंट मोशन दिया था, जिसको मैंने कॉलिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया है और इसे मैंने दिनांक 27.02.2020 को चर्चा के लिए स्वीकृत भी कर लिया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैंशन मोशन पर तो सेम डे चर्चा करवाई जा सकती है यानि कालिंग अटैंशन मोशन जिस दिन दिया जाये उसी दिन भी उस पर चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैंने 5 कालिंग अटैशन मोशंज स्वीकृत किये हैं। गन्ने के न्यूनतम मूल्य बारे व प्रदेश के युवाओं में नशाखोरी बढ़ने बारे ये दोनों कालिंग अटैंशन मोशंज 27.02.2020 को चर्चा के लिए लगाये गये हैं। इसी प्रकार से भारी और मूसलाधार वर्षा से फसलों को हुए नुक्सान बारे जो कालिंग अटैंशन मोशन है उसको दिनांक

03.03.2020 को चर्चा के लिए स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से ये तीन कालिंग अटैशन मोशंज 27.02.2020 और 03.03.2020 के लिए चर्चा हेतु स्वीकार किये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिन कालिंग अटैंशन मोशंज को अस्वीकार किया गया है हमें उनके अस्वीकार होने का कारण भी बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जहां तक धान घोटाले से सम्बंधित कालिंग अटैंशन मोशन का सम्बन्ध है उस पर सरकार के कमैंट्स मांगे गये हैं। जब सरकार से कमैंट्स प्राप्त हो जायेंगे तो उसके बारे में सदन में जानकारी दे दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, अगर आप माननीय सदस्यों के किसी भी कालिंग अटैंशन मोशन को रिजैक्ट करते हैं तो आपको उसकी रिजैक्शन का कारण भी बताना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, जो कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार किये गये हैं मैंने उनकी जानकारी भी दे दी है। बाकी के कालिंग अटैंशन मोशंज को सरकार के पास कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है जैसे ही सरकार के कमैंट्स प्राप्त होंगे उनके बारे में भी सदन में सूचना दे दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी तो सत्र के समापन में काफी समय शेष है इसलिए कालिंग अटैंशन मोशन तो हम कभी भी लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन कभी भी दे सकती हैं। इससे आपको किसी ने मना नहीं किया है। आप अपने कालिंग अटैंशन मोशन दें आपका स्वागत है।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, अभी जो आपने कालिंग अटैंशन मोशन की सारी की सारी बात की है। आज इस सत्र में डिसकशन का पहला दिन है। आपके पास कालिंग अटैंशन मोशंज आ गये it is your discretion कि आप कौन सा रिजैक्ट करेंगे और कौन सा एडमिट करेंगे लेकिन जो आप आज ही 03. 03.2020 को डिसकशन के लिए निर्धारित किये गये कालिंग अटैंशन मोशन की जानकारी दे रहे हैं यह ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से कालिंग अटैंशन मोशन उससे पहले भी आ सकते हैं how can you listed them? मेरा यही कहना है कि जो कालिंग अटैंशन मोशन आपके पास पहले आयें उनको आप पहले लगायें और जो

बाद में आयें उनको बाद में लगायें। (विघ्न) It should be according the procedure of the House.

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, हमारे पास जो कालिंग अटैंशन मोशंज पहले आये हैं हम उन्हीं पर पहले चर्चा करवा रहे हैं और जो बाद में आयेंगे उन पर हम बाद में चर्चा करवायेंगे। इसके अलावा मेरा आप सभी से यह भी कहना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए हमने तीन दिन का समय फिक्स किया है। यह बी.ए.सी. की मीटिंग में तय किया गया था। अगर इस बीच में कोई कालिंग अटैंशन मोशन आयेगा तो उस समय उसके बारे में विचार कर लिया जायेगा। मेरा आप सभी से यह भी कहना है कि आज सभी माननीय सदस्यों को जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया जायेगा उस समय आप किसी भी ज्वलंत मुद्दे को उठा सकते हैं। (विघ्न) जो माननीय सदस्यगण को समय मिलेगा उसमें वे उस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं जिसके बारे में वे अपना कालिंग अटैंशन मोशन देना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसी कोई परम्परा नहीं है। मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय मिलेगा तो उस दौरान मैं कालिंग अटैंशन मोशन पर कैसे बोल सकता हूं। होता तो यही है कि किसी भी कालिंग अटैंशन मोशन पर गवर्नमैंट की तरफ से रिप्लाई भी आता है और सभी माननीय सदस्यों द्वारा सरकार के रिप्लाई को पढ़ा भी जाता है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, मैंने यही कहा है कि आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। (विघ्न) बतरा जी, मेरा यही कहना है कि आपका जो कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार नहीं होता तो आप उस पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने विचार रख सकते हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मेरा आपको यही कहना है कि आप इस सम्बन्ध में जो निर्धारित कंवैंशज हैं उनको फोलो करें और कंवैंशंज यही हैं कि आज आपने 03.03.2020 को किसी कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा के लिए फिक्स कर दिया। फिर जो कालिंग अटैंशन मोशंज कल आयेंगे उन पर आप कब चर्चा करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आपको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय मिलेगा जो भी विषय आप यहां पर उठाना चाहते हैं उनको आप उस समय रखें इससे आपको कौन रोक सकता है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। ध्यानाकर्षण सूचना अगर मंजूर होती है तो उसका जवाब सरकार को देना होता है। आपने तो कह दिया कि आपकी बाकी ध्यानाकर्षण सूचनाएं नामंजूर कर दी गई हैं।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जो जरूरी लगी वे हमने स्वीकार की हैं। जो विषय सालों साल से चले आ रहे हैं जिनका जवाब भी सरकार की तरफ से समय–समय पर दिया जाता रहा है उनको स्वीकार नहीं किया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण सूचना नामंजूर की गई हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया जाये कि वे किस आधार पर नामंजूर की गई हैं?

श्री अध्यक्षः किरण जी, हमने नामंजूर की सूचना के बारे में आपको लिखित में जवाब भिजवा दिया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने एक लाईन का जवाब भिजवा दिया है कि आपकी ध्यानाकर्षण सूचना नामंजूर की जाती है। आपने यह नहीं बताया कि उसको किस कारण नामंजूर किया गया है?

श्री अध्यक्षः किरण जी, कारण बताना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से विषय हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं और वे कालिंग अटैन्शन नोटिस के लिए उपयोगी नहीं हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अरावली वन क्षेत्र के घटने के बारे में एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी उसका फेट बताया जाए?

श्री अध्यक्षः किरण जी, जब भी आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें तो इस मुद्दे पर भी आप अपनी बात रख सकती हैं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्या हैं। आप जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें उस समय आप यह प्रश्न उठा सकती हैं तथा जब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो वह सरकार की तरफ से ही जवाब होगा और आपके प्रश्न का जवाब भी आ जायेगा।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, it is written in the Rule 73(2)(ii) that-

> "Notices for a sitting received one hour before the commencement of the sitting shall be deemed to have been received for that day. Notices received within one hour before the commencement of the sitting shall be deemed to have been given for the next sitting".

यहां तक तो रूल्ज में प्रावधान है। आप बतायें कि कौन से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने रिजैक्ट किये गये हैं? I know, Powers are with the Hon'ble Speaker but reasons have to be mentioned while declining/rejecting notices.

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, मैं तो पिछली परम्पराओं को ही फौलो कर रहा हूं।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह तो बता ही नहीं रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से जो 15 कालिंग अटैंशन मोशंज दिये गये थे उनमें से आपने केवल 5 कालिंग अटैंशन मोशंज ही एक्सैप्ट किये हैं जिनमें श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक के दो, मेरा एक और एक श्री चिरंजीव राव, विधायक का और एक इनैलो पार्टी के श्री अभय सिंह चौटाला का बाकी कालिंग अटैंशन मोशंज के बारे में किसी मैंबर को जानकारी ही नहीं है कि उनका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, बता तो दिया है कि हमने 5 कालिंग अटैंशन मोशंज को एक्सैप्ट कर लिये हैं और बाकी कालिंग अटैंशन मोशंज रिजैक्ट हो गये हैं।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हुआ कि आपने 15 में से केवल 5 कालिंग अटैंशन मोशंज ही एक्सैप्ट किये हैं।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, ये तो आपकी सरकार के समय की ही बनाई हुई परम्पराएं हैं क्या वे अच्छी नहीं थी?

.....

गैर–सरकारी दिवस से संबंधित मामला उठाना

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, वीरवार को नॉन ऑफिशियल डे फिक्स किया जाता है। पिछले 5 सालों में ऐसा होता आया है कि एक भी वीरवार को नॉन ऑफिशियल डे नहीं हो पाया। बी.ए.सी. की मीटिंग में उसको ऑफिशियल डे में

कनवर्ट कर लिया जाता था। इस बार वीरवार को नॉन ऑफिशियल डे रखा गया है और हमने इस बार इस बारे में नोटिस भी दिया है। इस बारे में मेरा एक निवेदन है कि एक दिन का एक्सपीरियेंस हो जायेगा और इस वीरवार को नॉन ऑफिशियल डे को एक्सैप्ट करके विधायकों को बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपने जो नोटिस दिया है वह आज ही दिया है और इस पर विचार कर लिया जायेगा।

.....

विभिन्न मामले/मांगें उठाना

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखनी है, इसलिए मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक हजार के करीब प्राईवेट स्कूल्ज ऐसे हैं जिनमें कुछ टीचर्ज ने पिछली बार ड्यूटी नहीं दी थी, इसलिए बोर्ड इस बार उन स्कूल्ज के बच्चों के रोल नम्बर्ज इशू नहीं कर रहा है। इस कारण लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हैं। बोर्ड के एग्जाम की डेट अनाउंस होने वाली है और अभी तक संबंधित स्कूल्ज के बच्चों के रोल नम्बर्ज इशू नहीं किये गये हैं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। दूसरी बात यह है कि जिन टीचर्ज की ड्यूटी एग्जाम में लगी थी उनका कहना है कि पिछली बार ज्यादातर टीचर्ज ऑन ड्यूटी पर थे, परन्तु उनको मानदेय नहीं दिया गया और न ही उनको सुविधाएं दी गयी। मान लीजिए, इस वजह से उन टीचर्ज ने ड्यूटी नहीं भी की तो उन स्कूल्ज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की इसमें किसी प्रकार की कोई गलती या दोष नहीं है। इसको माननीय मंत्री जी गम्भीरता से लें। इसके कारण federation of private schools association और दूसरे लोगों में यह डिस्पयूट काफी समय से चल रहा है। आप कृपा इसमें इन्टरविन करके अतिशीघ्र संबंधित स्कूल्ज के बच्चों को रोल नम्बर्ज दिलवाएं। इसमें ये बातें भी निकलकर आयी हैं कि बच्चों के रोल नम्बर्ज इशू करने के लिए संबंधित स्कूल्ज से पैसों की डिमांड की जा रही हैं। यह गम्भीर मुद्दा है और इसको गम्भीरता से लिया जाए।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या की बात का जवाब दे रहा हूं और इनको भी इस बात से खुशी होगी कि उन स्कूल्ज के बच्चों के रोल नम्बर्ज नहीं रोके जाएंगे। जिन प्राईवेट स्कूल्ज के टीचर्ज ने पिछले साल पेपर्ज में ड्यूटी नहीं दी थी, उन पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 5,000 रुपये

का जुर्माना लगाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किसी भी बच्चे का रोल नम्बर नहीं रोका जाएगा। यह केवल दबाव बनाने के लिए किया गया था।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई ?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि बोर्ड द्वारा किसी बच्चे का रोल नम्बर नहीं रोका जाएगा। मैं यह बात हाऊस में कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी दबाव बनाने की बात कैसे कह रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, यह शब्द गलत हो सकता है। मैंने यह कहा है कि असल में प्राईवेट स्कूल्ज के टीचर्ज की भी जरूरत पड़ती है। केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही सारी व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, इसलिए उनसे कहा गया था कि आप भी एग्जाम में ड्यूटी करें। जिन टीचर्ज ने पेपर्ज में ड्यूटी नहीं दी थी, उनके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। मैं अपना शब्द वापिस लेता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, इनको अपना शब्द वापिस लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना शब्द वापिस ले लिया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, एक तो हम कहते हैं कि परीक्षा के दौरान बच्चे स्ट्रैस फ्री होकर एग्जाम दें ताकि बच्चे अच्छी तरह से एग्जाम दे पाएं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे शीघ्रता से कोई डेट फिक्स करके उन स्कूल्ज के बच्चों के रोल नम्बर्ज जारी करवा दें। इसके अतिरिक्त मंत्री जी से अनुरोध है कि ज्यादातर स्कूल्ज के बच्चों के एग्जाम सैंटर बहुत दूर–दूर बनाये गये हैं, इसलिए उनके परीक्षा केन्द्रों का डिस्टैंस कम किया जाए क्योंकि परीक्षा केन्द्र दूर होने के कारण तथा साधन की कमी के कारण भी काफी तकलीफों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन विद्यार्थियों को रोल नम्बर आदि नहीं दिए गए हैं उनको शीघ्रअतिशीघ्र रोल नम्बर दिए जायें और इसके साथ प्राइवेट स्कूलों के उन शिक्षकों को अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है इसलिए उनको मानदेय भी

दे दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि निजी स्कूलों के बच्चों के परीक्षा केन्द्र दूर बनाये गये हैं, उनको नजदीक बनाने का काम करें ताकि हमारे बच्चे स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम दे सकें तथा परीक्षा लेने के लिए जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है वे भी स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम ले सके।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल 1800 प्राइवेट स्कूल हैं। बोर्ड ने इन सभी प्राइवेट स्कूलों से च्वॉयस मांगी थी। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमने 960 प्राइवेट स्कूलों को पहली च्वॉयस पर, 521 प्राइवेट स्कूलों को दूसरी च्वॉयस पर, 189 प्राइवेट स्कूलों को तीसरी च्वॉयस पर, 75 प्राइवेट स्कूलों को चौथी च्वॉयस पर, 31 स्कूलों को पांचवीं च्वॉयस पर एग्जाम सैंटर अलॉट किए हैं और 89 प्राइवेट स्कूल ऐसे है जिनको एनीव्हेयर की श्रेणी में डाला गया था, जिन्होंने परीक्षा केन्द्र के लिए केवल एक ही विकल्प भरा था, दूसरा कोई विकल्प हीं नहीं दिया था।

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माइनिंग मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि माइनिंग यमुना के साथ लिंक नहीं रही है क्योंकि गांव–गांव में जगह–जगह माइनिंग के अड्डे बन चुके हैं। मेरे पास प्रदेश में हो रही अवैध माइनिंग की कुछ फोटोज हैं और इसकी हमने निसिंग थाने में भी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड तथा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की जो सड़कें बनाई जाती हैं, उन सड़कों को बनाने के लिए ठेकेदार सड़क के साथ लगती किसी किसानों की जमीन मिट्टी खोदने के लिए ठेके पर ले लेते हैं और फिर किसान की उस जमीन को 60–60 फुट गहरा खोदकर वहां से निकाली गई मिट्टी को सड़क के निर्माण कार्य में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ठेकेदार दूर से मिट्टी लाने के प्रयोजन को दिखाकर ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज के नाम पर सरकार को चूना लगाने का काम करते हैं वहीं दूसरी और वह किसान जिसके खेत को 60–60 फुट गहरा खोद दिया जाता है, उसको भी हैरासमैंट करने का काम इन ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार दो महीने तक प्रदेश में हो रही अवैध माईनिंग की व्हाट्सप्प के जरिये डायरेक्ट माइनिंग को मैसेज भी भेजता रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि माइनिंग के लिए सरकार ने एस.आई.टी. की टीम गठित कर रखी है इस काम को एस.आई.टी. की टीम ही देखती है परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह

भी बताना चाहूंगा कि आखिर में पानीपत माइनिंग ऑफिसर पर दवाब दिया गया तब जाकर दिनांक 28.01.2020 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी परन्तु आज तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पास एफ.आई.आर. की कॉपी और अवैध माइनिंग की फोटोज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि सरकार किसानों के बारे में भी विचार जरूर करे क्योंकि जिस किसान के पास एक एकड़ तक की जमीन है, वह बेचारा मारा जाता है और जो बड़े–बड़े मगरमच्छ होते हैं वे आसानी से बच निकलते हैं।

श्री धर्मपाल गोंदरः अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीलोखेड़ी और तरावड़ी नगरपालिका में चुनाव से एक साल पहले 40–50 गज के लगभग अढ़ाई सौ मकान थे उनको यह कह कर तुड़वा दिया गया कि उनको लैंटर वाले पक्के मकान बना कर दिये जायेंगे लेकिन अभी तक वे मकान नहीं बनाए गए हैं। वे लोग आज भी तिरपालों के नीचे और फ्लाईओवर्स के नीचे रहने को मजबूर हैं और जब भी हम अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो हमें उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी इन्कवायरी करवाई जाये कि ये मकान किसने किराए तथा अभी तक क्यों नहीं बन रहे हैं? इसके अतिरिक्त मैं एक विषय और उठना चाहता हूं। हरियाणा में वी.एल.डी.ए. का कोर्स हरियाणा के हिसार में करवाया जाता है वह दो साल का है और एन.डी.आर.आई. करनाल में वही कोर्स 3 साल का करवाया जाता है। अभी बहुत से बच्चों ने वी.एल.डी.ए. की भर्ती के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया और उनकी लिखित परीक्षा भी हुई लेकिन जब नियुक्ति देने का समय आया तो उनको यह कह कर मना कर दिया गया कि एन.डी.आर.आई. के वी.एल.डी.ए. के कोर्स को हरियाणा में मान्यता प्राप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के 194 बच्चे हैं जिनकी जिन्दगी अधर में है इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाये।

श्री राम करण : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विनती है कि माईनिंग में जो एक गाड़ी में 55 टन वजन तक निर्धारित है उससे पंचायतों को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि इससे मैटीरियल बहुत महंगा हो गया है। जिससे जिन ठेकेदारों ने पंचायती कामों के ठेके ले रखे हैं वे मैटीरियल महंगा होने की वजह से सारे बन्द हो गये हैं । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक गाड़ी में जो 55 टन वजन भरना निर्धारित किया हुआ है उसको बढ़ाकर 60 टन किया जाए। अगर कोई 60 टन से ज्यादा वजन

अपनी गाड़ी में भर कर लाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसकी गवर्नमैंट से निर्धारित रशीद काटी जाए। आज कई जगह माईनिंग बन्द हैं जिससे मैटीरियल बहुत महंगा हो रहा है। मैटीरियल महंगा होने की वजह से पंचायतों के काम के जो ठेके हो रहे थे वह काम भी बन्द पड़े हैं क्योंकि उनके ठेकेदारों ने मैटीरियल महंगा होने की वजह से पंचायती कामों के ठेके छोड़ दिये हैं जिससे पंचायतों को भी घाटा हुआ है और सरकार को भी घाटा हुआ हैं आज जमीनदार व मजदूर को भी मैटीरियल महंगा मिल रहा है इसलिए गाड़ियों में जो 55 टन वजन भरना निर्धारित किया हुआ है उसको बढ़ाकर 60 टन कर दिया जाए और जो गाड़ी ऑवर लोडिड पाई जाती है तो उस गाड़ी को बन्द करने की बजाए उस पर जुर्माना किया जाए क्योंकि अगर उसकी गाड़ी की कीमत 15 लाख है तो उसको छुड़वाने के लिए 7 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। सर, इससे तो ट्रांसपोर्ट मारा गया। जिस जमीनदार का ट्रैक्टर ट्राली 5 लाख रुपये का है और उसको छुड़वाने के लिए उसको ढाई लाख रुपये भरने पड़ते हैं तो वह जमीनदार अपना ट्रैक्टर–ट्राली छुड़वाने में असमर्थ हो जाता है जिसकी वजह से आज बहुत से जमीनदार व मजदूरों की ट्रैक्टर–ट्राली थाने में खड़ी हैं। इससे सरकार और पब्लिक दोनों का ही नुकसान है इसलिए जो भी गाड़ी 60 टन वजन से ऊपर पाई जाती है उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसकी गवर्नमैंट की रशीद काटी जाए। इससे पंचायतों व एक मजदूर को सस्ता मैटीरियल मिलेगा और गवर्नमैंट के ठेके भी महंगे जाएंगे। इसी के साथ मेरा निवेदन है कि जो गाड़ियां थाने में बन्द पड़ी हैं उनको भी छुड़वाने की कोशिश करें क्योंकि जिसकी 15–20 लाख रुपये की गाड़ी बन्द हो गई है और उसको अपनी गाड़ी 10 लाख रुपये भर कर छुड़वानी पड़ेगी तो वह उस गाड़ी को कैसे छुड़वाएगा। वह तो सारी उमर उस काम से ही वंचित हो जाएगा। जिस जमीनदार को ट्रैक्टर के 5 लाख रुपये भरने पड़ गये तो वह तो गया काम से फिर वह आगे वह काम कैसे करेगा। अतः इस बात पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इससे प्रदेश की जनता नाराज है। इससे पंचायतों के काम भी पैंडिंग पड़े हैं जिससे सरकार को भी लोस हो रहा है इसलिए इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। धन्यवाद।

श्री रणधीर सिंह गोलनः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरी विधान सभा एक ग्रामीण क्षेत्र है। मेरी विधान सभा के पाई, भाणा, करोडा, रमाणा, हजवाना आदि गांवों का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्दर

कन्या महाविद्यालय की सख्त जरूरत है। शिक्षा की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले पांच वर्षों के अन्दर भी अनेक कन्या महाविद्यालयों का निर्माण करवाया है। मेरा उसी कड़ी में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पाई गांव के अन्दर जहां पंचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है वहां एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया जाए। दूसरी मेरे क्षेत्र की एक बहुत पुरानी मांग है कि वहां पर तहसील तो बहुत पुराने समय से है लेकिन अब तक सरकार ने उसके लिए कोई जमीन एकवायर नहीं की है जिसकी वजह से अब तक उस तहसील का अपना भवन नहीं बना है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर पशु पालन विभाग की 4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है जो वर्ष 1991 में जोहटा फार्म के नाम से एक्वायर हुई थी । अगर वह 4 एकड़ जमीन रेवैन्यु डिपार्टमैंट के नाम ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर हमारी तहसील का भवन भी बन जाएगी और तहसील ग्राउंड भी बन जाएगा। इसी के साथ मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और है कि पुण्डरी को अगर सब–डिविजन का दर्जा दे दिया जाए तो वह भी सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य होगा क्योंकि गुहला, कलायत व कैथल के अन्दर भी सब–डिविजन है। लेकिन मेरा विधान क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सब डिवीजन नहीं है। वैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र का भाग्य भी कुछ ऐसा है कि यहां पर लगातार छठी बार आजाद उम्मीदवार जीतकर आया है जिसकी वजह से इस क्षेत्र की आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं होता है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात जरूर सुनेंगे क्योंकि मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत पुराना नाता रहा है इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे मेरी बातों पर गौर करके उन्हें अवश्य पूरे करने का काम करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदार दिल के हैं और उनके दिल में मेरे प्रति जो प्यार है वह भी आज का नहीं है बल्कि यह प्यार लगभग 27–28 सालों पुराना प्यार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री नीरज भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि कोई भी कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि लॉ एंड आर्डर की स्थिति अच्छी तरह से कायम रह सके। हमारे भारत देश का संविधान इस पद्धति पर आधारित है कि 100 गुनहगार छूट जायें परन्तु एक बेगुनाह को सजा न हो क्योंकि एक भी बेगुनाह को सजा हो गई तो हमारे पास ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है कि हम उस बेगुनाह को

बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, अभी माइनिंग के विषय पर सदन में चर्चा चल रही थी। हरियाणा प्रदेश में एन.जी.टी. का एक कानून बनकर आया है कि इल्लीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के अंदर और आस–पास के एरिया में माइनिंग एक तरह से लोगों का रोजी–रोजगार का साधन है। यहां पर माइनिंग के कार्य के लिए डंपर चलते हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इल्लीगल माइनिंग की आड़ में माइनिंग से जुड़े लोगों के रोजी–रोजगार पर तलवार न चलाई जाये। अध्यक्ष महोदय, माइनिंग के कार्य में सबसे बड़ा मसला ओवरलोडिंग का होता है। राजस्थान प्रदेश में माइनिंग लीगल है और हमारे क्षेत्र के लोग लीगली राजस्थान से पत्थर खरीदकर लाते है लेकिन जैसे ही हरियाणा की सीमा में एंट्री होती है तो हरियाणा में कायम एन.जी.टी. कानून का सहारा लेकर इल्लीगल माइनिंग के नाम पर इन लोगों के चालान काट दिए जाते है जोकि बहुत गलत बात है। मैं अभी पीछे अपने साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करने के लिए मिला था। माननीय माइनिंग मिनिस्टर जी भी हमारे शहर से है। मैंने कहा कि आप कोई ऐसी जगह बना दें कि जहां यह पता लगाया जा सके कि कोई पत्थर कहां से आ रहा है। अगर कोई ट्रक ट्रैफिक मानदडों के हिसाब से ठीक नहीं है, किसी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है या कोई ट्रक ओवरलोडिड है तो उसके विरूद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाये लेकिन मात्र एन.जी.टी. कानून का सहारा लेकर राजस्थान से लीगली तौर पर लाये जा रहे पत्थर से भरे ट्रकों का हरियाणा की सीमा में घुसने पर इल्लीगल माइनिंग के आधार पर चालान काटना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदमी ओवरलोडिंग या तो मजबूरीवश करता है या फिर कम्पीटीशन के कारण करता है कि जैसे मान लो कोई ट्रक वाला अपने ट्रक में दो टन फालतू कोई चीज ले आता है तो दूसरा सोचने लग जाता है कि वह भी इससे ज्यादा सामान ट्रक में लादकर लायेगा। यह ओवरलोडिंग की मेन वजह होती है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पत्थर सस्ता होता है और उसकी क्वॉलिटी हरियाणा के पत्थर की क्वॉलिटी से अलग होती है। राजस्थान में हर जगह धर्म कांटे की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ओवरलोडिंग की समस्या आ जाती है लेकिन यह बात भी बिल्कुल नहीं भूली जानी चाहिए कि जो पत्थर राजस्थान से खरीदा गया होता है उसका कंप्यूटराइज्ड बिल इन लोगों के पास होता है और इस प्रकार भूल–चूक

में ये लोग ओवरलोडिंग का शिकार हो जाते हैं और हरियाणा की सीमा में आने पर एन.जी.टी. कानून का सहारा लेकर इल्लीगल माइनिंग के नाम पर इनका चालान काट दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ओवरलोडिंग करनी चाहिए लेकिन राजस्थान प्रदेश में लीगली खरीदे गए पत्थर को हरियाणा प्रदेश की सीमा में एन.जी.टी. द्वारा कानून का सहारा लेकर इल्लीगल माइनिंग के नाम पर चालान काट देना किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी का इल्लीगल माइनिंग का चालान कट जाता है उसके घर में दो–तीन दिन टाइम पर रोटी भी नहीं बनती है और ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि जैसे उस घर में कोई मौत हो गई हो। अध्यक्ष महोदय, अगर कल यह सिद्ध हो जाता है कि जिन ट्रकों का एन.जी.टी. कानून का सहारा लेकर इल्लीगल माइनिंग के नाम पर चालान काटा गया है, उन ट्रकों में भरा जो पत्थर है वह लीगली तौर पर राजस्थान प्रदेश से खरीदा गया है अर्थात वह पत्थर हरियाणा का नहीं बल्कि राजस्थान से खरीदकर लाया गया पत्थर है तो क्या ऐसी परिस्थिति में जितने दिन ट्रक खड़े रहे, क्या उतने दिन का ब्याज सरकार अपनी तरफ से भरने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, माइनिंग से जुड़े मेरे क्षेत्र के लोग अपना घर बेचकर ट्रकों की किश्तें भर रहे हैं लेकिन एन.जी.टी. के नाम पर जो यह अवैध माइनिंग का कानून बना है इसकी आड़ में जनता की रोजी–रोटी पर तलवार नहीं चलाई जानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस कानून की पालना होनी चाहिए। माननीय माइनिंग मिनिस्टर जी मेरे शहर से हैं मैं उनसे भी इस संदर्भ में खासतौर से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं एन.जी.टी. का इल्लीगल माइनिंग का यह कानून, काला कानून न बन जाये। धन्यवाद।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कुछ गुजारिश करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात क्षेत्र के नूंह जिले में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यदि पिछले पांच सालों के आंकड़े देखें तो पायेंगे कि 248 राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब तक तकरीबन 3200 एक्सिडेंट्स हुए हैं जिनमें तकरीबन 1300 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 248 रोड्ज को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देकर इन्हें फोर लेन बनाने की बात कही गई थी। उसी परिपेक्ष्य में मेरी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि नूंह से मुंडाका राजस्थान बार्डर तक की 51 किलोमीटर लंबी सड़क को फोर लेन बनाया जाये ताकि लोगों की जानें बचाई जा

सकें क्योंकि यहां पर जितनी भी रोड दुर्घटनायें हुई हैं वें केवल सिंगल रूट की वजह से ही हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले गुरूग्राम के राजीव चौक से लेकर राजस्थान बार्डर तक के रोड को फोर लेन बनाने का सरकार का इरादा था परन्तु राजीव चौक, गुरूग्राम से लेकर सोहना तक के रोड को छह लाइन का बनाया गया जोकि एक बहुत अच्छी बात है। यही नहीं सोहना से लेकर नूंह तक के रोड को भी फोर लेन बनाया गया। यह भी एक बहुत अच्छी बात सरकार के द्वारा की गई है। अध्यक्ष महोदय, जो रोड गुरूग्राम से सोहना जाता है और सोहना से अलवर जाता है, यह वही रूट है जो नूंह से राजस्थान बार्डर तक जाता है जिस पर डेली आने–जाने का तकरीबन 30–35 हजार ट्रैफिक का फलो बनता है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस इस रोड को भी फोर लेन बनाया जाना चाहिए। शुक्रिया।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने एन.जी.टी. के तहत कार्रवाई, ओवर लोडिंग और अवैध खनन के बारे में सदन में चर्चा की है। कोई भी व्हीकल अवैध खनन करते पाया जायेगा तो उसका शॉ–रूम प्राइज़ का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा। मैं समझता हूँ कि यह हर किसी के लिए देना संभव नहीं है। एक किसान व्यक्तिगत रूप से किसी काम के लिए आता है और वह एन.जी.टी. के शिकंजे में फंस जाता है तो वह अपने व्हीक्ल से हाथ धो बैठता है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के तहत हरियाणा सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए ताकि अवैध खनन भी रूके और अवैध खनन के रूप में लोगों को परेशान करने की जो नीति बन चुकी है उस पर भी रोक लग सके। यह बात सही है कि अवैध खनन से हमें रैवेन्यु लॉस होता है और ओवर लोडिंग से सड़कें टूटती हैं और लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ होता है। अध्यक्ष महोदय, नारनौल–महेन्द्रगढ़ से लेकर दिल्ली तक शाम को 6:00 बजे से लेकर रात 11:00/12:00 बजे तक सड़क पर राजस्थान और हरियाणा से माइनिंग के ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे और दूसरे साधनों को क्रॉस करने की जगह भी नहीं मिलती है। इस बात पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। पहले तो सरकार को अवैध खनन रोकना चाहिए और उसके बाद ओवर लोडिंग रोकनी चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सही आदमी को गलत सजा न मिले।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका नहरी पानी पर निर्भर है। जमीनी पानी इतना अच्छा नहीं है और नहरी पानी पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता

है। मेरे इलाके में नहर और ड्रेन के माध्यम से ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। लेकिन पिछले 6–7 महीनों से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। आज फसल कुदरती तौर पर ठीक है लेकिन पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ड्रेन में खासतौर पर पानी किसानों के लिए सुनिश्चित किया जाये ताकि हमें सिंचाई के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आये। पहले हमें नहरी पानी ठीक प्रकार से मिलता रहा था, लेकिन अब नहरी पानी कम मिल रहा है। हमें पानी ठीक मात्रा में दिया जाये ताकि हमारे किसानों का गुजारा हो सके। धन्यवाद।

श्री सोमवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 में दादरी को जिला बनाया गया था। मेरे ख्याल से यह हरियाणा का पहला ऐसा जिला होगा जिसके अंदर राजकीय कॉलेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सदन के नेता से प्रार्थना है कि दादरी में राजकीय कॉलेज बनाया जाये। हमारे दादरी में मैडिकल कॉलेज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे हल्के के छप्पार गांव में मैडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध है लेकिन मैडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया है। दादरी हल्के के आधे से ज्यादा लोग रोहतक मैडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे हल्के में भी सरकार की पॉलिसी के मुताबिक मैडिकल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मांग यह भी है कि वर्ष 1996 से लगभग 203 एकड़ में सी.सी.आई. फैक्टरी बंद पड़ी हुई है, सरकार को उस जमीन को अपने अंडर लेकर किसी कॉमर्शियल परपज़ के हिसाब से यूज करनी चाहिए। मेरे हल्के का इमलोटा गांव की हजारों एकड़ भूमि पिछले 30 वर्षों से पानी में डूबी हुई है जिसके कारण हजारों एकड़ फसल पानी के कारण बर्बाद हो जाती है। इसके साथ 5–7 गांवों का तो समाधान हो गया है, इसलिए इस गांव का भी समाधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दादरी से खरड़ी मोड़ तक 30–35 किलोमीटर का इलाका है उसको फोर–लेन मंजूर करके हाई–वे तक कनेक्टिविटी हो जायेगी तो दादरी के लोगों को सुविधा मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, दादरी हल्के में जो आखरी टेल तक पानी जाता है, वह आधे से ज्यादा पानी बीच में ही चोरी हो जाता है। सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरी मांग है कि रोहतक रोड पर रेलवे फाटक पर पुल बनाया

जाना चाहिए और शहर की सीवरेज़ व्यवस्था को भी दुरस्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने वर्ष 2014 में एक्स–सर्विसमैन और एक्स–पैरामिलिट्री परसोनल्स को फ्लैट्स देने के लिए ऐप्लीकेशंज इनवाइट की थी । गुरूग्राम, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, फरीदाबाद और झज्जर में जनवरी 2015 में ड्रॉ निकाला गया था । उसके बाद अलॉटीज ने उनकी 25 परसैंट पेमैंट भी हाउसिंग बोर्ड में नार्म्ज के मुताबिक जमा करवा दी थी, लेकिन अभी तक उन फ्लैट्स पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनका निर्माण–कार्य शुरू करवाया जाए । आप जानते हो कि हमारे जो एक्स–सर्विसमैन हैं वे एक–एक पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ते हैं । अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पुनः कहूंगा कि इन फ्लैट्स के निर्माण का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं । माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद और माननीय सदस्य श्री मामन खान ने सदन में पानी की कमी की बात रखी है । उनकी इस बात की मैं भी हिमायत करता हूं । इस संबंध में मैं, माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद और माननीय सदस्य श्री मामन खान माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे । हमारे इलाके में जो आबपासी डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं और उनमें जो पानी चल रहा है वह सिर्फ कामचलाऊ ही है । जब इस संबंध में हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिले थे तो उन्होंने बताया था कि इस काम में कानूनी अड़चन है । उनकी बात ठीक है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल से कहना चाहूंगा कि बाकी हरियाणा के मुकाबले हमारे मेवात में पानी के साधन बहुत कम है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मैं इससे मना नहीं करता कि बाकी हरियाणा में भी पानी की कमी की समस्या नहीं है । हमारा फिरोजपुर–झिरका, नूंह और पुन्हाना का एरिया प्रदेश की नहरों के टेल पर पड़ता है । मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । हमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नरम स्वभाव से उम्मीद है कि वे हमारे क्षेत्र की इस पानी की समस्या का कोई

न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र एक बहुत ही ड्राई एरिया है और वहां पर पानी की बहुत भयंकर समस्या है । वहां पर किसान अपने ट्यूबवैल्ज से सिंचाई करते हैं । वहां के लगभग 20 गांवों में टमाटर की फसल बहुत ज्यादा होती है लेकिन वहां पर कोई भी 'टमैटो प्रोसैसिंग यूनिट' नहीं है । टमाटर के खराब होने से वे उनको या तो पशुओं को खिलाते हैं या फिर सड़कों पर फेंकते हैं । बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र के निवासियों ने मुझे चुनकर विधान सभा में भेजा है, इसलिए उनके हक की आवाज उठाना मेरा फर्ज है । अतः मेरी पुनः गुजारिश है कि बाढ़ड़ा में एक 'टमैटो प्रोसैसिंग यूनिट' अवश्य खोली जाए ताकि वहां के लोगों को काम मिले । इस यूनिट के खुलने पर बाढ़ड़ा में महिलाओं को भी काम मिलेगा । बाढ़ड़ा के चंदेनी गांव की लड़कियां कबड्डी और वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं । जब भी हम वहां पर जाते हैं तो लड़कियां हमें घेरकर कहती हैं कि वहां पर हॉल नहीं है, अभी कुछ दिन पहले वहां कबड्डी का मैच हुआ तो उस दौरान वहां पर किराये का मैट मंगवाया गया, तब जाकर वहां पर कबड्डी का मैच हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि वहां पर एक हाल का निर्माण करवाया जाए और उन लड़कियों को सुविधाएं दी जाएं। इसके अतिरिक्त एक विषय दातौली गांव से संबंधित है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग के अंडर है। इस गांव में पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या है। अभी कुछ दिन पहले विधान सभा का इलैक्शन हुआ था और उससे पहले लोक सभा का इलैक्शन हुआ था। इन इलैक्शंज में दातौली गांव के लोगों ने वोट नहीं डाला और गांव के बाहर बैनर लगा दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनके कार्यकर्ता गांव में वोट मांगने के लिए न आएं। इस गांव में पीने के पानी की सुविधा की जाए। इसके अतिरिक्त बहुत लम्बे समय से बाढ़ड़ा हल्के के किसान राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और कम से कम उनको 8 महीने हो गये हैं। इस दौरन वहां पर बैठे–बैठे 7 या 8 किसान शहीद हो चुके हैं। मेरी गुजारिश है कि उन किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त दातौली गांव की पीने के पानी की समस्या का हल किया जाए और बाढ़ड़ा हल्के के लिए एक टैमाटो प्रोसैसिंग यूनिट लगायी जाए। धन्यवाद।

श्री राम करणः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः राम करण जी, प्लीज आप बैठ जाएं। आपको बाद में बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

श्री प्रदीप चौधरीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज ट्रैफिक की बहुत भारी समस्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिजौंर –नालागढ़ का जो रोड है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। वहां पर पहले फोरलेन बनाने का प्रावधान किया गया था। अब सुनने में आया है कि संबंधित रोड को फोरलेन नहीं बनाया जाएगा। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इसको फोरलेन किया जाए। इसके अतिरिक्त मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र के सारे रोडज टूटे हुए हैं। पहले रोडज पर पैच वर्क हुआ करता था, परन्तु शायद अब बन्द कर दिया गया है। इसमें फिर चाहे मौली से रायपुररानी चले जाएं या रायपुररानी से टोका चले जाएं या चाहे पिंजौर से कालका चले जाएं। इन सभी जगहों पर रोड्ज टूटे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि वहां पर कम से कम पैच वर्क करने का प्रावधान किया जाए।

श्री राम करणः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से विनती है कि मेरे शाहबाद हल्के के पटवारखाने का जमीनों के रिकार्ड के मामले में पूरे हिन्दुस्तान में नाम है। वहां पर सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है, इसलिए वहां पर क्रिकेट और फुटबाल का ग्राउंड बनाया जाए। इस काम के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे क्योंकि वहां पर संबंधित काम के लिए जमीन भी खाली पड़ी हुई है। धन्यवाद।

श्री धर्म सिंह छौक्करः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ–साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे समालखां टाउन में कोई गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है, जिसके कारण वहां की लड़कियों को बाहर पढ़ने जाने के कारण आने–जाने में असुविधा होती है क्योंकि उनको पढ़ने के लिए पानीपत जिले में जाना पड़ता है, इसलिए समालखां हल्के में एक कन्या विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या कॉमन है। मेरे साथी इसराना के विधायक जी भी बैठे हुए हैं, पानीपत हल्के से विधायक श्री प्रमोद विज जी भी हैं और मैं समालखां हल्के से विधायक हूं। इन तीनों हल्कों के साथ 8

नम्बर ड्रेन लगती है। इस बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से प्री बजट में भी प्रार्थना की थी। इस ड्रेन नम्बर 8 में कैमिकल इन्डस्ट्रीज और टैक्सटाईल इन्डस्ट्रीज का गंदा पानी तीनों कांस्टीच्यूअंसी से होते हुए यमुना में जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इस पानी को ट्रीट किया जाए क्योंकि यह पानी इतना जहरीला है कि अगर किसी के पैर या हाथ पर एक बून्द भी गिर जाए तो वह हिस्सा गल जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं डिप्टी सी.एम. साहब और माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने पहले प्री बजट डिस्कशन में भी रिकवेस्ट की थी और सुझाव भी दिये थे। एक पी. डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस समालखां हल्के में बनाया जाए ताकि किसी वी.आई.पी. को वहां पर रूकना पड़ जाए तो वहां पर रूक सके क्योंकि वहां पर रेस्ट हाऊस की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उप मुख्य मंत्री जी इन बातों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही साथ यमुना एक्सप्रैस की चर्चा भी चली। इसके बारे में पहले भी चर्चा चली थी और फिर बन्द हो गयी। यह चर्चा फिर चली और उसके बाद फिर बन्द हो गयी। मेरी कांस्टीच्यूअंसी यमुनानगर के साथ–साथ लगती है। यमुनानगर को के.एम.पी. के साथ जोड़ दिया जाए तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो यह होगा कि इससे यमुना का बांध पक्का हो जाएगा क्योंकि हर साल करोड़ों रुपये का बजट बाढ़ को रोकने के लिए पत्थर व दूसरी चीजों के लिए खर्च होता है। उसका बचाव हो जाएगा। वहां पर बांध पहले से ही बना हुआ है और यह 40 फुट चौड़ा है जिसके कारण खर्चा भी कम आएगा। वहां पर जमीन भी है और उस पर यमुना एक्सप्रेस बना दिया जाए तो जी.टी. रोड का जो कंजैस्टिड ट्रैफिक है, वह बाहर से ही यमुनानगर के साथ–साथ के.एम.पी. से जाकर आगे गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश तक कनैक्ट करेगा। इससे चार राज्यों को फायदा होगा जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–काश्मीर का ट्रैफिक शामिल है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल गोंदर : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी और सभी विभागों के माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि वन विकास निगम में अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर तैयार किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस

महान सदन में यह कहना चाहता हूं कि विभाग जब कभी सरकारी ऑफिस के लिए, किसी संस्था के लिए या सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदता है तो एक ही दुकानदार से कम रेट पर तीन कोटेशन बनवा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी मंत्रीगण जी से निवेदन है कि जब भी वे अपने–अपने विभाग के लिए फर्नीचर खरीदते हैं तो वन विकास निगम से ही फर्नीचर खरीदने का काम करें क्योंकि वहां पर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर मिलता है और वह काफी सालों तक भी चलता है।

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुलाना विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर पी.डब्ल्यू. डी. विभाग और मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी सालों साल तक रिपेयर नहीं होती हैं जिसके कारण आये दिन वहां पर एक्सीडैंट्स से होने वाली मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है इसलिए जल्दी से जल्दी इन सड़कों को रिपेयर करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सड़कों पर माइनिंग के ओवरलोडिड ट्रक चलते हैं, जिनकी प्रोपर तरीके से ब्रेक भी नहीं लगती है। ओवर लोडिंग के कारण ये सड़कों को भी तोड़ने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा गया है कि सरकार को काफी राजस्व प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा तो सड़कों के निर्माण कार्यों में लग जायेगा इसलिए सरकार इस बात पर भी ध्यान देने की कृपा करे।

श्री सुभाश गांगोली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं कि हमारे सफीदों विधान सभा क्षेत्र और जुलाना विधान सभा क्षेत्र में जो ग्राउंड वाटर है, वह बहुत ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे विभाग ने अंडर पास पर 70 फुट का गहरा चौआ बनाया है, उसमें 6–7 फुट तक पानी खड़ा रहता है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर वहां के स्थानीय लोग धरने पर बैठे हुए थे। मैं उन लोगों को मना कर धरने से उठाकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं उन स्थानीय लोगों को दो महीने के लिए तो धरने से उठा दिया परन्तु उन्होंने मुझे कहा है कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो वे दोबारा से दिनांक 25 अप्रैल, 2020 को धरने पर बैठ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक रोडवेज की बस और एक स्कूल बस इस रेलवे अंडर पास के नीचे डूब गई थी।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना से 10 दिन पहले एक व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी में उचाना गांव से मोरखी गांव में आया था। उसने देखा कि इसमें सिर्फ 4 फुट पानी है इसलिए वह आसानी से निकल गया लेकिन इसके 10 दिन बाद वह अपने उचाना गांव में जाने लगा तो वह उस पानी में डूब गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वे दिनांक 25 अप्रैल, 2020 को दोबारा धरने पर बैठेंगे और रेलवे का रास्ता रोकने का काम भी करेंगे इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि दिनांक 25 अप्रैल, 2020 से पहले–पहले इस गंभीर समस्या को हल करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे हल्के इसराना में डाहर और नौलथा गांव आते हैं। वहां से पानीपत से रोहतक हाईवे भी निकलता है, इस हाईवे पर ब्रेकर नहीं बनाये गये हैं जिसके कारण कई बच्चों और कई व्यक्तियों की एक्सीडैंट्स होने से मौतें भी हो चुकी हैं इसलिए वहां पर ब्रेकर बनवाये जायें और ब्रेकर बनने के बाद उन ब्रेकरों को हटाया न जाये। अध्यक्ष महोदय, गांव नामुण्डा से गांव ग्वालड़ा तक की सड़क लगभग काफी दिनों से टूटी हुई है क्योंकि गांव नामुण्डा श्री धर्म सिंह छौक्कर जी के हल्के में पड़ता है। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी गये थे। अध्यक्ष महोदय, तब स्थानीय लोगों ने सड़क बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना भी की थी परन्तु उस सड़क पर आज भी काम शुरू नहीं हो पाया है जबकि वहां पर एक्सीडैंट होने के कारण दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि चुनाव से ठीक कई महीने पहले मेरे गांव ग्वालड़ा से कुतबपुर बली सड़क जाती है, उस सड़क का माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय पूर्व परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी ने पत्थर लगाने का काम किया था परन्तु आज तक इस सड़क पर एक पैसे का भी काम शुरू नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि करनाल से लाडवा वाया इंद्री सड़क को फोरलेन

किया जा रहा है। इस सड़क को करनाल जिले की सीमा तक तो फोरलेन कर दिया गया है लेकिन कुरूक्षेत्र जिले की सीमा में जो इस सड़क का 6 किलोमीटर का हिस्सा है उसको फोरलेन बनाने का काम छोड़ दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस सड़क की फोर लेनिंग के कार्य को लाडवा तक कम्पलीट किया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यमुना नदी से जितनी भी माईनिंग होती है उसका तमाम ट्रैफिक लाडवा के बाजार से होकर गुजरता जाता है। इससे लाडवा के बाजार में सारे का सारा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। मेरा उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि लाडवा के बाई–पास का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाये। जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय में उनके अथक प्रयासों से लाडवा के बाई पास को बनाने की प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू हो चुकी थी। जमीन की निशानदेही हो चुकी थी और इस बाई पास को बनाने के लिए जमीन को एक्वॉयर करने के लिए सैक्शन–04 व 06 के नोटिस भी जारी हो चुके थे। यह महज 2 से अढ़ाई किलोमीटर लम्बा बाई–पास है। मेरा उप मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि इस बाई–पास का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाये ताकि लाडवा हल्के को जाम से छुटकारा मिल सके। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यमुनानगर से पेहवा होते हुए पटियाला पंजाब बॉर्डर तक एक फोरलेन सड़क का निर्माण होना था। इसमें पेहवा, थानेसर, लाडवा, रादौर और यमुनानगर ये पांच हल्के लगते हैं। यह सड़क तीन राज्यों को जोड़ने वाली है इसलिए मेरी उप मुख्यमंत्री से यह भी रिकवैस्ट है कि इस सड़क को भी फोरलेन किया जाये। धन्यवाद।

श्री कुलदीप वत्स : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह रिकवैस्ट है कि मेरे बादली विधान सभा क्षेत्र में किलोई गांव है। पूरे जिला झज्जर की चकबंदी हो चुकी है लेकिन आज तक किलोई की चकबंदी नहीं हुई है। इसके लिए मेरे हल्के के लोग बहुत बार पूर्व कृषि मंत्री जी से भी मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा था। मेरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार–बार यही रिकवैस्ट है कि मेरे बादली हल्के के किलोई गांव की चकबंदी का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बादली को सब–डिवीजन बनाने की घोषणा की थी। बादली शहर के अंदर बस–स्टैण्ड की जगह है और वहां पर बस स्टैण्ड की मंजूरी भी हो चुकी है लेकिन आज तक भी वहां पर

बस–स्टैण्ड का निर्माण नहीं हो पाया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि बादली शहर के बस–स्टैण्ड को भी जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बादली से गुरूग्राम रोड जहां पर रिलांयस के प्रोजैक्ट चले हुए हैं इस कारण वहां पर बहुत भारी ट्रैफिक के.एम.पी. से उतरकर गुरूग्राम की तरफ जाता है। बीच में पेलपा और सौंधी गांव आते हैं। भारी व्हीकल्ज के कारण वहां पर बहुत बार बड़े–बड़े हादसे हो चुके हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर जल्दी से जल्दी बाई–पास रिलायंस से बनवाया जाये या फिर सरकार स्वयं अपने खर्च से वहां पर बाई–पास का निर्माण करवाये। अब उप मुख्यमंत्री जी से यह रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि पाटौदा गांव के अंदर पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस की करोड़ों रूपए की जमीन है। वहां पर पुराने समय का पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस है। मेरा यह निवेदन है कि उसको रेनोवेट करवाया जाये या फिर उसको नये सिरे से बनवाया जाये क्योंकि यह एक बहुत ही पुरानी धरोहर है। प्रॉपर पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस न होने के कारण लोगों द्वारा करोड़ों रूपये की जमीन को कब्जाया हुआ है। उसको खाली करवाकर वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस का निर्माण करवाया जाये। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में एक कुलाना चौंक पड़ता है। रेवाड़ी–झज्जर–पटौदी की उस चौंक से कनैक्टिविटी है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि 50–60 गांव इस चौंक से कनैक्टिड हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वहां पर एक अण्डर पास का निर्माण करवाया जाये क्योंकि वहां पर अण्डर पास न होने की वजह से बार–बार एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय चौधरी दीपेन्द्र हुड्डा जी और आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र हुड्डा साहब ने सुबाना गांव का बाई–पास मंजूर करवाया था लेकिन उस बाई–पास का अभी तक भी निर्माण नहीं करवाया गया है। इस बाई–पास के न होने के कारण भी मेरे बादली हल्के को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मेरी सरकार से यह मांग है कि सुबाना गांव के बाई–पास का भी जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बादली की रैली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि बादली को नगर पालिका बनाया जायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि झज्जर को उन्होंने नगर पालिका से नगर निगम घोषित कर दिया लेकिन बादली को अभी तक भी नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया गया है। हमें यह बताया जाये

कि इस मामले में क्यों हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बादली को जल्दी से जल्दी नगर पालिका का दर्जा दिया जाये। सरकार से मेरा एक निवेदन यह है कि मेरे हल्के में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का बहुत भारी नुक्सान हुआ है इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यह रिकवैस्ट है कि किसानों की फसलों के नुक्सान की स्पैशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उनकी फसलों के नुक्सान का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाये। इससे मेरे हल्के के किसानों में बड़ी भारी निराशा है क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि से उनके फसलों को हुए नुक्सान की अभी तक भी गिरदावरी नहीं हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को मुआवजे की राशि जल्दी से जल्दी वितरित करवाते हैं तो उनकी बहुत कृपा होगी। जो अभी मैंने गांव के अण्डर पास के निर्माण की बात की है उस सम्बन्ध में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल रिकवैस्ट है कि वहां पर अण्डर पास के अभाव में जान माल का बहुत भारी नुक्सान होता है वहां पर लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल होता है इसलिए वहां पर अण्डर पास का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाये। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार–बार यही रिकवैस्ट है कि मेरे हल्के में मेरे कहे अनुसार अण्डर पास का अतिशीघ्र निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक विषय और उठाना चाहूंगा। दिनांक 21.12.2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा झज्जर आये थे और उनके साथ उस समय के केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री वल्लभ राजू भी उपस्थित थे। उस समय आई.आई.टी. के लिए घोषणा हुई थी तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाढ़सा गांव ने अपनी 50 एकड़ जमीन इसके लिए दी थी जिसका इंतकाल भी हो गया है लेकिन आज तक वहां पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका निर्माण कार्य शुरू न होने का क्या कारण रहा है? इसी तरह से हमारे ऐम्स की जो 10 यूनिट बननी हैं उनका काम भी यथाशीघ्र पूरा करवाया जाए।

श्री बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों सरकार ने जल ही जीवन है नाम से एक स्कीम चलाई थी। उसके तहत किसानों को प्रेरित करने के लिए कुछ जिलों को मक्का की खेती के लिए चुना गया था। उन जिलों में किसानों को प्रेरित करने के लिए ए.डी.ओज. की भी ड्यूटी लगाई गई थी तथा किसानों को समझाया

गया कि आप ज्यादा से ज्यादा मक्का की बिजाई करो। उसके लिए सरकार ने मक्का की बिजाई करने वाले किसानों के लिए कुछ इनसैंटिव रखा था। उस इनसैंटिव के तहत किसान की मक्का की फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार की तरफ से करवाया जाना था। उस स्कीम से प्रेरित होकर किसानों ने मक्का की बिजाई भी कर दी लेकिन ओलावृष्टि या बारिस के कारण उनकी फसल खराब हो गई। अब सरकार ने किसानों को बताए बिना या उनसे पूछे बिना बैंकों को कह दिया कि किसानों को बीमा राशि का मुआवजा न दिया जाये क्योंकि सरकार ने उनकी फसल की बीमे की किश्त भरी ही नहीं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय पर दोबारा से विचार किया जाए तथा जिन–जिन किसानों की मक्का की फसल खराब हुई है उनको इनसैंटिव दिया जाए।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा विधान सभा क्षेत्र असंध शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है इसलिए असंध में एक पॉलिटैक्निक कॉलेज बनवाने की मेहरबानी कर दें तो आपका बहुत–बहुत धन्यवाद होगा। इसी प्रकार से असंध और करनाल के बीच में सिंगल रोड पर जो टोल प्लाजा लगाया गया है उसको भी हटवाया जाये। इस बारे में मैं लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी दे चुका हूं। इस टोल प्लाजा से वहां के लोगों में बहुत आक्रोस है क्योंकि लोगों को असंध से करनाल बहुत ज्यादा आना–जाना पड़ता है इसलिए इस टोल प्लाजा को वहां से हटाया जाए क्योंकि यह तो उनके लिए एक तरह का जजिया कर हो गया। अगर उस टोल प्लाजा को सरकार नहीं हटाना चाहती है तो असंध को जिला बना दिया जाए जो वहां के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है और इस बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में भी दे चुका हूं क्योंकि असंध चारों जिलों जीन्द, कैथल, पानीपत और करनाल से 45–45 किलोमीटर की दूरी पर है जबकि 25–25 किलोमीटर की दूरी वाले भी जिले बने हुए हैं। अगर असंध को जिला बना दिया जायेगा तो हमारा असंध विधान सभा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको अगड़े क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने पिछले दिनों कैथल में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में वहां पर

इसकी जरूरत भी थी। कैथल शहर की लगभग अढ़ाई लाख की आबादी है तथा कैथल से 50–60 किलोमीटर तक कोई मेडिकल कॉलेज या पी.जी.आई. नहीं है। यह कैथल के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब घोषणा की गई थी कि कैथल में पी.जी.आई. बनाई जायेगी, उसके बाद कहा गया कि यहां पर मिनी पी.जी.आई. बनायेंगे लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बहन गीता भुक्कल जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार के समय में भी इस प्रकार की घोषणाएं होती थी कि कैथल में पी.जी.आई. बनाई जायेगी। वहां पर तो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि कैथल के अस्पताल में जो मशीन और इंस्ट्रूमैंट्स आये थे उनको बहन गीता भुक्कल जी झज्जर में ले गई। मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता था कि उनके राज में इस प्रकार की घोषणाएं होती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कैथल में मैडिकल कॉलेज मंजूर करने से कैथल के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। मैं कैथल के लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि कैथल में मैडिकल कॉलेज बनने से हरियाणा के कैथल व जीन्द के लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे नजदीक लगते पंजाब के संगरूर जिले को भी उसका फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जरूर बताना चाहूंगा कि उस कॉलेज के लिए कैथल शहर के नजदीक लगते एक डेरा में और करनाल रोड़ पर सांपली खेड़ी गांव में सैंकड़ों एकड़ जमीन मिल सकती है।

16:00 बजे

श्री अध्यक्ष : लीला राम जी, इन सारी चीजों के बारे में तो आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल लेना।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई लीला राम गुर्जर जी ने विशेष रूप से मेरा नाम लेकर कहा है कि आप जब कैथल से झज्जर गई तो कैथल से पी.जी.आई. भी झज्जर ले गई। चलो इनकी यह बात तो ठीक है कि पहले मैं कैथल जिले से चुनाव लड़ती थी अब मैं झज्जर जिले से चुनाव लड़ती हूं। दूसरी बात लीला राम जी, आप अफवाओं पर ध्यान न दें क्योंकि उस समय कैथल में पी.जी.आई. बनाने की कोई किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई थी। हमारे झज्जर में आज तक भी मात्र 100 बैडिड होस्पिटल है जिसके बारे में मैं पिछले पांच साल से विपक्ष में रहते हुए एक नर्सिंग कॉलेज और कई चीजों की मांग कर रही हूं। आप हमारे समय की हैल्थ डिपार्टमैंट की कोई भी घोषणा उठाकर देख लें या

मुख्यमंत्री की घोषणा उठाकर देख लें उनमें कैथल में पी.जी.आई. या मिनी पी.जी. आई. बनाने की घोषणा नहीं थी। दूसरा आप सरकार से जरूर पूछ लें कि पिछले टर्म से कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बार–बार चर्चा हो रही है लेकिन आज तक भी उस पर काम नहीं हुआ। उस संस्कृत विश्वविद्यालय में अब तक न कोई वाईस चांसलर है, न कोई रूम्ज बने हुए हैं, वहां कुछ भी नहीं है। वहां वाईस चांसलर की नियुक्ति पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर काम शुरू हो गया है।

श्रीमती गीता भुक्कल : लीला राम जी, क्या आप बताएंगे कि वहां कितने कमरे बन गये हैं और कहां पर बने हैं? वहां कहां पर क्लासिज चल रही हैं और उस संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ कितने कॉलेजिज ऐफीलिएटिड किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सभी चीजें क्लीयर करना चाहती हूं क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है और उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। मेरा इनसे अनुरोध है कि ये अफवाओं पर ध्यान न दें क्योंकि कैथल में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई थी।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, बहन जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने लोगों का भ्रम तो दूर कर दिया परंतु वहां पर तो दीवारों पर बड़े–बड़े पोस्टर छपे हैं, मुनादी की गई है कि कैथल में पी.जी.आई. खुल गया। वे इनकी पार्टी के ही नेता होंगे जिन्होंने यह प्रचार किया था। हमारी पार्टी के नेताओं ने तो यह प्रचार नहीं किया। यही सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है कि कैथल में जो मैडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है उसके लिए सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद। बहन जी का भी धन्यवाद कि इन्होंने हमारा अंधेरा दूर कर दिया है क्योंकि हम भ्रम में थे।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ होगी। डॉ. अभय सिंह यादव विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव(नांगल चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेक्ष निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए–

''कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है'।''

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपना भाषण इस सदन में दिया है। संविधान की धारा 154 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय राज्य के कार्यकारी मुखिया होते हैं। संविधान की धारा 176 के तहत राज्यपाल महोदय को सदन का जब नया चुनाव होता है तो हर आम चुनाव के बाद जो पहला अधिवेशन होता है उसमें राज्यपाल महोदय को अभिभाषण देना होता है तथा इसी तरह से नये साल का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। वैसे आर्टिकल–175 के मुताबिक राज्यपाल महोदय कभी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं और अपना संदेश भी भेज सकते हैं और उसी क्रम में राज्यपाल महोदय ने अपना संदेश दिया भी है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी यहां प्रजातंत्र की जो प्रक्रिया है, उसके तहत चुनकर सदन में आये हैं। जब चुनाव के समय हम जनता के सामने जाते हैं तो हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र लेकर जाती है और उस घोषणा पत्र को देखकर जनता की जो जनभावनायें होती हैं या अपेक्षायें होती हैं, उन पर विश्वास करके लोग पार्टियों को वोट देते हैं। किसी पार्टी के घोषणा पत्र में जो एजेंडा होता है, उस पर लोगों का विश्वास ही किसी पार्टी को सत्ता में लेकर आता है और आगे चलकर इसी एजेंडे के मुताबिक ही पार्टियां चलती भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि 'ए' सरकार ज्यादा काम करती है या 'बी' सरकार ज्यादा काम करती है। हरियाणा प्रदेश 1 नवम्बर, 1966 को बना था। 1966 का जो हरियाणा था उसके परिपेक्ष्य में आज का हरियाणा ज्यादा विकसित और सशक्त हरियाणा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी सरकारें इस प्रदेश में सत्ता में रही, हर सरकार ने अपने–अपने हिसाब तथा प्रयासों के मुताबिक इस प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने की हर संभव कोशिश की और हर सरकार ने अपने हालातों व अपनी शक्तियां के हिसाब से बैस्ट देकर इस प्रदेश को विकास की राह में ले जाने का काम किया है जिसके कारण ही आज 2020 में हमारा प्रदेश इस मुकाम पर पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि किसी सरकार ने बुरा काम किया या किसी सरकार ने अच्छा काम किया बल्कि जो वास्तविकता है मैं तो केवल

वही बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज सरकारों के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है या चुनौती है वह यह है कि आज का समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और इस बदलते हुए समय में सरकारों को रोजाना नई–नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि भीमबेटका और सतपुड़ा की मांसाहारी सभ्यता से सिंधु सरस्वती की सभ्यता तक पहुंचते–पहुंचते हजारों सालों का समय बीत गया था। अगर हम आज के जीवन को तथा पुराने जीवन को देखें तो पायेंगे कि समय इतना तेजी के साथ बदला है कि जहां हम पहले नाड़ी–नब्ज दिखाकर वैद्य से दवाई लिया करते थे आज के हालात में हम आर्गेन ट्रांसप्लांट की स्टेज तक पहुंच गए हैं। यही नहीं बैलगाड़ी से चलने वाले हम लोग आज सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले जहाजों तक पहुंच गए हैं। समय इतना तेजी से बदला है कि इस बदलते समय में हर सरकार को कुछ अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संचार के साधनों ने दुनिया के देशों में आपसी दूरियां कम कर दी हैं। बदलती हुई दिनचर्या के मुताबिक ही लोगों की सरकार के प्रति अपेक्षायें व जनभावनायें भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी हैं और मैं समझता हूँ कि सरकारों के सामने उन जनभावनाओं के अनुरूप काम करना वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं इसी क्रम में अपनी सरकार द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में भी संक्षिप्त में जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार को पहली बार सत्ता में आने का मैंडेट मिला तो उस समय सरकार ने चुनाव के दौरान जो माहौल देखा था और चुनाव के दौरान जो हमारा एजेंडा था या हमारा घोषणा पत्र था उसके आधार पर हमारी सरकार ने सारे प्रदेश का एकमुश्त विकास करने का बीड़ा उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबका साथ–सबका विकास का नारा दिया वह मात्र एक नारा नहीं था बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ी भावना छिपी हुई थी कि हम सब मिलकर ऐसे प्रयास करेंगे जिससे पूरे प्रदेश का एक साथ विकास संभव हो सके और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह विकास हुआ भी है और यह विकास किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहा बल्कि समस्त प्रदेश के सभी क्षेत्रों व सभी विभागों में समान रूप से विकास कार्य किए गए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कृषि विभाग की बात करता हूँ। कृषि विभाग में सरकार का जो बहुत ही सराहनीय काम रहा वह कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि का है। निःसंदेह इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिला है और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। मैं उदाहरण के रूप में बाजरे

की फसल के बारे में बताता हूँ। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1900 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है लेकिन इससे पहले बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 1100 रूपये प्रति क्विंटल ही था। इससे किसानों की आमदनी रातोंरात दोगुनी हो गई है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) इसी प्रकार से सरसों और कपास के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाए हैं। आज किसान की खेती लाभ की हालत में पहुँचने लगी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 93 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई और किसानों को इसके लिए 17,222 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, खरीफ मार्केटिंग सीजन वर्ष 2019–20 के दौरान 11,870 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि से 64 लाख 69 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद 1835 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से खरीदी गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने फसल मुआवजे की राशि भी निर्धारित की है। अध्यक्ष महोदय, हमें बचपन की वे बातें याद हैं कि ज्यों ही बरसात के समय ओले पड़ने शुरू होते थे त्यों ही हमारे गांव की बुजुर्ग महिलाएं भाग कर रसोई से तवा लेकर आती थी और बरसात में उल्टा करके रख देती थी। इसका मतलब यह हुआ करता था कि हे ! भगवान हमारे ऊपर दया कीजिए क्योंकि हमारी रोजी–रोटी की बात है। अगर आपने हमारी फसल को नष्ट कर दिया तो हमारे तवे की रोटी बंद हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों को इस मामले में बेनिश्चित करने के लिए 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा फसल खराब होने पर दिया है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने के बहुत सारे मंच हो सकते हैं लेकिन 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' पर राजनीति न करके सही तरीके से देखें और पढ़े तो किसानों को इससे बढ़िया पॉलिसी नहीं मिल सकती है। इस पॉलिसी में किसानों के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं कि यह बात आपके माध्यम से सदन में कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को लागू करने में विभाग और सरकार को जितना प्रयास करना चाहिए था उतना प्रयास नहीं हुआ है। अर्थात् 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की जागरूकता लोगों में उतनी नहीं पहुँची है जितनी पहुँचनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुँचाई जाये। अध्यक्ष महोदय,

सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' के बारे में उठाया है। जैसे आदमी को बीमारियां लगती है उसी प्रकार मिट्टी को भी बीमारियां लगती है। मिट्टी का उपचार भी ठीक उसी तरह नहीं हो सकता जिस प्रकार आदमी का उपचार बिना टैस्ट लैब के नहीं हो सकता। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' हमारे प्रदेश में बने हुए हैं और मेरी सूचना के मुताबिक 81 लाख 69 हजार के करीब 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' इशू किए गए हैं। इस वर्ष सरकार का कृषि विपणन समितियों की 111 मंडियों और सबयार्ड में मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। अगर किसी मरीज की बीमारी लैब में टैस्ट करेंगे और उसे टैस्ट की रिपोर्ट दे देंगे तो उस मरीज को कोई फायदा नहीं होगा। जब तक डॉक्टर उसको दवाई और सलाह नहीं देगा तब तक वह टैस्ट रिपोर्ट उस मरीज के किसी भी काम की नहीं है। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' सरकार ने बना दिए हैं लेकिन इसमें दो–तीन और काम करने की जरूरत है। एक तो जो सैंम्पल हैं, सैंम्पल का रैंडम वैरीफिकेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक भी सैंम्पल गलत हुआ तो वह सारे के सारे सिस्टम को डैमेज कर देगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ स्टेट लैवल पर एक्सपर्टज की एक टीम बनाई जाये और वह टीम हर 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' को देखकर अपनी संस्तुति दे कि अमूल खेत में यह फसल बोई जा सकती है या फिर इस खेत में यह फसल नहीं बोई जा सकती है। इस फसल के लिए इतनी जैविक खाद की आवश्यकता है या फिर इसमें दवाई का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सारी की सारी एक डिटेल पास बुक बनाकर किसान को देनी चाहिए। जैसा कि चकबंदी के समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि हर किसान को एक पास बुक बनाकर दी गई थी। जिसमें किसान की भूमि का सारे का सारा विवरण था। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' में भी दवाई और सलाह की पूरी डिटेल एक्सपर्ट टीम बनाकर किसानों को देगी तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा कदम होगा। इसी के साथ कृषि क्षेत्र में मेरा एक और सुझाव है । यह सुझाव मैंने प्री–बजट डिस्कशन सैशन में भी दिया था । हमने वन मैम्बर किसान आयोग बनाया है । मेरे ख्याल से किसान आयोग का पिछले 4 साल से जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वह नहीं रहा है । अगर मेरी सूचना गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा । इसमें मेरा सुझाव है कि किसान आयोग मल्टी मैम्बर बना दिया जाए और उसमें एक सॉयल साइंटिस्ट, एक ऐग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट शामिल कर दिया जाए और वे सभी मिलकर केवल किसानों के बारे में विचार करें । इसमें मेरा

एक और सुझाव है कि किसान आयोग का दफ्तर एच.ए.यू. में ही बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर लैब वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इससे किसी विषय पर रिसर्च भी की जा सकती है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के विषय पर बात करना चाहूंगा । यह सर्वविदित है कि हरियाणा के पास सीमित पानी है । हमारे पास पानी लेने के लिए भाखड़ा और यमुना सिस्टम केवल ये दो विकल्प ही हैं। यमुना सिस्टम से पानी एक निश्चित क्षेत्र में जा रहा है क्योंकि दूसरे क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए न तो सुविधा है और न ही उनके लिए पानी उपलब्ध है । हमारी सरकार ने इस विषय में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । प्रदेश में पानी लाने के लिए बनाई गई एस.वाई.एल. नहर का मामला भी किन्हीं कारणों से लटका हुआ है । दक्षिण हरियाणा में भाखड़ा से एस.वाई.एल. नहर के द्वारा पानी आना था लेकिन उससे वह पानी नहीं आ पाया । इसका परिणाम यह हुआ कि जहां पानी की बहुतायत है उस क्षेत्र में वॉटर लॉगिंग की प्रोब्लम हो गई और दक्षिण हरियाणा के जिलों मेवात, पलवल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और भिवानी में पानी की कमी की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो गई । फिलहाल हरियाणा को पंजाब से मिलने वाले 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी में से केवल 1.62 मिलियन एकड़ फुट पानी मिल रहा है । उस पानी में से आधे पानी को हरियाणा में हाँसी–बुटाना नहर के माध्यम से लाने की सरकार ने योजना बनाई । यह एक बहुत अच्छी योजना थी । जब इंडस वाटर ट्रिटी हुई तो उस समय हमें पाकिस्तान से रावी–ब्यास नदी का अतिरिक्त पानी मिलना तय हुआ था और इसके लिए उस जमाने में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 100 करोड़ रूपये दिए थे । उन कागजात के मुताबिक उस जमाने में दक्षिण हरियाणा को पूर्वी पंजाब कहा जाता था और यह पानी झज्जर, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़ जिलों के लिए लिया गया था । मुझे बड़े दुःख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन जिलों को पानी देने के लिए हाँसी–बुटाना नहर का निर्माण कार्य कैथल जिले के हजीमगढ़ से शुरू किया गया और आगे जाकर राइट साइड को टर्न देकर जींद के अंटा हेड में मिला दिया गया । अब दक्षिण हरियाणा के पास पश्चिमी यमुना लिंक नहर के अलावा पानी ले जाने का कोई अन्य विकल्प नहीं बचा । हाँसी–बुटाना नहर की दोनों में से किसी भी ब्रांच से दक्षिण हरियाणा के जिलों में पानी नहीं जा सकता । मैंने यह विषय सदन में पहले भी उठाया था कि हमारे साथ पानी के डिस्ट्रिब्यूशन में बहुत राजनीति हुई है और इस मामले में जितनी ज्यादा राजनीति हुई है उतना ही प्रदेश का और किसान का विकास रूका

है । अगर आप हरियाणा के वाटर लॉग्ड एरिया पर एक बार दृष्टि डालें तो आपको पता चलेगा कि वाटर लॉगिंग सिर्फ उन्हीं एरियाज में है जो कभी सत्ता के केन्द्र रहे थे । इसको आप रैंडमली चैक करवाकर देख लें। 80 प्रतिशत वॉटर लॉगिंग एरिया उन जिलों में है जो कभी सत्ता का केन्द्र रहे थे। इसका परिणाम बड़ा सीधा है कि कहीं पर वॉटर लॉगिंग हो रही है और कहीं पर सूखा पड़ रहा है। मैं इसके बारे में एक दूसरा उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि जे.एन.एल. फीडर मूल रूप से तीन जिला को पानी देने के लिए बनी है। ये एरियाज उस टाईम पर भिवानी जिले के अंडर आते थे, परन्तु अब दादरी जिले के अंडर आते हैं जिसमें दादरी, बाढ़ड़ा के अलावा लोहारू सब डिविजन आता है। इसके अतिरिक्त महेन्द्रगढ और रेवाड़ी जिले भी शामिल हैं। लोहारू कनाल जे.एन.एल. फीडर से निकलती है और बाखड़ा हैड से भिवानी जिले के एरिया को पानी देती है। जे.एन.एल. फीडर रेवाड़ी जिले को पानी देती है और महेन्द्रगढ़ कनाल महेन्द्रगढ जिले को पानी देती है। जे.एन.एल. फीडर के साथ वाले एरिया को पानी देने के लिए अलग से व्यवस्था थी। भालौठ ब्रांच जे.एल.एन. फीडर के पैरलल बनायी हुई है और इसके साथ झज्जर सब ब्रांच उसकी टेल पर थी क्योंकि झज्जर सब ब्रांच के टेल पर जो एरियाज थे, उनमें पानी कम आता था। इस प्रॉब्लम का यह उपचार किया गया है कि झज्जर सब ब्रांच को खत्म कर दिया और लगभग 900 क्यूसिक पानी डायरेक्ट आउटलेट्स देकर जे.एन. एल. फीडर से निकाल दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज सालावास तक धान की खेती की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी एरिया के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसे फैसले किसान को बर्बाद करते हैं। मेरी बात आप इस सदन के रिकार्ड में रिकार्ड करवा लें कि जिन क्षेत्रों में आज धान की खेती की जा रही है, उनको आप 10 साल के बाद देखेंगे तो वे क्षेत्र वॉटर लॉगिंग के एरियाज की लाईन में खड़े पाएंगे। इसका यही कारण है कि आज भी रोहतक और झज्जर के जिन इलाकों में धान की खेती की जाती है, उनमें तीन–चार बार पानी बदलना पड़ता है। इसका कारण यह है कि मिट्टी में पानी घुलने से सैलैनिटी बढ़ जाती है और ज्यों ही सैलैनिटी बढ़ती है तो उस पानी को निकालकर ताजा पानी भरना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आदमी को बदहजमी होती है, उसी प्रकार मिट्टी को भी बदहजमी होती है और मिट्टी को जब बदहजमी होती है तो वह किसान को बर्बाद कर देती है। वह मिट्टी बीज उगाने के लायक नहीं रहती है। मेरा अनुरोध है कि हम चाहे हम किसी भी पार्टी के विधायक हों। मैं किसी एक आदमी पर

दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हम सभी माननीय सदस्यगण राजनीति से ऊपर उठकर फैसले करें और जहां किसान का भला हो, उस काम को करें। मैं इसी क्रम में सिर्फ दो–तीन बातें और बताना चाहूंगा। हमारे पास सिंचाई का बहुत बड़ा संकट यह है कि एस.वाई.एल. नहर नहीं बनी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे बाद में अपनी बात कह लें। अध्यक्ष महोदय, मैं 10 मिनट में अपनी बात कन्कल्यूड कर दूंगा। दूसरा संकट यह है कि एस.वाई.एल. सम– हाऊ नहीं बन पायी। नरवाना ब्रांच भाखड़ा का पानी लाने के लिए हमारा दूसरा साधन है। यह नरवाना ब्रांच सन् 1954 में बनी थी और उस समय इसकी डिजाईन्ड कैपेसिटी बनी थी तो इसमें 4200 क्यूसिक पानी चल रहा था। अब क्योंकि हमारे पास नरवाना ब्रांच से पानी आता है और इसके अलावा दूसरी जगहों से पानी लाने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं। एस.वाई.एल. नहर पंजाब के एरिया में नहीं बनी। हम नरवाना ब्रांच को रिपेयर करने के लिए बन्द नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से हरियाणा प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा बिना पानी के सूखे के कारण मारा जाएगा। आज की तारीख में स्थिति यह है कि नरवाना ब्रांच में सिर्फ 3400 क्यूसिक पानी चलता है और इससे ज्यादा पानी पंजाब गवर्ननैंट अलाऊ नहीं करती। इसमें से 500 क्यूसिक पानी दिल्ली सरकार का है और मिनिंग देयरबाई हरियाणा का सिर्फ 2900 क्यूसिक पानी इस नरवाना ब्रांच से आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है क्योंकि पानी के मामले में आगे–आगे सारे प्रदेश में क्राईसिज बढ़ेंगे। हमें इसका रास्ता निकालना होगा कि किस प्रकार नरवाना ब्रांच की रिपेयर करवा सकते हैं ? इसके अलावा सरकार ने बिजली के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। यह ठीक है कि राजनीतिक दृष्टि से बिजली विभाग ने जो काम किया है, उसमें कई जगह आलोचनाएं भी होती हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बिजली एक ऐसी सेवा है जो मुफ्तखोरी से नहीं चलयी जा सकती। जब तक उपभोक्ता बिजली के बिल की कीमत नहीं समझेगा तब तक बिजली विभाग ठीक से नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों में मुख्य लोकप्रियता लेने के लिए मुफ्त की बातें बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन आज पंजाब प्रांत की आर्थिक हालत को देखते हैं तब पता चलता है। हमारे हरियाणा प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे बिजली बोर्ड की जो मुफ्त की मानसिकता थी, उसको बाहर निकालने का काम किया गया है। हम इस बात को

भी मानते हैं कि ऐसा करने से कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और लोगों ने यह बात भी कही कि मेरे यहां पर बिजली चोरी के छापे पड़े हैं और बिजली विभाग वाले सख्ती भी कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बिजली विभाग ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे श्री रणजीत सिंह जी नये बिजली मंत्री बने हैं। मैंने इनसे बिजली से संबंधित विषय पर बात भी की थी। मैं सदन के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि ये जनता दरबार लगाकर के लोगों को बिजली बिल भरने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से निवेदन है कि जो बड़े–बड़े उपभोक्ता हैं, पहले उनका ऑडिट करवाएं ताकि प्रदेश में हो रही बिजली की चोरी का पता चल सके। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए और सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हैल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में एक आधारभूत ढांचा तैयार करने का काम किया है और इसके लिए सरकार ने नई पॉलिसी भी बनाई है और इसके साथ ही साथ नये कॉलेजिज और नये मैडीकल कॉलेजिज खोलने का प्रोसैस भी चल रहे हैं। अभी हमारी माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी कह रही थी कि प्रदेश में सभी मैडीकल कॉलेज हवा में चल रहे हैं और धरातल पर असली काम नहीं हो पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि अपना कीमती समय निकालकर के हमारे नारनौल विधान सभा क्षेत्र में आयें तो इनको वहां पर मैडीकल कॉलेज का काम बहुत अच्छी तरह से चलता हुआ दिखाई देगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी से कहना चाहती हूं कि पिछले पांच सालों में भिवानी जिले में मैडीकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और वहां पर सरकार की तरफ से अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई है।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि नारनौल विधान सभा क्षेत्र भी इनका ही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी ढाणियों में भी रहती है और बिजली विभाग द्वारा ढाणियों में भी बिजली की सप्लाई की जा रही है। हमारी सरकार ने ढाणियों में पैट ट्रांसफार्मर्ज लगाकर ढाणियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को सिंग्ल फेस की बिजली देने का काम शुरू किया था लेकिन अभी सभी फीडर्ज पर पैट ट्रांसफार्मर्ज नहीं लगे हैं

इसलिए मेरा बिजली मंत्री जी से निवेदन है कि पैट ट्रांसफार्मर्ज ज्यादा से ज्यादा फीडर्ज पर लगाये जायें ताकि ढाणियों में बिजली की सप्लाई की जा सके। अध्यक्ष महोदय, आज यानी 21वीं सदी में भी हमारे प्रदेश के बच्चे रात को लालटेन लेकर पढ़ेंगे तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी पैट ट्रांसफार्मर्ज के लिए ऑर्डर कर दिये हैं।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने पिछले 5 सालों में प्रदेश में जो रोड तैयार किए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छे रोड बनाये हैं और हमारी सरकार ने यह बहुत सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने नैशनल हाईवे का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का काम किया है और विशेषकर हमारे दक्षिणी हरियाणा में देखेंगे तो 6 लेन के रोड और 4 लेन के रोड जिस स्पीड से बनने लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये दो तीन सालों में बनकर कंपलीट हो जाएंगे। जब आप नारनौल जाएंगें तो नारनौल को पहचान नहीं पाएंगें कि ये वही नारनौल है। इस प्रकार से रोड्ज पर भी बहुत काम हो रहे हैं। मैं एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जिन रोड्ज की हालत खराब हो चुकी है। जैसे आजकल कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति में अंतर और भेदभाव होता है तो इस अंतर और भेदभाव को पहचानने में कई बार नुकसान भी हो जाता है। मैं इस महान सदन में एक छोटी से बात कहना चाहता हूं। मैं यह बात किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के खिलाफ नहीं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2014 में चुनाव से पहले गोहाना में एक रैली की थी, उस रैली में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बसों को भर–भर कर ले गये थे। जब ये लोग नारनौल, दादरी और रोहतक की टूटी हुई सड़कों से उनको ले गये थे और जब इन लोगों को वापिस घर छोड़ा गया तो लोग कहने लगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जब आप सबका साथ और सबका विश्वास करोगे तो लोगों में हार्ट बर्निंग नहीं होगी और लोग नाराज भी नहीं होंगे इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम सभी को मिलकर और सभी पुरानी बातें भूलकर एक जुट होकर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा विपक्ष के

माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने–अपने सकारात्मक सुझाव भी सदन में जरूर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि सिर्फ 5 साल आलोचना करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब जोगी राम सिहाग, विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, डॉ. अभय सिंह यादव जी ने जो सदन में गलत बातें कही है उनका कौन जवाब देगा? Dr. Abhe Singh Yadav is supporting Governor's Address. माननीय सदस्य के पास कोई डाटा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बतायें कि सरकार ने पावर जनरेशन कितनी की है और कौन सा नया प्लांट लगाया है।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, जब आप अपनी बात सदन में रखेंगे तब आप इन बातों को ठीक कर देना। प्लीज आप बैठ जायें।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई माननीय सदस्य हाउस में गलतब्यानी कर रहा है और डाटा के अनुसार नहीं बोल रहा है तो उसका जवाब कौन देगा?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा उस समय आपको जिन बातों पर संदेह है उनको क्लीयर कर देना। (शोर एवं व्यवधान) अभी आप कृपया करके बैठ जायें। अब श्री जोगी राम सिहाग जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायें और हाउस की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री बतरा जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी थर्मल पॉवर प्लांट में रेड की और उसमें 4 एस.ई., तीन चीफ इंजीनियर और एक फाईनैंशियल डॉयरैक्टर सहित कुल 7 व्यक्तियों को मौके पर पकड़ा और उसके बाद उनके ऊपर थैप्ट के लिए पैनल्टी लगाई गई ताकि लोगों को यह मैसेज दिया जा सके कि हरियाणा में अब बिजली की चोरी को किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं

किया जायेगा। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से श्री भारत भूषण बतरा जी से रिकवैस्ट है कि भविष्य में वे जब भी बोलें तो तथ्यों पर आधारित जानकारी के आधार पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, Hon'ble Minister should speak on facts but the Member, who is supporting the Governor's Address and who is speaking on behalf of the Government, he must come with the data.

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, कृपया आप बैठें और जोगी राम सिहाग जी को बोलने दें।

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय जी, मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव, विधायक द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं 14वीं हरियाणा विधान सभा के प्रथम बजट सत्र में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हम सभी हरियाणा की जनता के कल्याण हेतु रचनात्मक और उपयोगी विचार–विमर्श करेंगे। जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है। चाहे वह पिछली सरकार है या चाहे वर्तमान सरकार है प्रदेश को एक अच्छा माहौल देने का काम किया है। अच्छे माहौल की वजह से प्रदेश ने चहुंमुखी विकास किया है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसी पैटर्न पर चलते हुए वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार सुशासन की नई–नई पहलों और सभी विभागों द्वारा राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करने पर वर्ष भर बल देगी। मेरा विश्वास है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके सहजता से सरकारी सेवाएं मिलने के फलस्वरूप ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। आगामी सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसम्बर, 2020 को हमारी सरकार ऐसी पहलों पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगी और अनुकरणीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों को सम्मानित भी किया जाएगा। उपाध्यक्ष जी, मुझे यह कहते अति हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार नये जनादेश के साथ सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्यरत है। मार्केटिंग सीजन 2019–20 के दौरान 6 लाख 19 हजार मीट्रिक टन सरसों की रिकार्ड खरीद की गई। पिछली सरकारों द्वारा इस प्रकार की खरीद कभी भी नहीं की गई। इसके अलावा 13 हजार 156 मीट्रिक टन

सूरजमुखी की खरीद भी की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की पूरी राशि किसानों के खातों में सीधे जमा करवाई गई। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए हरियाणा को 02 जनवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रशस्ति पुरस्कार (कृषि कर्मण अवार्ड) प्रदान किया गया। जो हम सभी के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है और यह प्रशंसा पत्र यह दर्शाता है कि इससे हमारी हौंसला अफजाई होती है। आज हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसके लिए हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अब किसानों के लिए मार्केटिंग का समय है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज के सत्र में जो भी चर्चा की जाए वह किसानों को किस प्रकार से सुविधाएं दी जाएं, किस प्रकार से उनकी आदमनी बढ़ाई जाए, उस पर चर्चा की जाए। इसी प्रकार से हमारी सरकार किसानों को बागवानी की मुख्य फसलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार में उपज के भाव कम होने की स्थिति में हरियाणा सरकार द्वारा "भावांतर भरपाई योजना" के तहत किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। किसानों की फसल के मूल्य के मुकाबले ज्यादा खर्च हो जाता था इसलिए उनके भाव के अन्तर के लिए भावांतर भरपाई योजना सरकार ने चालू की है, यह सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। आज हरियाणा सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से अच्छा माहौल बनाती है उसको और आगे बढ़ाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण के दौरान जिन नौजवानों तथा बुजुर्गों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सभी मुकदमों को तुरन्त वापिस लेकर माहौल को और अच्छा बनाने का कार्य सरकार करे। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> "कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :–
>
> > "कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने

दिनांक 20 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है'।"

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रजातंत्र की नीति और प्रणाली रही है कि सरकार के पूर्व में किए हुए कार्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में उसका क्या विजन है, उसको माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण के माध्यम से सदन के पटल पर रखते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने चौदहवीं हरियाणा विधान सभा के इस बजट सत्र में अपने अभिभाषण में बहुत सारी बातें सरकार के आधार पर कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार सुशासन की नई–नई पहलों और सभी विभागों द्वारा राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करने पर वर्ष भर बल देगी। मेरा विश्वास है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके सहजता से सरकारी सेवाएं मिलने के फलस्वरूप ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, ईज़ ऑफ लिविंग तो जब होता है जब शिक्षा, चिकित्सा, भोजन और साधन सब कुछ उपलब्ध रहता है। जिस तरह की नीति और जिस तरह की योजनाएं आज दर्शाई गई हैं उस पर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से काम करने की बात सरकार की रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश कृषि प्रधान रहा है। हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि there is no culture except agriculture इसीलिए हरियाणा प्रदेश में गेहूं, सरसों, धान और गन्ने की फसल पैदा की जाती है और बेची जाती है। अभी डॉ. अभय सिंह यादव जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार ने एम.एस. पी. पर गेहूं और धान खरीदा है और किसानों को उनका समय पर भुगतान किया है। मैं गारन्टी से कह सकता हूं कि सरकार आज भी धान और गेहूं के बारे में ब्यौरा ले ले, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि आज भी किसानों का 35 लाख रुपया सरकार की तरफ बकाया है। इससे पता चलता है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदय, –– (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : महिपाल जी, प्लीज आप बैठिये। दान सिंह जी, आप अपनी बात रखिये।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी भी किसान से पूछ लें कि उनका कोपरेटिव मिलों के अन्दर गन्ने का कितना पैसा बकाया पड़ा हुआ है। यह किसान के साथ अन्याय है।

मोहम्मद इलियास : उपाध्यक्ष महोदय, ––

श्री उपाध्यक्ष : इलियास जी, प्लीज आप बैठिये, आपकी पार्टी के सदस्य ही बोल रहे हैं। आप प्लीज बैठिये।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद सरकार ने कहा 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा।' जिसमें किसान को अपनी फसल का पूरा ब्यौरा डिजिटलीकरण के माध्यम से देना पड़ता है। पहली दिक्कत तो यह है कि सभी जगह इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि किसान को फॉर्म भरना नहीं आता है और उसे दूसरे आदमी की सहायता लेनी पड़ती है जिसका परिणाम यह होता है कि किसान जो चाहता है वह उसको नहीं मिल पाता है। यह सरकार की नाकामयाबी है उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले भी कहा गया है कि भावान्तर भरपाई योजना से शिकायत है। भावान्तर भरपाई योजना हकीकत में वो होनी चाहिए जो किसान की लागत है और किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यह किसान के साथ भी धोखा है और उपभोक्ता के साथ भी धोखा है। इसमें अगर फसल की असली कीमत पूछकर, उसकी समीक्षा करके उस फसल का भाव दिया जाता है तो हम मान सकते हैं कि सरकार सही में भावान्तर भरपाई का कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बात करना चाहता हूं सरकार के आने वाले हैल्थ सोयल टेस्टिंग के बारे में सरकार ने कहा है कि सरकार इसके लिए लैबोरेट्री बनाएगी। यह हम भी मानते हैं कि विधिवत रूप से जो हमारी संचारित फसल हैं उनके साथ फसलों का विविधीकरण होना चाहिए लेकिन जितनी भी योजनाओं और लैब्स के बारे में जिक्र किया गया है हकीकत में इस तरह की कोई लैब प्रदेश के अन्दर या किसी क्षेत्र के अन्दर काम नहीं कर रही है जिस तरह से सरकार ने उनको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनुमोदित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कोपरेटिव सोसायटी और लैंड मोरगेज बैंक्स का सवाल आता है। एक समय था कि जब किसान को किसी ऋण की जरूरत

पड़ती थी तो वह किसान कोपरेटिव बैंक या लैंड मोरगेज बैंक में चला जाता था लेकिन आज किसान जब इन बैंक्स में जाता है तो बैंक मैनेजर का जवाब मिलता है कि हमारे पास देने के लिए धन नहीं है और अगर धन मिलता है तो इस शर्त पर कि वह पुराने लोन की भरपाई करके आदान–प्रदान करके नया लोन देकर किया जाता है। ऐसा करके सरकार किसानों से श्रय लेने का प्रयास कर रही है कि हमने पुराने कर्जे को माफ कर दिया और हमने उनको नये ऋण दे दिये हैं लेकिन हकीकत इनसे विपरीत है। आप यह स्वयं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर देख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पशुधन का सवाल आया है। देखिये किसान के पास कृषि के बाद एक पशुधन ही ऐसा होता है जिससे किसान अपनी आजीविका चलाता है। आज अचानक पशु के अन्दर कोई बीमारी आ जाती है तो उसके उपचार के लिए सरकार को जितने साधन मुहैया करवाने चाहिएं, जितने पशुचिकित्सा होस्पिटल्ज बनाने चाहिए, जितनी लैबोरेट्रीज खोलनी चाहिएं वे नहीं हैं। उनके लिए सरकार को निश्चित तौर पर प्रयास करके किसान की इस ज्यादा से ज्यादा परेशानी को मिटाने का काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश दूध के मसले में पूरे हिन्दुस्तान में दूसरे स्थान पर है लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई चिन्ता है तो वह दूध उत्पादन की है क्योंकि जितने भी कैंसर रोगी हैं उनमें कहा जाता है कि ज्यादातर बिमारियां दूध के कारण आती हैं। जितना हम दूध पैदा करते हैं उसमें बहुत सारी मिलावट देखी गई है। पीछे पंजाब के अन्दर एक सर्वे किया गया था। अचानक उन डेरियों पर दौरा किया गया और वहां पर छापे मारने के बाद पता लगा कि उनके 100 में से 29 सैम्पल फेल हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार भी यह देखे कि हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान में दूसरे स्थान पर तो आया है लेकिन उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिलावटी दूध सप्लाई कर रहे हों और जिस तरह से आज कैंसर की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा एक भयानक बीमारी का रूप लेती जा रही है इस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं इतना कह सकता हूँ कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्ज के संदर्भ में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ई–वेईंग मशीनों के बारे में कहा गया है और इन मशीनों को सरकार ने लगाया भी है लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन मशीनों का उपयोग हो भी रहा है या नहीं, यह देखने वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत व सच्चाई कुछ और है लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वे कुछ और हैं और इन बातों को

सिर्फ कागजी कार्रवाई कह दे तो कोई गलत बात नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा जो चीज बताने की कोशिश कर रही है, हकीकत में वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी डॉ. अभय सिंह यादव जी ने समान पानी के वितरण की एक बात कही थी। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक प्रदेश में अनेकों सरकारें आई और चली गई, कितने ही मंत्री आये और चले गए तथा कितने ही मुख्यमंत्री आये और चले गए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बहुत ही कम ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने पूरी सच्चाई के साथ हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र में पानी देने का प्रयास किया है। माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी सदन में बैठे हैं इन्होंने तथा चौधरी बंसी लाल जी ने प्रदेश में हर टेल तक पानी पहुंचाने के अथक प्रयास किए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई चुनाव आता है तो पानी के विषय को चुनावी मुद्दा बनाकर तरह–तरह की घोषणायें चुनावों से पहले की जाती हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद भी नहरों के संदर्भ में प्रदेश हित में कुछ करके नहीं दिखाया है बल्कि जो नहर बनाई जा रही थी उनके प्रति भी उदासीनता का ही व्यवहार अपनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एलायंस से सरकार बनी थी। अगर सरकार की मंशा होती तो हरियाणा में आज पानी की कमी नहीं होती। हमारे किसान और जवान दोनों बहुत परिश्रमी हैं। देश की किसी भी लड़ाई की बात करें चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो या फिर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी सर्विस की ही बात क्यों न हो, इन सबमें जब भी शहीदों का नाम आता है तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र का नाम जरूर आता है क्योंकि हम अपने खून से इतिहास लिखना जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की सूखी धरती पर रहने वाले लोग पानी की एक–एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। हमने इस दिशा में अनेक प्रयास किए थे। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास यह भी था कि जब तक एस.वाई.एल. नहर बने तब तक हांसी–बुटाना लिंक नहर के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो एस.वाई.एल. नहर तथा हांसी–बुटाना लिंक नहर के विषय को इस प्रकार से अलग करके रख दिया है कि मानों प्रदेश व मेरे क्षेत्र को पानी की कोई जरूरत ही न हो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के लोगों को हर बार यही आश्वासन मिलता है कि पानी आयेगा, जरूर आयेगा

और अब तो मैं भी इस बात को मानने लगा हूँ कि पानी आयेगा और जरूर आयेगा लेकिन यह पानी हमारे खेतों में नहीं बल्कि हमारी आंखों में आयेगा। इस प्रकार का कार्य यह सरकार हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ करने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देने की बात कही गई है लेकिन आज पीने के पानी के विषय में भी एक अलग तरह की समस्या हमारे सामने आ रही है और यह समस्या इस रूप में है कि जैसे आज गांव–गांव तथा शहर–शहर साफ पानी के लिए आर.ओज. का प्रावधान किया गया है लेकिन यह बात सुनने व देखने में आ रही है कि आर.ओज. के पानी को ठंडा रखने के लिए पानी में फर्टीलाइजर अर्थात यूरिया का प्रयोग किया जाता है जोकि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बात को जरूर चैक किया जाये कि आर.ओज. के पानी में यूरिया डाला जा रहा है या नहीं। अगर यूरिया डाला जा रहा है तो निःसंदेह यह स्वास्थ्य के लिए 100 प्रतिशत हानिकारक सिद्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वे भी मेरी बात पर निश्चित रूप से गौर फरमायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं बिजली के विषय पर अपनी बात रखूंगा। अभी थोड़ी देर पहले बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी तथा माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी जगमग योजना की बात कहते हुए गांव व शहरों को चमकाने की बात कह रहे थे लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि जब मौजूदा सरकार ने बिजली की एक भी यूनिट पैदा करने का प्रोजैक्ट नहीं लगाया तो कैसे सरकार जगमग योजना के तहत गांवों व शहरों को चमकाने की बात कर रही है। जब कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं लगा तो बताओ कि पॉवर जैनरेशन कहां से होगी और किस प्रकार जगमग योजना शुरू करेंगे यह सदन में जरूर बताया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में पॉवर प्रोजैक्ट्स लगाये गए थे उसके बाद कोई भी पॉवर प्रोजेक्ट लगाया गया हो तो बतायें? उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार द्वारा कहे जाने वाले दूसरे विकास कार्यो की भी पृष्ठभूमि के बारे में बताता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के सभी गांवों में बिजली आ रही है क्या यह इन लोगों को दिखाई नहीं देता? पहले जब विपक्ष के साथियों की सरकार सत्ता में थी, तब बिजली लोगों को क्यों नहीं मिल पाती थी, यह बात सदन

में बताने की है? इस तरह की बातें करके सदन को बरगलाया नहीं जा सकता। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, आपने माननीय दान सिंह जी को बोलने का समय दिया लेकिन सत्ता पक्ष के एक सदस्य श्री असीम गोयल जी बोलने में बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन्हें बिठाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लोगों को बिजली मिल रही है यह सोलर एनर्जी से प्राप्त की जा रही है और इस सोलर एनर्जी से प्राप्त बिजली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई योगदान नहीं है बल्कि हमारी सरकार के समय में हमने हर मकान मालिक के लिए सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने को मैंडेटरी किया था और इसी प्रकार वाटर कंजर्वेशन प्लांट को भी हमने मैंडेटरी किया था। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली ज्यादा और सस्ते रेटों पर दी जा रही है। यह बात भी इनको सदन में जरूर बतानी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भाकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में बहुत महंगी बिजली दी जा रही है।।(विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयः शकुंतला जी, प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, जब अभय सिंह यादव जी बोल रहे थे तो हमारी पार्टी के सदस्यों की तरफ से उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया गया। अब यदि हमारा कोई सदस्य अपनी बात रख रहा है तो उन्हें भी अपनी बात रखने दी जानी चाहिए। किसी भी सदस्य को बीच में उठकर इन्हें बाधित करना ठीक नहीं है। अगर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने यह फैसला कर ही लिया है कि वे कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य को बोलने नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, हम नहीं बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, प्लीज आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार कह रही है कि प्रदेश में प्रॉपर बिजली दी जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि ये किस आधार पर बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार के समय में गुजरात के खेड़ी मुन्दड़ा में जो अडानी के बिजली के प्लांट लगे हुए थे उसे 1440 मेगावाट बिजली का पी0पी0ए0 किया गया था और वहां से सीधी वी.सी. लाइन से हमारे क्षेत्र में बिजली आती थी। उस बिजली प्लांट की कैपेसिटी 2500 मेगावाट की है। आज के दिन सरकार वहां से फालतू बिजली बॉरो कर रही है और यह इसलिए संभव हो रहा है कि उनसे पी0पी0ए0 हमारे समय में किया गया था और मौजूदा सरकार ने अपने खुद के जनरेटिंग प्लांट बंद किए हुए हैं क्योंकि उनसे बिजली का उत्पादन महँगा पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय में किया गया बिजली का एग्रीमैंट सस्ता पड़ता है। उस प्रोसैस में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का हाथ था क्योंकि उन्होंने हरियाणा प्रदेश को सस्ती बिजली देने का काम किया था। उसके बाद जनरेशन पॉवर और बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के समय में यह मैंडेटरी किया हुआ था कि जो व्यक्ति 500 गज का या इससे अधिक जगह पर मकान बनायेगा तो मकान के ऊपर सोलर सिस्टम लगायेगा और नीचे वॉटर कन्जर्वेशन सिस्टम बनायेगा ताकि पानी के लैवल में भी सुधार हो। यह सारा का सारा मैंडेटरी हमारी सरकार के समय में किया गया था। इस प्रोसैस में मौजूदा सरकार का कोई भी योगदान नहीं है और न ही कोई मौजूदा सरकार ने एक यूनिट बिजली पैदा की है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' के संबंध में आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है क्योंकि बाहर की कम्पनियां हरियाणा में सुविधाएं देखकर निवेश करने के लिए आती हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इनके समय में कितनी कम्पनियां बाहर से हरियाणा में निवेश करने के लिए आई हैं? कितने रुपये की एफ.डी.आई. हुई है और हमारे समय में 2 लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यूज. हुए थे और उनमें से 59 हजार करोड़ रुपये एम.ओ.यूज. के माध्यम से हरियाणा में एफ.डी.आई. आई थी। मौजूदा सरकार में 6 लाख 28 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यूज. किए गए थे बतौर इसके लिए 'हैपनिंग हरियाणा' के नाम से इवेंट प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि 6.28 लाख करोड़ रुपये में से कितने करोड़ रुपये की एफ.डी.आई. हरियाणा में आई यह भी सदन को बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जी.एस.टी. के संबंध में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन थी लेकिन इसको लेकर पहले भाजपा के बड़े नेतागण विरोध कर रहे थे। अब जी.एस.टी. लागू हो गई है। हमें पता है कि जी.एस.टी. कंज्यूमिंग स्टेट्स जैसे दिल्ली, गोवा आदि के लिए कारगर साबित हुआ है लेकिन हरियाणा जैसे स्टेट के लिए नहीं क्योंकि यहां मैन्यूफैक्चरिंग है। हमें इस संबंध में आश्वासन दिया गया था कि कम्पनसेशन दिया जायेगा लेकिन आज भी कम्पनसेशन पूरा नहीं दिया जा रहा है। सरकार के पास पैसा कहां से आयेगा? क्योंकि मौजूदा सरकार कर्जा लेकर चल रही है। वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2014 तक हरियाणा के ऊपर कितना कर्जा था और वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक कितना कर्जा और चढ़ गया है इस बात का अनुमान सरकार स्वयं लगा सकती है कि उसकी मानसिक और आर्थिक स्थिति क्या है? यही बातें मैं निश्चित तौर पर सरकार को बताना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद खनन की भी बात सदन में आई थी।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आपके पास बोलने के लिए 15 मिनट का समय था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिस्से का समय भी राव दान सिंह को दे दिया जाये।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मैडिकल कॉलेज के बारे में सदन से कहना चाहता हूँ। कई माननीय सदस्यों जैसे श्रीमती निर्मला रानी, श्री लीला राम गुर्जर जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विकास के काम के नाम पर केवल घोषणाएं ही की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषणा नहीं बल्कि लोगों के लिए विकास के काम करके दिखाए हैं। हमारे समय में मेरे क्षेत्र में भी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी में मैडिकल कॉलेज बनना था लेकिन वह भाजपा सरकार ने नहीं बनने दिया। यह बात मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ। सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी में मैडिकल कॉलेज डिक्लेयर हुआ और नहीं बनाया गया, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों नहीं बनाया गया। जहां तक सड़कों की बात है, एन0एच.–71 किसने बनाया है। नार्थ–साउथ कॉरीडोर किसने बनाया है। एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का प्रोविजन किस सरकार में हुआ है। गुरूग्राम से दिल्ली व बहादुरगढ़ से दिल्ली मैट्रो जोड़ने का काम किस सरकार

में हुआ था। दिल्ली से फरीदाबाद मैट्रो का इन्फ्रास्ट्रक्चर किसने बढ़ाया था। ये सारे के सारे विकास के काम कांग्रेस पार्टी के समय हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए थे उससे आगे भाजपा सरकार ने एक पिल्लर भी नहीं बढ़ाया है और यदि कुछ आगे बढ़ाया है तो वह अवैध खनन का कार्य जरूर बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि हमारी सरकार के समय में खनन पर रोक होने के बावजूद भी हमने प्रदेश में विकास कार्य तेजी से करवाएं थे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कॉलेज, वुमन कॉलेज या को–एड कॉलेज चले या न चले अलग बात है लेकिन इनको चलाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारा इलाका किसान के साथ–साथ जवान का भी है। हमारे इलाके में दो व्यवस्थाएं थी। एक सैनिक स्कूल हमारे रेवाड़ी के पाली में बना था।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार कह रही है कि प्रदेश में प्रॉपर बिजली दी जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि ये किस आधार पर बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार के समय में गुजरात के खेड़ी मुन्दड़ा में जो अडानी के बिजली के प्लांट लगे हुए थे उसे 1440 मेगावाट बिजली का पी0पी0ए0 किया गया था और वहां से सीधी वी.सी. लाइन से हमारे क्षेत्र में बिजली आती थी। उस बिजली प्लांट की कैपेसिटी 2500 मेगावाट की है। आज के दिन सरकार वहां से फालतू बिजली बॉरो कर रही है और यह इसलिए संभव हो रहा है कि उनसे पी0पी0ए0 हमारे समय में किया गया था और मौजूदा सरकार ने अपने खुद के जनरेटिंग प्लांट बंद किए हुए हैं क्योंकि उनसे बिजली का उत्पादन महँगा पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय में किया गया बिजली का एग्रीमैंट सस्ता पड़ता है। उस प्रोसैस में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का हाथ था क्योंकि उन्होंने हरियाणा प्रदेश को सस्ती बिजली देने का काम किया था। उसके बाद जनरेशन पॉवर और बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के समय में यह मैंडेटरी किया हुआ था कि जो व्यक्ति 500 गज का या इससे अधिक जगह पर मकान बनायेगा तो मकान के ऊपर सोलर सिस्टम लगायेगा और नीचे वॉटर कन्जर्वेशन सिस्टम बनायेगा ताकि पानी के लैवल में भी सुधार हो। यह सारा का सारा मैंडेटरी हमारी सरकार के समय में किया गया था। इस प्रोसैस में मौजूदा सरकार का कोई भी योगदान नहीं है और न ही कोई मौजूदा सरकार ने एक यूनिट बिजली पैदा की है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' के संबंध में आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है क्योंकि बाहर की कम्पनियां हरियाणा में

सुविधाएं देखकर निवेश करने के लिए आती हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इनके समय में कितनी कम्पनियां बाहर से हरियाणा में निवेश करने के लिए आई हैं? कितने रुपये की एफ.डी.आई. हुई है और हमारे समय में 2 लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यूज. हुए थे और उनमें से 59 हजार करोड़ रुपये एम.ओ.यूज. के माध्यम से हरियाणा में एफ.डी.आई. आई थी। मौजूदा सरकार में 6 लाख 28 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यूज. किए गए थे बतौर इसके लिए 'हैपनिंग हरियाणा' के नाम से इवेंट प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि 6.28 लाख करोड़ रुपये में से कितने करोड़ रुपये की एफ.डी.आई. हरियाणा में आई यह भी सदन को बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जी.एस.टी. के संबंध में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन थी लेकिन इसको लेकर पहले भाजपा के बड़े नेतागण विरोध कर रहे थे। अब जी.एस.टी. लागू हो गई है। हमें पता है कि जी.एस.टी. कंज्यूमिंग स्टेट्स जैसे दिल्ली, गोवा आदि के लिए कारगर साबित हुआ है लेकिन हरियाणा जैसे स्टेट के लिए नहीं क्योंकि यहां मैन्यूफैक्चरिंग है। हमें इस संबंध में आश्वासन दिया गया था कि कम्पनसेशन दिया जायेगा लेकिन आज भी कम्पनसेशन पूरा नहीं दिया जा रहा है। सरकार के पास पैसा कहां से आयेगा? क्योंकि मौजूदा सरकार कर्जा लेकर चल रही है। वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2014 तक हरियाणा के ऊपर कितना कर्जा था और वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक कितना कर्जा और चढ़ गया है इस बात का अनुमान सरकार स्वयं लगा सकती है कि उसकी मानसिक और आर्थिक स्थिति क्या है? यही बातें मैं निश्चित तौर पर सरकार को बताना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद खनन की भी बात सदन में आई थी।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आपके पास बोलने के लिए 15 मिनट का समय था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिस्से का समय भी राव दान सिंह को दे दिया जाये।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मैडिकल कॉलेज के बारे में सदन से कहना चाहता हूँ। कई माननीय सदस्यों जैसे श्रीमती निर्मला रानी, श्री लीला राम गुर्जर जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विकास के काम के नाम पर

केवल घोषणाएं ही की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषणा नहीं बल्कि लोगों के लिए विकास के काम करके दिखाए हैं। हमारे समय में मेरे क्षेत्र में भी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी में मैडिकल कॉलेज बनना था लेकिन वह भाजपा सरकार ने नहीं बनने दिया। यह बात मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ। सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी में मैडिकल कॉलेज डिक्लेयर हुआ और नहीं बनाया गया, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों नहीं बनाया गया। जहां तक सड़कों की बात है, एन0एच.–71 किसने बनाया है। नार्थ–साउथ कॉरीडोर किसने बनाया है। एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का प्रोविजन किस सरकार में हुआ है। गुरूग्राम से दिल्ली व बहादुरगढ़ से दिल्ली मैट्रो जोड़ने का काम किस सरकार में हुआ था। दिल्ली से फरीदाबाद मैट्रो का इन्फ्रास्ट्रक्चर किसने बढ़ाया था। ये सारे के सारे विकास के काम कांग्रेस पार्टी के समय हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए थे उससे आगे भाजपा सरकार ने एक पिल्लर भी नहीं बढ़ाया है और यदि कुछ आगे बढ़ाया है तो वह अवैध खनन का कार्य जरूर बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि हमारी सरकार के समय में खनन पर रोक होने के बावजूद भी हमने प्रदेश में विकास कार्य तेजी से करवाएं थे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कॉलेज, वुमन कॉलेज या को–एड कॉलेज चले या न चले अलग बात है लेकिन इनको चलाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारा इलाका किसान के साथ–साथ जवान का भी है। हमारे इलाके में दो व्यवस्थाएं थी। एक सैनिक स्कूल हमारे रेवाड़ी के पाली में बना था। उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है लेकिन वह कम्पलीट नहीं हो पा रही है । वहां पर क्लासिज लग रही हैं लेकिन उसमें बच्चे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं । क्या सरकार ने अपने किसी अधिकारी से इस बारे में जानने की कोशिश की है ? दूसरा, गुरूग्राम के बिनोला गांव में एक डिफैंस यूनिवर्सिटी का तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था । उस समय उनके साथ यू.पी.ए. की तत्कालीन चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी उपस्थित थे । देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता नहीं होता है और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी । इस सरकार ने उस यूनिवर्सिटी की केवल चारदीवारी करवाने के अलावा उस पर कोई अन्य कार्य शुरू नहीं किया है । सरकार ने कहा कि हम पाली गांव में एम्स बनाएंगे । मैं समझता हूं कि वह एम्स

अभी तक इधर से उधर बनाने के चक्कर में ही झूल रहा है । इस सरकार की काम करने की शैली इस तरह की है कि कभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंच से तो कभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मंच से कोई नेता किसी काम की घोषणा कर देता है लेकिन वह काम किया नहीं जाता है । एम्स बनाने का काम आज भी लटका हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में पंचायती राज के द्यौतक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे । उन्होंने पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों आदि को बनाया था । उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कह रही है कि के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के साथ रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, उससे गांवों–शहरों को जोड़ेंगे इत्यादि । यह एक अच्छी शुरूआत है लेकिन यह काम हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ था । हमारी सरकार के समय में इसका लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था । आपके समय में एक्सप्रैस–वे के जिस पॉर्शन का निर्माण हुआ था उस पर बहुत ज्यादा एक्सीडैंट्स हुए हैं । सरकार चाहे तो इसका रिकॉर्ड निकालकर देख ले । इन एक्सीडैंट्स का कारण यह है कि इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंफीरियर है । वृद्धावस्था पैंशन पूर्व उप–प्रधानमंत्री श्री देवीलाल ने शुरू की थी और उस राशि को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था । अब भी हमने कहा था कि हम अपनी पार्टी की सरकार आने पर वृद्धावस्था पैंशन 5100 रूपये प्रति माह करेंगे । इसी तरह इस सरकार में एक सहयोगी दल ने भी वृद्धावस्था पैंशन बढ़ाने की बात कही थी और भाजपा ने भी कहा था कि वे वृद्धावस्था पैंशन 3100 रूपये कर देंगे लेकिन इस सरकार ने पैंशन सिर्फ 250 रूपये बढ़ाई है । ऐसा करके इस सरकार ने बुजुर्गों के साथ अन्याय किया है । यह सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की बात करती है। इसी नाते इस सरकार ने नई ऐक्साइज नीति बनाई है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ 1000 रूपये में लाइसैंस लेकर 2 पेटी शराब और 2 पेटी बीयर की बेच सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों के कहने पर हम शराब के ठेके को उस जगह से हटा लेंगे और दूसरी तरफ ये हर व्यक्ति को 1000 रूपये में शराब बेचने का लाइसैंस दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकारों में तो 10 हजार रूपये में लाइफटाइम के लिए शराब बेचने का लाइसैंस दिया जाता था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर चुप बैठे हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि हम इनकी फालतू बात भी सुनते रहेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बैठ जाइये ।

17:00 बजे

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार के समय में दिल्ली को करनाल, मेरठ, अलवर से रैपिड मैट्रो के थ्रू जोड़ा जाना था लेकिन वह काम आज भी लटका हुआ है । इसके अलावा दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) का काम भी अधर में लटका हुआ है । माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह जी भी यहां पर बैठे हैं। सरकार द्वारा लोजिस्टिक हब के नाम पर 1,000 एकड़ जमीन इकट्ठी करवायी गयी, लेकिन वह काम अभी भी अधर में लटका हुआ है और वहां पर लोजिस्टिक हब नहीं बना है। (शोर एवं व्यवधान) यह सरकार की कार्य प्रणाली है कि सरकार किस तरह से, किस तेजी से और किस निपुणता से काम करना चाहती है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर बात की है, इसलिए मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिर्फ शिलान्यास किया है और कुछ नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय सदस्य राव दान सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं।

डॉ0 अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर बात की गयी है, इसलिए मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उसके बाद माननीय सदस्य अपनी बात रख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। सरकार के माननीय सदस्य इसके बारे में फैसला कर लें कि अगर सरकार के माननीय सदस्य हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों के बोलने के टाईम पर बीच में बोलकर समय खराब करेंगे तो हम भी इनके समय में अपनी बात रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम आपकी इजाजत के बगैर कोई बात रखते हैं ? (शोर एवं व्यवधान) हमारी पार्टी के माननीय सदस्यगण आपकी इजाजत के बैगर नहीं बोलते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष के माननीय सदस्य गलत बात कहेंगे तो हम उस बात को नहीं सुनेंगे। हम वाक आऊट करेंगे।

डॉ0 अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी इजाजत के बैगर कोई बात नहीं कहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। जब माननीय मुख्य मंत्री/माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, तब इनकी बातों का जवाब आ जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य जो बोलेंगे, उसका जवाब दे देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के माननीय सदस्यगण आपकी इजाजत के बिना बोल रहे हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर बात कही है, इसलिए मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब माननीय सदस्य बाद में दे दें। माननीय सदस्य ने भी ऐसी बहुत सी बातें कही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। बीच में कोई भी माननीय सदस्य न बोले।

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तराः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बत्तरा जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। आपकी पार्टी के ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री भारत भूषण बत्तराः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के माननीय सदस्य बीच में ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्वायंट ऑफ ऑर्डर में पर्सनल पॉजीशन एक्सपलेन नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान) He cannot explain his personal position.

श्री उपाध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी मैम्बर का नाम लेकर कुछ कहा जाए तो वह मैम्बर अपनी बात रख सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बाद में अपनी बात कह सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण चेयर की इजाजत लेकर अपनी बात रख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी यही बात कही है कि माननीय सदस्यगण आपकी इजाजत से बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपकी इजाजत नहीं ली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण आपकी इजाजत से ही बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तराः उपाध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ ऑर्डर में पर्सनल पॉजीशन एक्सपलेन करने की इजाजत नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बत्तरा जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, क्या बत्तरा जी ने आपसे बोलने की इजाजत ली है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : महीपाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात का जवाब दूंगा। माननीय सदस्य ने अभी लोजिस्टिक हब की बात की है, उसके लिए 1,000 एकड़ लैंड एक्वायर की जा चुकी है। इसके लिए फोरलेन रोड नांगल चौधरी से लोजिस्टिक हब तक बन चुका है। इसके अतिरिक्त 8 किलोमीटर का रोड जो एन.एच–48बी से मिलाना है, उसका टैंडर प्रोसैस में है। इस पर काम चल रहा है। इसके बीच में कुछ लोगों की जमीन है जिसके कंसालिडेशन का काम चल रहा है और यह काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अपनी कल्पनाओं की बात है। इसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो भी सरकार होती है। वह लम्बी अवधि के प्रोग्राम बनाती है, लेकिन उनके खाते में वही काम जाते हैं जो उनके टाईम में किये जाते हैं। मान लीजिए, हमने योजना बना ली कि हम महेन्द्रगढ में कॉलेज खोलेंगे

और आगे कुछ नहीं करेंगे तो योजना बनाने से क्या लाभ होगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः डॉ0 साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में जिन कार्यों के करने के फित्ते काटे हैं, वे इनके खाते में कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह यादव जी ने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया था उस समय उन्होंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में सभी सरकारों ने काम किये हैं।

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात कन्कल्यूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्षः राव साहब, आपको अपनी बात रखते हुए काफी समय हो गया है। दूसरे मैम्बर्ज भी अपनी बात रखेंगे। कृपा, आप जल्दी कन्कल्यूड करें।

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंत में नशे की आदत के मसले को 'एंटी नारकोटिक्स विंग' में लेकर ठीक करने की बात कही गई है। यह बात सत्य है कि आज नशे ने पूरे पंजाब को ग्रस्त कर रखा है और मैं कह सकता हूं कि वे बड़ी संख्या में नशे की लत से परेशान हैं। यह बीमारी धीरे–धीरे हरियाणा प्रदेश और राजस्थान की तरफ भी बढ़ रही है। यह एक चिन्ता का विषय है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया है। इसमें हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। हम लोग केवल आलोचना के लिए नहीं है बल्कि विपक्ष में होने के नाते हम सही काम की प्रशंसा और गलत काम की आलोचना करते हैं। नशे की एक ऐसी आदत है, जिससे इंसान का जीवन बदल जाता है। एक बच्चा जो जवानी में प्रदार्पण करता है, उसका जीवन बिगड़ सकता है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसको रोकने के लिए सरकार जितने भी कार्य करे, उतने कम हैं। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने नारा दिया है मैं समझता हूं कि वह सिर्फ एक नारा है कि ''हरियाणा एक हरियाणवी एक''। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि अगर हम ''भारत एक भारतीय एक'' का नारा लगायें तो इस देश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ''आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस बारे में अभी भी सोच लो क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता महान है, वह सब कुछ देख रही है और सब कुछ जानती भी है।

''चेहरे की हंसी से गम को भुला दो,

कम बोलो पर सब कुछ बता दो।

खुद ना रुठों पर सब को हंसा दो,

यही राज है ज़िंदगी का, कि जियो और जीना सिखा दो''। जय हिन्द।

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) (अ.जा.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने वर्ष 2020 में एक सुशासन वर्ष मनाने का संकल्प लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकारों के समय में प्रदेश के लोगों को मूलभूत संविधाएं नहीं मिलती थी, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जैसे किसी व्यक्ति ने अपना लाइसैंस बनवाना हो या एस.सी. कैटगरी का सर्टिफिकेट इत्यादि बनवाना हो तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब हमारी सरकार ने इन सभी सुविधाओं को ऑन–लाइन कर दिया है जो कि मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सरहानीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के समय में सरसों की फसल को बेचने में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन इस बार वर्तमान सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी बना करके सरसों की फसल की खरीद की है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फतेहाबाद जिले से श्री दूड़ा राम जी सदन में बैठे हैं। फतेहाबाद जिले में सरसों की काफी अच्छी फसल होती है और यहां के किसानों को इस बात का पूरा फायदा भी मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में यह बात भी बताना चाहूंगा कि ''किसान पंजीकरण पोर्टल (मेरी फसल मेरा ब्यौरा) के माध्यम से अपनी फसल बेचने में किसानों को पूरा फायदा मिला है। इस माध्यम से चालू रबी सीजन में अब तक 6 लाख 40 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया है। सरकार ने ''भावांतर भरपाई योजना'' प्रदेश में शुरू की है। उसके तहत किसानों

को बाहर नई सब्जियों जैसे गाजर, मटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिण्डी, मिर्च, घीया, करेला, हल्दी, बंदगोभी, मूली, लहसुन तथा तीन फलों अमरूद, आम और किन्नू को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि इससे किसानों की आय बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से पर्यावरण सुरक्षा के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। मेरे क्षेत्र में भी धान की काफी अच्छी फसल होती है। उपाध्यक्ष महोदय, फसल अवशेषों के स्थान पर ही प्रबंधन के लिए काफी किसानों को अनुदान पर उपकरण प्रदान किए गए हैं। मैं समझता हूं कि इन उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी बढ़ाई जाये क्योंकि एक मशीन की कीमत 14 लाख रुपये तक की है और ट्रैक्टर की कीमत अलग से है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले ऐसे किसानों, जो ऋण की अदायगी न करने के कारण डिफाल्टर हो गये थे, उन्हें बड़ी राहत पहुंचाने के लिए पहली सितम्बर, 2019 से एकमुश्त निपटान योजना शुरू की थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गांवों को ''लाल डोरा मुक्त'' करने का एक पायलट प्रोजैक्ट 25 दिसम्बर, 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी में शुरू किया है। अब इस योजना के तहत 15 जिलों के 75 गांवों की मैपिंग के साथ–साथ सोनीपत, करनाल और जींद जिलों की सम्पूर्ण मैपिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रदेश के लोग जब बैंक में ऋण के लिए जाते थे तब उनको शहर की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कहा जाता था। जब किसी किसान या गरीब का बच्चा विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता था तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन वर्तमान सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है, जिससे कि उसको अपने मकान का मालिकाना हक मिल जायेगा और अब लाल डोरा के भीतर स्थित भूमि और सम्पत्तियों की रजिस्टरी की जायेगी जिससे बैंक भी उस व्यक्ति को लोन देने के लिए तैयार हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पशुधन को बढ़ावा देने के लिए उच्चकोटि की पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है और राज्य में 02 लाख 20 हजार पशुओं का बीमा किया गया है। सरकार ने एक संयुक्त टीके का उपयोग करके प्रदेश की गायों और भैंसों को मुंह–खुर की बीमारी

से मुक्त किया। हरियाणा में हमारी सरकार के द्वारा पहली बार प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी का एक समान वितरण किया गया है। पहले सिंचाई और पीने के पानी में भी भेदभाव बरता जाता था और जिस इलाके का मुख्यमंत्री होता था उस इलाके को प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई और पीने का पानी दिया जाता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में जल शक्ति अभियान चलाया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा जल जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। इसके तहत सरकार द्वारा गांवों में कमेटीज का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार से इस योजना के तहत जो भी पैसा आयेगा वह सीधे इन कमेटीज़ के खाते में ही आयेगा। इससे पानी की लीकेज जैसी सभी समस्याओं का समाधान ग्राम के स्तर पर ही हो जायेगा और लोगों की पानी से सम्बंधित सभी शिकायतें दूर हो जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राम निवास (नरवाना)(अ.जा.) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारे नरवाना में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। पानी की समस्या के समाधान के लिए कुछ समय पहले 12 गांवों द्वारा लगातार डेढ़ महीने तक हड़ताल भी की गई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के के जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या है उनकी समस्या का समाधान कब तक हो जायेगा? नरवाना विधान सभा क्षेत्र का प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मंत्री श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला और पूर्व मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा समय–समय पर प्रतिनिधित्व किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी नरवाना का समग्र विकास नहीं हो पाया। आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री से एक बार फिर से यही अनुरोध है कि सबसे पहले तो मेरे नरवाना हल्के में एक गवर्नमैंट गर्ल्स कालेज की स्थापना की जाये। वहां पर जितने 12–13 गांवों में पीने के पानी की समस्या है खास तौर से जो हमारे नैन खाप के गांव हैं उनकी पानी की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाये। धन्यवाद।

डॉ. कृष्ण मिढ्डा (जीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलने का अवसर प्रदान किया सर्वप्रथम तो इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, जिस तरह से महामहिम ने अपने अभिभाषण

के दौरान सरकार का विजन सदन के पटल पर रखा इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा–जजपा की यह सरकार किसान और किसानी के उत्थान के लिए तथा किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर, व्यापारी और युवा वर्ग के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। महामहिम के अभिभाषण की झलक ने यह साबित किया है कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुणा करने के लिए वचनबद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान को किस तरह से आर्थिक मजबूती प्रदान की जाये इसकी रूपरेखा तैयार की है। इस हेतु किसानों को गेहूं व धान के अलावा सूबे के किसानों के लिए सूरजमुखी, बाजरा व तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद करने का जो फैसला किया है वह स्वागतयोग्य है। किसानों की फसल की खरीद में पूर्ण रूप से पारदर्शिता सुनिश्चित हो इसके लिए किसान पंजीकरण पोर्टल पर प्रत्येक किसान को पंजीकृत करके प्रदेश के किसानों के हित में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में उच्च कोटि के पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए सभी पशुओं के लिए बीमा योजना को लागू करके किसानों की बचत को सुनिश्चित करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने जहां किसानों की भावनाओं के साथ निरंतर मजाक किया वहीं आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान के हित में उसकी पीड़ा को समझते हुए जहां बिना ब्याज के फसली ऋण प्रदान किया वहीं दूसरी ओर भावांतर भरपाई योजना जैसी किसान हितैषी योजनायें लागू करके सरकार ने अपने किसान हितैषी होने का प्रमाण दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों की किसान विरोधी नीतियों की वजह से ही किसानों को अपनी आलू, टमाटर, पपलर व सफेदे की खड़ी फसलों को नष्ट करना पड़ा था लेकिन मनोहर सरकार ने किसान और किसानी की दशा को पूर्ण रूप से सुधारने का सराहनीय काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जहां हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जन कल्याणकारी नीतियां लागू की हैं उसको देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि–

इसी शान से हरियाणा को आगे बढ़ाते रहिए,

विकास का परचम यूं ही लहराते रहिए,

जिन लोगों ने खुद को ही सरकार समझा था,

उनको आईना दिखाते रहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रि–बजट चर्चा के दौरान और विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से पश्चिमी यमुना कैनाल प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के प्रस्ताव को और आदरणीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वपन के अनुसार डब्ल्यू.वाई.सी. में 40 प्रतिशत की क्षमता वृद्धि के लिए किसान और प्रदेश हित में काम करते हुए साहसिक कदम उठाने का काम किया है। प्रदेश में काला पीलिया, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा सरकार ने श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आव्हान पर हर घर तक स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाते हुए 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से अटल भूजल के माध्यम से बेहतर जल प्रबन्धन करने का काम किया है और जीन्द में भी भाखड़ा का पानी लाने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मनोहर सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों का संकल्प प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जनहित में लिया है उसके लिए मैं उनको साधूवाद देता हूं। मेरे पिता जी स्व. डॉ. हरिचन्द मिड्ढा जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से जीन्द में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें इसके लिए जीन्द में एक मेडिकल कॉलेज की मांग रखी थी। मैं आज अपनी तथा अपनी जीन्द की जनता की तरफ से सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा का प्रारम्भ मेरे पिता जी की मांग के अनुरूप करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने जीन्द जिले का हमेशा शोषण किया है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और जीन्द को हमेशा रैलीगढ़ बनाने का काम किया। जब विकास करने की बात आई तो लोगों ने अपने–अपने क्षेत्र में विकास करने की बात कही।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बात सही नहीं है। जीन्द में विकास हमारी सरकार के समय में भी हुआ है। जीन्द में यूनिवर्सिटी बनाई गई है तथा हॉस्पिटल बनाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, आप बीच में न बोलें। इनको अपनी बात समाप्त करने दें। हुड्डा साहब अभी कह कर गये हैं कि कोई भी बीच में टोका टिप्पणी न करे। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्या हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह रहा हूं कि 10 साल में जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। माननीय सदस्या भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में जीन्द में जितना विकास हुआ है उसको देख कर ये चकित हो जायेंगी। आज मैं फिर से इस बात को मानता हूं कि उन पिछले 10 सालों के मुकाबले इन 5 सालों में जीन्द में बहुत ज्यादा काम हुआ है । पिछली सरकार के बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूं कि –

थोड़ा सा करके आसमान बताया करते थे,
बिना किए काम गिनाया करते थे
हमने वह दौर भी देखा है जनाब ,
जब वादा करके लोग भूल जाया करते थे।

मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जीन्द को प्रदेश का केन्द्र बिन्दु मानते हुए 6–6 नैशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया है जो प्रदेश में उद्योग के नये आयाम स्थापित करने का काम करेगा। मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को साधूवाद देता हूं। जीन्द की कई वर्षों पुरानी मांग को मेरे पिता जी स्व. डॉ. हरिचन्द मिड्ढा जी की मांग पर 700 करोड़ रुपये का बाईपास जो कम्पलीट करने का काम किया इसके लिए मैं उनका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से जीन्द को हर जिले के साथ बेहतर कनैक्टिविटी देने का काम किया है। चाहे दिल्ली से जीन्द ग्रीनफिल्ड नैशनल हाईवे की बात हो या जीन्द–हांसी नई 50 किलोमीटर रेलवे लाईन की बात हो। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने जीन्द का कम विकास किया था और पिछले 5 सालों में जीन्द का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। उनके बारे में मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि –

वे मुस्कुरा तो रहे हैं, पर आह सुनाई देती है,
खुद से भी अब शिकायत आपको दिखाई देती है,
अगर दिल में हो मलाल कुछ न करने का तो,
देखो खामोशी भी गवाही देती है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पूर्व विधायक डॉ. हरीचन्द मिड्ढा जी के देहान्त के बाद जीन्द की घोषणाएं की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठिये, जब आपकी बारी आएगी तब बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कृश्ण लाल मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यह है कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के साथ–साथ मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और हर व्यक्ति के हित और हकों के लिए काम कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भाकुन्तला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने डॉ. हरीचन्द मिड्ढा जी के देहान्त के बाद जीन्द की घोषणाएं की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शकुन्तला जी, प्लीज आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कृश्ण लाल मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश मुद्दा विहीन नजर आता है। मैं चन्द पक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। ''हक लोगों को जब से मिलने लगे हैं, कुछ दोस्त मेरे नाराज नजर आते हैं।' झूठे मसीहा अब वह बन न सकेंगे, रेत के महल एक लहर में बिखर जाते हैं।'' आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी कुछ डिमांड्स रखना चाहता हूं क्योंकि काम निरन्तर बढ़ता रहता है। जीन्द वालों को सरकार से और आस जगी है कि इतने सालों के बाद जीन्द की किसी ने सुद्ध–बुद्ध तो ली है। मेरी डिमांड है कि जीन्द के शुगरमिल की पिराई की क्षमता को बढ़ाने के लिए बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाए। जीन्द के लोगों को स्वच्छ पेय जल मिले इसके लिए भी बजट का प्रावधान इसी बजट सत्र में किया जाए। ऑटो मार्किट की मांग के लिए तो बड़े डॉक्टर साहब भी वर्ष 2009 से निरंतर लगे हुए थे।

श्री भारत भूशण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे।

डॉ. कृश्ण लाल मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, गलत तो मैं भी नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बतरा जी पर एक बात याद आ गई । एक दिन मैं भी बड़े डॉक्टर साहब की तरह ही एक रोगी को देख रहा था, मेरे पास गांव में एक लेडीज आई

और कहने लगी कि कृष्ण मुझे ऐसे–ऐसे ये बीमारी है तो मैंने कहा कि आपको ये–ये टैस्ट करवाने पड़ेंगे तो जो 10–12 टैस्ट लिखे थे वह वे टैस्ट करवाकर आई और पूछने लगी कि टैस्टों में क्या–क्या कमी आई है। मैंने उनको कहा कि आपके एच.बी., टी.एल.सी. और यूरिन आदि में कमी है तो वह लेडीज मुझे कहने लगी कि कृष्ण एक बात बताऊं मुझ में इतनी कमियां तो मेरी सासू ने भी नहीं निकाली थी जितनी आपने निकाल दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जीन्द में पोलटैक्निकल कॉलेज के लिए बजट की व्यवस्था की जाए। जीन्द विधान सभा क्षेत्र में गांव रायचन्द वाला, डालमवाला, बहुतवाला, खुंगाकोठी इन चारों गांवों को उपमण्डल उच्चाना से बदलकर जीन्द उपमण्डल में ही जोड़ा जाए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मोहम्मद इलियास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके हमारे जो भाई सत्ता पक्ष बैठे हुए हैं उनका भी टैस्ट किया जाए कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुण्डरी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है जिस पर सभी विधायक और मंत्री अपनी–अपनी बात रख रहे हैं। जहां तक कार्य करने की बात है हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश से पानी की निकासी की समस्या को दूर करने के लिए पिछले दिनों सरकार ने एक योजना बनाई है कि इस पानी की निकासी से कैसे छुटकारा मिले इस योजना के तहत मैं अपनी पुण्डरी विधान सभा का जिक्र करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के अन्दर लगभग 54 गांव हैं जिनमें से लगभग 30–35 गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर पानी की निकासी की बहुत भारी दिक्कत है। पिछले दिनों हमने इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के पास एक पत्र भी भेजा था। सिंचाई विभाग इस योजना को देखता है और उन्होंने तुरंत एक महीने के अंदर लगभग 25–30 गांवों की पानी की निकासी की प्लानिंग को सिरे चढ़ाते हुए आश्वासन भी दिया है कि मई–जून तक लगभग 25–30 गांवों का पानी बाहर निकालने का काम किया जायेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई–बहनों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की अनेकों योजनाओं को सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया है और निःसंदेह हमें ऐसी योजनाओं का लाभ भी जरूर उठाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक किसान हूँ इसलिए किसान के

विषय पर अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान चाहे वह छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सभी तरह के किसान आज कर्जमंद हैं और उनकी जमीन बैंकों में गिरवी रखी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में एक योजना लागू की थी कि जिन किसानों ने लैंड मोरगेज बैंक, सोसायटीज तथा अपेक्स बैंक्स से कर्जे ले रखे हैं, उन कर्जों की किस्त को अगर कोई एकमुश्त भरने का काम करेगा तो उस कर्ज के पूरे ब्याज तथा प्लेन्टी को माफ करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों के लिए अच्छी शुरूआत है तथा इसको किसान हित में एक अच्छी पहल ही माना जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब इस महान सदन में बैठते हैं इसलिए यह हम सबका कर्त्तव्य बनता है कि हम सब एक मत होकर किसान की आय को बढ़ाने या दुगुनी करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करें क्योंकि आज किसान की हालत बहुत पतली है और जिस प्रकार से कर्जे माफ की तथा ब्याज माफ करने की योजना सरकार ने चलाई है, वह वास्तव में बहुत सराहनीय कदम है और मेरा निवेदन है कि इसी तरह की कोई योजना बिजली के बिलों को भरने के संबंध में भी चलाई जानी चाहिए। माननीय बिजली मंत्री जी सदन में बैठे हुए है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश को जगमग योजना के अधीन लाने का काम किया जा रहा है और इसको मूर्त रूप देने के लिए छापे भी बड़ी भारी संख्या में मारे जा रहे हैं जिससे प्रदेश का गरीब आदमी बहुत परेशान है क्योंकि इन लोगों पर बिजली संबंधी अनियमितताओं के लिए जो जुर्माने व बिल दिए जा रहे है उनको एक साथ भुगतान करने में इनको बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उनको कोई ऐसा मौका दिया जाये या कोई ऐसी छूट दी जाये या फिर कोई ऐसी प्लानिंग बनाई जाये ताकि उनका जो बिजली का बिल या जुर्माने की राशि है, वह सब कुछ खास प्रकार की बनाई गई प्लानिंग/योजनाओं के तहत कवर हो जाये और इन उपभोक्ताओं को 20–30 या 50 प्रतिशत तक की कोई राहत मिल जाये और वे अपना बिल भर सकें। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के गरीब, मजदूर तथा किसान अर्थात हर आदमी को बिजली बिलों के संबंध में बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पर लोगों को बिजली चोरी की बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है और इस आदत को छूटने में धीरे धीरे समय भी लगेगा। माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी भी सदन में बैठे हुए हैं। वे कह

रहे थे कि हमारे एरिया में कम बिजली चोरी होती है पर मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि हमारे कैथल में तो बिजली की पूरी चोरी होती है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आ रही इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने का काम सदन के सभी सदस्यों को मिल बैठकर करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार की उपलब्धियों की बात है तो उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले दिनों मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नर्सिंग कॉलेज बनाये जाने की मांग की थी और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव धेरडू में 32 करोड़ रूपये की लागत से नर्सिंग कॉलेज का काम बड़े जोर–शोर से जारी है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवादी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अनेक प्रकार की कई योजनाओं को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमलीजामा पहनाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कैथल से करनाल फोर लेन सड़क बनाने की बात हो उस दिशा में भी बहुत जोरो से कार्य किया जा रहा है यही नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो इंडोर–आउटडोर स्टेडियम बनाने की मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को भी पूरा करते हुए पूंडरी के अंदर इंडोर–आउटडोर स्टेडियम बनाने का काम किया है जिसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से मेरा विधान सभा क्षेत्र उन्नतशील रहा है। तीन–तीन कॉलेज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मेरे हल्के के पाई गांव में कन्या महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। क्योंकि यह गांव बहुत बड़ा है और लगभग 14000 के करीब वोटर्ज हैं। यदि इलाके की एक बेटी शिक्षित होगी तो वह दो घरों को रोशन करेगी। एक घर जिसमें उसने जन्म लिया है और दूसरा घर जो वह शादी के बाद जायेगी। कन्या महाविद्यालय खुलने से हमारी बेटियों की शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा, ऐसी मेरी सोच है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे पीने के पानी की जरूरत होती है वैसे ही सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था की जरूरत होती है। इसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फतेहपुर माइनर का एक्सटैंशन करने का अनुरोध किया था, जिस पर आज जोर–शोर से काम चल रहा है। मेरे क्षेत्र में हाबड़ी ब्रांच है जिसमें पूरे इलाके की सिंचाई की व्यवस्था होती है उसका नवीनीकरण का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी

की कृपा से हो रहा है। हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 'सबका साथ सबका विकास' और उसी सोच के मुताबिक पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को अपने–अपने हल्के में विकास के नाम पर 5–5 करोड़ रुपये की ग्रांट दी है। जोकि एक सराहनीय कदम है। इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि सरकार की उपलब्धियों का लाभ मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी मिला है। मेरे साथी अपने–अपने क्षेत्र में राजनीति की बातें करते रहते हैं। अगर हम गरीब आदमी के हितैषी हैं तो हमें सदन में बैठ कर गरीब आदमी और मजदूर के उत्थान के बारे में कोई ऐसी योजना जरूर बनानी चाहिए जिसको उसका वास्तव में लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। डॉ0 अभय सिंह यादव जी ने कहा कि जब हम लोगों के बीच वोट लेने के लिए जाते हैं तो हम पार्टी का एजेंडा लेकर जाते हैं। सरकार ने जिन–जिन लोगों के लिए घोषणाएं की थी, उसका जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 160 घोषणाएं जजपा ने की थी और 260 के करीब घोषणाएं भाजपा ने की थी। लेकिन आज तक कोई भी 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' डिसाईड नहीं हुआ है। जब तक सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय न हो तब तक हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को कैसे विश्लेषण कर सकते हैं कि अभिभाषण में क्या कहा गया है । इस अभिभाषण में कोई विजन नहीं है । आज हरियाणा में बेरोजगारी दर 26.8 प्रतिशत है जोकि पूरे देश में सबसे ज्यादा है । अभिभाषण में बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में कोई एजेंडा नहीं दिया गया है । कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे । यह सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाने की बात करती है लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरैंस की नीति का कोई जिक्र नहीं है । इस समय बहुत से घोटाले हो रहे हैं लेकिन सरकार उन पर

कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है । मेरे पास धान घोटाले समेत 40–45 घोटालों की लिस्ट है । यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहती है तो सरकार को पिछले 5 सालों में हुए और अब होने वाले भ्रष्टाचारों की जांच करवानी चाहिए । बिजली मंत्री इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं । उनके सामने भी मीटर घोटाला, बिजली घोटाला, जी.पी.एस. इंडैक्स का 308 करोड़ रूपये का घोटाला आदि बहुत–से घोटाले आये हैं । क्या सरकार इन घोटालों की जांच करके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? क्या सरकार इन घोटालों की जांच करने की हिम्मत करेगी ? धान घोटाले में अधिकारियों की ऊपर से नीचे तक मिलीभगत है तो क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी जिससे पता लगे कि सरकार का विजन क्या है और सरकार भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है या नहीं ? अब मैं सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात करूंगा । जे.जे.पी. के घोषणा पत्र में था कि हमारी पार्टी की सरकार बनने पर सभी फसलों की खरीददारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी लेकिन आज बाजरा, सरसो, सूरजमुखी, गन्ना जैसी फसलों के पूरे स्टॉक को नहीं खरीदा जाता है । ऐसे में किसान को लाभ कैसे होगा ? ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार किस तरह से वर्ष 2022 तक किसान की आमदनी बढ़ाएगी ? जे.जे.पी. ने कहा था कि ट्यूबवैल कनैक्शन मुफ्त दिये जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर खरीदारी होने पर गिरफ्तारी करने का कानून बनाया जाएगा, फसल बीमा योजना के तहत किसानों से लूट हुई है, इसलिए उस फसल बीमा कम्पनी को सरकारी कम्पनी बनाकर सरकार द्वारा स्वयं फसल का बीमा किया जाएगा इत्यादि । लोगों ने इन चीजों पर इन लोगों को समर्थन देकर विधायक बना दिया और जब यह पार्टी सरकार में शामिल हो गई है तो क्या जे.जे.पी. अब इन बातों की पैरवी करेगी या चुपचाप बैठ जाएगी ? मैं इनसे इन सवालों का जवाब चाहता हूं । इन्होंने उस समय ट्रैक्टर, बुढ़ापा पैंशन आदि के बारे में कई बातें कही थी लेकिन आज ये इनके बारे में बात नहीं करते । भाजपा ने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था लेकिन आज भी वह सिर्फ वायदा ही है, उनको पक्का नहीं किया गया है । कहा गया था कि हम कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे लेकिन नहीं दिया गया । आज सरकार को 6 लाख कर्मचारियों की जरूरत है लेकिन सरकार युवाओं को डी.सी. रेट और आउटसॉर्स पर भर्ती करके काम चला रही है । जो बेचारे गार्ड अस्पतालों में काम करते थे सरकार उनकी रोजी–रोटी

छीनने में लगी हुई है और उनको होमगार्ड लगाने की बात कह रही है । यह सरकार लोगों का रोजगार छीन सकती है उनको रोजगार देने का काम नहीं कर सकती । हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हम नये मैडिकल कॉलेज खोलेंगे लेकिन आज तक किसी नये मैडिकल कॉलेज में एक भी मरीज का इलाज नहीं किया गया है । मैं पूछता हूं कि नया मैडिकल कॉलेज कहां पर खोला गया है ? हमने खानपुर कलां गांव में भगत फूल सिंह महिला मैडिकल कॉलेज खोला था । अब उसके 45 सीनियर डॉक्ट्र्स छोड़कर चले गए हैं क्योंकि उनको प्रमोट नहीं किया गया था । अब वहां पर नये डॉक्ट्र्स भर्ती हुए हैं और वहां पर 23 डॉक्ट्र्स को प्रमोट नहीं किया गया है जबकि उन्होंने 8 साल का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया है । उस मैडिकल कॉलेज में आज न तो दवाइयां हैं, न टैस्ट होते हैं इसके लिए चाहे आप वहां का रिकॉर्ड मंगवाकर चैक कर लीजिए । पहले जहां प्रतिदिन साढ़े चार हजार मरीज ओ.पी.डी. में आते थे। आज वहां पर केवल 500–600 मरीज की ही ओ.पी.डी. रह गई हैं। अब लोग वहां पर केवल खांसी–बुखार की दवाइयां लेने के लिए ही जाते हैं, वहां पर कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। उस हॉस्पिटल में कॉर्डियोलॉजिस्ट्स और हार्ट का भी डॉक्टर नहीं है। उस मेडिकल कॉलेज में कैंसर का ईलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। वहां पर कोई न्यूरोसर्जन भी नहीं है ताकि अगर किसी का एक्सीडैंट हो जाए तो उसको संभाल सके। क्या वह मेडिकल कॉलेज है? अगर सरकार नये मेडिकल कॉलेज खोलने की बजाए जो पहले से मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, उनमें सारी सुविधाएं देकर बढ़िया ईलाज करवाए तो अच्छा रहेगा। आज लोगों को हॉस्पिटल्ज में आने–जाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि लोगों के पास काफी गाड़ियां हैं। जिससे वे 20 से 50 किलोमीटर तक पेसैंट को जल्दी ले जा सकते हैं। अगर डॉक्टर हीं नहीं होंगे तो मेडिकल कॉलेज खोलने का क्या फायदा होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि इन मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल्ज को सही तरीके से चलाएं। गवर्नर एड्रैस में पिछले साल भी मैट्रो ट्रेन को लेकर बड़ा शोर था कि प्रदेश में मैट्रो ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। हम भी सोच रहे थे कि नरेला से कुंडली तक मैट्रो ट्रेन का विस्तार किया जाएगा और सोनीपत में भी मैट्रो ट्रेन आएगी, लेकिन आज गवर्नर एड्रैस में इसका कोई जिक्र नहीं है। बहादुरगढ़ से सांपला तक मैट्रो ट्रेन आनी थी, वह भी नहीं आयी। रोजगार के नाम पर रेल कोच फैक्ट्री जो गोहाना हल्के के लाठ–जौली गांव में

लगनी थी, वह भी नहीं लगायी गयी। इन्टरनेशनल एयरपोर्ट जो महम में बनाया जाना था जिससे लाखों बच्चों को रोजगार मिलता, लेकिन वह भी नहीं बनाया गया। खरखौदा में जो जापानी कम्पनी आनी थी, वह भी नहीं

आयी। इस सरकार का क्या विजन है और सरकार क्या चाहती है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसके अलावा सरकार के द्वारा गऊ माता का नाम लिया जाता है और गऊ माता की जय भी बोली जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट में 10,772 गऊएं मरी हैं तो बाकी पूरे प्रदेश में कितनी मरी होंगी। हमारे यहां पर ऐसी हालत है कि किसानों की फसलों का नुकसान करती हैं और एक्सीडैंट में लोग मारे जाते हैं। इसके लिए सरकार पॉलिसी बनाए और अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाए। इनके कारण जो लोग मारे जाते हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाये। इसके अतिरिक्त सरकार किसानों की भलाई की बात करती है। किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना के बारे में बातें की गयीं, लेकिन यह पता नहीं सरकार किसानों का भला कैसे करेगी ? सरकार किसानों से टमाटर 5 रुपये किलो लेती है परन्तु आज मार्केट में टमाटर का भाव 32 रुपये किलो है तो क्या किसान सरकार को टमाटर बेचेगा ? प्याज साढ़े 6 रुपये लेती है, परन्तु बाजार में प्याज का भाव 35 रुपये प्रति किलो है। आलू 5 रुपये किलो लेती है, परन्तु आलू का भाव 16 रुपये प्रति किलो है। फूलगोभी साढ़े 7 रुपये लेती है, परन्तु बाजार में इसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसी प्रकार गाजर 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ली जाती हैं। (शोर एवं व्यवधान) मेरे पास सरकार द्वारा निर्धारित किये गये रेट्स की लिस्ट है।

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों से उस टाईम सब्जियां खरीदती है, जिस वक्त मार्केट में उनको कोई नहीं खरीदता।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। सरकार ने मिनिमम प्राईज पर किसी को भी उसकी फसल बेचने के लिए नहीं कहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि यह दवाई कड़वी जरूर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास अरोड़ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब किसानों की सब्जियों के रेट्स डाउन आते हैं तो सरकार उसके जे फार्म पर सब्जियों के कम रेट्स आते हैं उसके हिसाब से क्लेम के पैसे देती है। इसके लिए किसान द्वारा अपनी फसल की गिरदावरी करवायी जानी जरूरी है। तब जाकर किसान भावांतर भरपाई योजना के तहत क्लेम करते हैं और सरकार किसान के नुकसान की भरपाई करती है और करेगी।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण बीच में बोलकर मेरा समय खराब कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह दवाई कड़वी जरूर है, लेकिन अगर ये इसको निगल जाएंगे तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।(शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त मटर का भाव 40 रुपये प्रति किलो है, लेकिन सरकार उसको 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है। मैं यह कहता हूं कि कम से कम किसानों की फसल का एक्चयूअल भाव दिया जाए। किसान अपनी जमीन को सब्जी उगाने के लिए काफी बार ठीक करता है और उसमें कितनी लेबर लगती है, कितनी खाद लगती है, कितना किराया लगता है, कितनी कटाई लगती है, कितनी दवाइयां लगती हैं ? इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि किसानों की फसला का मूल्य सी–टू फार्मूले से कैल्कयूलेट करके दें दे तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। सरकार किसानों को उनकी फसलों का सही भाव दे तभी किसानों को फायदा होगा।

श्री कवंर पालः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत लम्बे समय तक शासन किया है, इसलिए ये यह बात बता दें कि इनकी सरकार के राज में किसानों ने कितनी बार अपनी फसलें सड़कों पर डाली हैं ? माननीय सदस्य कोई एक उदाहरण देकर बता दें कि इन्होंने किसानों की भलाई के लिए अच्छा कार्य किया हो। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि अगर किसान का ज्यादा नुकसान होगा तब उस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। सरकार का इससे बढ़िया निर्णय और क्या हो सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि एक किसान को अपनी आलू की फसल 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचनी पड़ी थी, उसकी रसीद मेरे पास है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हुड्डा साहब की बात बिल्कुल ठीक है। पहले जब किसान को अपनी फसल बेचने में 9 पैसे का भाव मिलता था तभी तो सरकार ने ''भावांतर भरपाई योजना'' की शुरूआत की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किस चीज का भावांतर कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, मंत्री जी कह रहे हैं कि जब किसान को मार्केट में कोई खरीददार नहीं मिलेगा तब सरकार इस योजना के तहत किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का काम करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज जल्दी से सम–अप कीजिए। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घन□यामदास अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अरोड़ा जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनीपत में अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी तथा राई क्षेत्र के सेरसा और जखौली गांव में मसाला मंडी कब तक बनकर तैयार हो जायेगी? इस बात का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हर बार होता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि गांवों को सेवन स्टार और फाईव स्टार जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे लेकिन अभी तक सरकार ने इस पॉलिसी पर भी कोई काम नहीं किया है और सरकार ग्राम सचिवालय की भी बात करती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार हर टेल तक पानी पहुंचाने की भी बात करती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से हर टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेगी जबकि हांसी–बुटाना ब्रांच और दादुपुर नलवी नहर को तो सरकार ने पहले ही बंद कर दिया है क्योंकि कहीं किसानों को अधिक मुआवजा न देना पड़ जाये। साथ में सरकार यह भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार किसानों की इतनी हितैषी

है तो फिर किसानों को मुआवजा क्यों नहीं देना चाहती है? यह ऐसी पहली सरकार है जिसने दादुपुर नलवी नहर को बंद करने का काम किया है। आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी चालू नहर बंद नहीं की है। सरकार यह कहती है कि हर खेत और हर टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में 13 टेल है, उनमें से किसी भी टेल में पानी नहीं आ रहा है और मेरे हल्के में 16 गांव ऐसे हैं जिनको पानी मोल लेकर पीना पड़ रहा है। वहां का अंडर ग्राउंड वाटर का लैवल काफी डाउन हो चुका है और कई जगहों पर नहरी पानी भी नहीं आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की बात करती है। मेरे हल्के में 31 सड़कें ऐसी हैं जो चलने लायक भी नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं इसलिए जल्दी से सम–अप कीजिए।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हमने प्रदेश में अपराध को रोकने का काम किया है। मैं समझता हूं कि प्रदेश में अपराध कम नहीं हुए हैं, बल्कि अपराध बढ़े हैं। मैं सरकार का ध्यान अपराध के आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में हत्या के मामलों की संख्या 2.54 प्रतिशत, गैर–इरादतन हत्या के मामलों की संख्या 11.11 प्रतिशत, इल्लीगल इंटैंशन के मामलों की संख्या 24.54 प्रतिशत, फिरौती के मामलों की संख्या 11.11 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की हत्या करने और उनको चोट पहुंचाने के आंकड़े भी प्रदेश में बढ़े हैं और इसके अलावा अनुसूचित जातियों की बहन बेटियों पर भी अत्याचार और दुष्कर्म के आंकड़े भी बढ़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गए हैं। प्लीज आप बैठ जायें। अब आप लिखकर के दे दीजिए, उसको हाउस की प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दिया जायेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे जरूरी बात थी वह तो रह गई है इसलिए मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की कर्जा माफी की बात करती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों का टोटल 371 करोड़ 25

लाख रुपये का कर्जा है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हरियाणा के बारे में नीति आयोग के आंकड़े पेश करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, आपको बोलते हुए 16 मिनट का समय हो गया है जबकि प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने हेतु सर्वसम्मति से 10–10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब आप कृपया करके बैठ जायें क्योंकि आपकी पार्टी के दूसरे माननीय सदस्यों को भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलना है। (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, अगर आपकी कुछ बातें रह गई हैं तो उनको आप लिखकर भिजवा दें उनको सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) इसके बाद आपको बजट पर भी बोलना है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आप जो भी आंकड़ें यहां प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें आप लिखकर सम्बंधित मंत्री जी को भिजवा दें। (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब जो प्रत्येक मैम्बर के बोलने की समय–सीमा है आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा 16 सतत् विकास के लक्ष्यों में बड़ी बुरी तरह से पिछड़ गया है। चाहे गरीबी उन्मूलन की बात हो या चाहे फिर बेहतर शिक्षा की बात हो। शिक्षा और गरीबी उन्मूलन में हरियाणा पहले नम्बर एक पर होता था जोकि अब पिछड़ कर 12वें नम्बर पर आ गया है। इस प्रकार से नीति आयोग के 16 के 16 हैड में अलग–अलग आंकड़ें हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1206 प्राईमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं जबकि होना तो यह चाहिए कि प्रदेश में और ज्यादा से ज्यादा प्राईमरी स्कूल खोले जायें क्योंकि सरकारी प्राईमरी स्कूल्ज में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ने जाता है। इसी प्रकार से 150 खेल नर्सरीज बंद होने जा रही हैं। इस बारे में सम्बंधित मंत्री जी का ब्यान आया है। ऐसे ही आरोही स्कूल भी एक–एक करके बंद होते जा रहे हैं जो पिछली सरकार द्वारा खोले गये थे। इसी प्रकार से जगमग योजना की बात भी बहुत बढ़ा–चढ़ाकर की जाती है। सरकार दावा करती है कि उसने प्रदेश के 4200 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मैं इस सम्बन्ध में भास्कर की रिपोर्ट दिखाना

चाहता हूं जो इस अखबार ने हरियाणा के एक–एक गांव को अच्छी तरह से चैक करके तैयार किया है। इस मामले में हकीकत यह है कि हरियाणा में इस समय केवल 70 गांवों में ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बहुत से गांवों में मीटर घरों के बाहर निकालने के बाद सरकार के दावे के मुताबिक 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई है। बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां पर मीटर तो घरों से बाहर निकाल दिये गये हैं लेकिन उनमें अभी तक भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। एक बात मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री की खुद के हल्के के बहुत से गांवों में अभी तक 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। सरकार के अपने विधायक और मंत्री अपने–अपने हल्कों में मीटर बाहर निकालने का विरोध कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है कि प्रदेश के बाकी लोग तो मरें लेकिन सरकार के अपने विधायकों और मंत्रियों के गांवों में मीटर घरों से बाहर नहीं निकलने चाहिएं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** इस प्रकार से यह सरकार की बहुप्रचारित जगमग योजना की ग्राउण्ड रिपोर्ट है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एच.टैट का रिजल्ट केवल मात्र 9 परसैंट है। इससे यह अंदाजा सहज में ही लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले पांच वर्ष के शासनकाल के दौरान प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इन सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार यह दावा कर रही है कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। मैं सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सोनीपत जिले में पिछले दो साल के दौरान 28 प्वायंट लिंगानुपात गिरा है। यह रिकार्ड की बात है। इसी प्रकार से मैं यह बताना चाहूंगा कि सुशासन के क्षेत्र में भी हरियाणा प्रदेश बहुत पीछे है। प्रदेश के विधान सभा चुनावों से पहले उप मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किये थे उनको निभायेंगे या नहीं यह देखने वाली बात होगी। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि यह जो अभिभाषण है गर्वनर साहब ने यह समझ लिया था कि इसमें कुछ नहीं है इसलिए वे पढ़ना बीच में ही छोड़कर चले गये। मुझे तो यही लगता है क्योंकि मुझे भी इसमें कुछ विशेष नहीं मिला इसलिए हम इसको सही नहीं मानते क्योंकि न

तो इसकी सही दिशा है और न ही सही दशा है। **श्री उपाध्यक्ष** : मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जायें।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अभी कुछ बातें कहने से रह गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है मलिक साहब जी, आप उनको लिखकर दे दीजिए, उनको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना दिया जायेगा।

***श्री जगबीर सिंह मलिक** : ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश इलाके में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है जैसे पिनाना गांव में पानी नहीं आता है, गांव लाठ में ट्यूबवैल से पानी की लाइन डलवाने का काम किया जाये, गांव जौली में नया ट्यूबवैल लगवाया जाये, गांव हुल्लाहेड़ी में बड़ी डिग्गी का निर्माण करवाया जाये और जो पानी की लाइनें खराब हो चुकी हैं, उनको ठीक करवाने का काम किया जाये। गांव खिजरपुर जाट माजरा में और गांव हुल्लाहेड़ी में पीने का गंदा पानी आता है, वहां पर शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया जाये। गांव बाघडू में पीने का पानी नहीं है इसलिए वहां पर ट्यूबवैल लगवाने का काम किया जाये। गांव तिहाड़ कलां में ट्यूबवैल का पानी खराब हो चुका है इसलिए वहां पर डिग्गी बनाने का काम किया जायें गांव तिहाड़ खुर्द में पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है और इसके अतिरिक्त वहां के ट्यूबवैल का पानी भी खराब हो चुका है इसलिए वहां पर जल्दी से जल्दी स्वच्छ पानी का प्रबंध किया करवाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि गांव शेल्द में ट्यूबवैल का पानी भी खराब हो चुका है जिसके कारण वहां की डिग्गी का पानी भी खत्म हो चुका है इसलिए वहां पर स्वच्छ पानी का प्रबंध किया जाये। गांव भादी में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है इसलिए वहां पर भी पानी पहुंचाने का काम किया जाये, गांव चिटाना में ट्यूबवैल का पानी खराब हो चुका है, गांव करेवड़ी में पानी की पाइप लाइन खराब हो चुकी है, गांव जुआं में पीने के पानी की काफी गंभीर समस्या बनी हुई है, गांव दोदवा में पीने के पानी के लिए एक और ट्यूबवैल लगवाने का काम किया जाये, गांव ककाना में

पानी की डिग्गी का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, उसको भी जल्दी ही बनवाने का काम किया जाये, गांव सलीमपुर ट्राली में पानी की डिग्गी के तालाब का बैड टूटा हुआ है जिसके कारण पानी जल्दी ही खराब हो जाता है उसको भी ठीक करवाया जाये, गांव बोहला में ट्यूबवैल मंजूर हो चुका है इसलिए उसको भी जल्दी ही बनवाने का काम किया जाये और वहां की पानी की लाइनें भी खराब हो चुकी हैं इसलिए वहां पर भी पानी की लाइनों को ठीक करवाने का काम किया जाये। गांव रत्नगढ़ के आधे गांव में पानी की लाइनें नहीं डाली गई हैं इसलिए वहां पर पानी की लाइनें डलवाने का काम किया जाये। गांव करेवड़ी में पानी की लाइन भी खराब

***चेयर के आदे ानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

हो चुकी है इसलिए वहां की लाइन को भी ठीक करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में टोटल 8 टेल हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि गुहणा माइनर में टेल पर पानी नहीं आता है इसलिए उस टेल पर पानी पहुंचाने का काम किया जाये, गांव किलोहड़द में राई डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी नहीं आता है इसलिए वहां पर भी पानी पहुंचाने का काम किया जाये। गांव भटाना–जफराबाद में सोनीपत माइनर में पानी नहीं आता है इसलिए वहां पर भी पानी पहुंचाने का काम किया जाये। गांव माच्छरी जुआं माइनर में टेल पर पानी नहीं आता है इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया जाये। गांव खानपुर कलां में रामगढ़ माइनर में टेल पर पानी नहीं आता है इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया जाये। गांव कैलाना खास में जवाहरा माइनर में पानी नहीं आता है इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया जाये। गांव सरगयल माइनर में टेल तक पानी नहीं आता है इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया जाये। गांव माहरा में खुबडू ब्रांच रजबाहे में पानी नहीं आता है इसलिए वहां पानी पहुंचाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांवों में सड़कों का बहुत बुरा हाल है इसलिए मैं उनके बारे में भी सदन में बताना चाहता हूं। गांव जौली से नयात तक और जौली से खेड़ी दमकल सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इन सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये। खेड़ी दमकल से लाठ तक और खेड़ी से न्यात तक की सड़कें भी खराब हो चुकी हैं इसलिए इन सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये। गांव तिहाड़ मलिक से मोहाना सड़क भी खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम

किया जाये। गांव पिनाना से भैंसवाल कलां तक सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। गांव गुहना से फरमाणा, गुहना से भैंसवाल कलां, गुहना से मोहाना, गुहना से सलीमसर माजरा तक की सड़कों का बहुत बुरा हाल हो चुका है इसलिए वहां की सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये। गांव लुहारी टिब्बा से मोहाना तक, फरमाणा रोड से गांव तक सड़क खराब हो चुकी है इसलिए वहां की सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये। हुल्लाहेड़ी गोहाना रोड से दिल्ली ब्रांच नहर तक सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। गांव किलोहड़द गोहाना रोड से किलोहड़द तक सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। खिजरपुर जाट माजरा गांव से चिटाना की सड़क, गोहाना रोड से खिजरपुर जाट माजरा तक की सड़क खराब हो चुकी है इसलिए वहां की सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये। गांव जाजी से माच्छरी तक सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। गांव नैना से मोहाना सड़क अधूरी पड़ी हुई है इसलिए इस सड़क को भी पूरा करवाने का काम किया जाये। नैना से सलीमपुर ट्राली सड़क भी खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। बाघडू महलाना पुल से बड़ी बाघडू तक सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। सलारपुर माजरा से मोहाना खड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। माच्छरी गोहाना रोड से गांव के स्कूल तक की सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी जल्दी से जल्दी बनवाने का काम किया जाये। गांव जुआं से माच्छरी तक सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। सलीमपुर ट्राली से नैनातातपुर सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। महलाना दिल्ली ब्रांच नहर के साथ वाली सड़क टूटी पड़ी हुई है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। चिटाना से चटिया ओलिया सड़क के बीच में बिजली के खम्बे खड़े हैं इसलिए इन खम्बों को हटवाने का काम किया जाये। दुलेहा से रोलद लतीफपुर सड़क खराब पड़ी हुई है इसलिए इस सड़क को भी बनवाने का काम किया जाये। कैलाना खास से मुण्डलाना सड़क पर पुल निर्माण करवाया जाये, खानपुर कलां से मुण्डलाना सड़क खराब हो चुकी है इसलिए इन सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये। दोदवा बोहला से दोदवा सड़क पर

पुल का निर्माण करवाया जाये। गांव माजरी में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण मेन सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण सड़क की खस्ताहालत हो चुकी है इसलिए इस सड़क का भी निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री राम करण (शाहबाद)(अ.जा.) : स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया सर्वप्रथम इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिमाण्ड है। शाहबाद शहर में जी.टी. रोड की एक साईड में विभिन्न स्कूल्ज और गर्ल्स कालेज है और दूसरी साईड में बस स्टैण्ड, तहसील कार्यालय और कोर्ट सहित दूसरे कार्यालय भी है लेकिन वहां पर कोई अण्डर पास नहीं है जिससे आम जनता को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो सड़क क्रॉस करते समय बहुत से व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि शाहबाद में बस–स्टैण्ड के पास जल्दी से जल्दी एक अण्डर पास का निर्माण करवाया जाये ताकि आम जनता को सुविधा हो सके। मेरी एक मांग यह है कि मेरे हल्के में सूरजमुखी की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है इसलिए सरकार सूरजमुखी की खरीद के लिए जो भी औपचारिकतायें जरूरी हैं उनको समय पर पूरा करे ताकि सूरजमुखी की फसल के बाजार में आने पर सूरजमुखी की खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक बात मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहबाद के साथ–साथ प्रदेश में जो भी विकलांग हैं उनकी पढ़ाई और दवाई का खर्च सरकार के स्तर पर वहन किया जाये। मुझे विश्वास है कि मेरी इन दो–तीन मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनका जल्दी से जल्दी समाधान करेगी। धन्यवाद।

श्री दीपक मंगला(पलवल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का "सबका साथ–सबका विकास" के नारे का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो वह हमारा पलवल जिला है। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही सबसे पहले वर्ष 2015 में पूरे हरियाणा में जब बारिस और ओलावृष्टि से हमारे किसान भाइयों की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मुझे वह दिन आज भी याद है कि माननीय मुख्यमंत्री

जी ने रात को 10 बजे अधिकारियों की तुरन्त मीटिंग बुला कर तथा वहां पर पटवारियों की एक टीम भेजकर फसलों के नुकसान की गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजा दिया था। सबसे ज्यादा मुआवजा पलवल जिले को दिया गया जबकि वहां से हमारी पार्टी का एक भी विधायक नहीं था। जहां पूरे हरियाणा को 1092 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया वहीं अकेले पलवल जिले को 199 करोड़ रुपये का किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया गया। यह मुआवजा भी एक महीने के सीमित समय में ही दिया गया। पलवल में पिछली सरकारों की जो घोषणाएं थी वे पूरी नहीं हुई थी। पलवल को जिला बने 10 साल का समय हो गया है लेकिन हमारे पलवल में कोई भी जिला स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं था। घोषणा तो पिछली सरकार के समय में कर दी गई थी लेकिन उसका काम हमारी श्री मनोहर लाल जी की सरकार द्वारा गुभेरा में 28 एकड़ में एक जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनवाया जा रहा है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ऐसी एक नहीं अनेकों घोषणाएं हैं जो पिछली सरकार द्वारा की गई थी लेकिन पूरी नहीं की गई। इसी प्रकार से गुरवारी में पॉन्टुन पुल की घोषणा भी कांग्रेस सरकार में की गई थी लेकिन उस पॉन्टुन पुल का निर्माण कार्य हमारी मनोहर लाल जी की सरकार ने शुरू करवाया है। कांग्रेस सरकार में इस पुल की घोषणा हुई थी लेकिन कभी इसको गुरवारी ने बनाने की बात कही जाती थी तो कभी हमारे खादर के गांव धन्तरी में बनवाने की बात की जाती थी लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने गुरवारी में भी और धन्तरी में भी दोनों जगह ये पॉन्टुन पुल बनवा दिये हैं जिससे किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिली है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से हमारे पलवल की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की हमारे किसानों की बहुत पुरानी मांग थी। यह केवल पलवल जिले के लिए नहीं बल्कि उसके साथ लगते जिले मेवात और फरीदाबाद के लिए भी फायदे की बात है। कांग्रेस सरकार में उस शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की सिर्फ घोषणाएं होती थी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्षमता बढ़ाने की घोषणा भी की और उस मिल की क्षमता को बढ़ाया भी तथा आज हमारी पलवल की शुगर मिल बढ़ी हुई क्षमता के साथ चल रही है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिराई का सीजन समाप्ति की ओर है लेकिन पलवल की शुगर मिल में पिराई शुरू भी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आप बैठ जाईये और बीच में टोका–टिप्पणी मत कीजिए।

18:00 बजे

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पिराई किसी शुगरमिल में हो रही है तो वह पलवल के शुगरमिल में हो रही है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी तरह से बवानी खेड़ा और रसूलपुर गांवों में एक–एक आर.ओ.बी. बनाने की घोषणा पिछली सरकार में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों आर.ओ.बीज. की घोषणा करके उन पर बहुत तेज गति से काम चालू करवा दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 'सबका साथ, सबका विकास' वाली बात थी वह पलवल जिले के अन्दर फलीभूत हो रही है जबकि पलवल जिले में एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। ऐसे ही हमारे पलवल में कॉलेजिज की बात तो छोड़िये हमारे यहां मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा स्कील डवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी बनाकर हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात दी है। इसी तरह से के.जी.पी., के.एम.पी. बनाए हैं। हमारे पलवल में एक कहावत होती थी कि 'पलवल की सडक पर घोड़ा दौड़ा–दौड़ा जाए।' एक हमारे यहां देहाती कहावत होती थी । आज के.जी.पी., के.एम.पी. ऐसी रोड बन गई हैं चाहे उन पर आप हवाई जहाज उड़ा लो। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यहां मेरे जितने भी साथी बैठे हुए हैं उन सभी को पता है कि वे रोड कैसे बने हुए हैं। जिस साथी ने भी पलवल आना होता है तो यह पता नहीं चलता कि कब पलवल में पहुंच गये। मेरे सभी साथियों को पता है। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, ––

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी, प्लीज आप बीच में न बोलिये।

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में रेलवे इंफ्रास्ट्रैक्चर की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। के.एम.पी. पर पलवल से सोनीपत तक जोकि 130 किलोमीटर लम्बा एरिया है जिस पर रेलवे लाईन बिछाने की परियोजना शुरू की है। वह पलवल से सोहना और गुड़गांव को जोड़ती हुई सोनीपत तक जाएगी। यह एक बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में शुरू की है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे पूरे

उत्तरी हरियाणा में रेलवे लाईन की अच्छी कनैक्टिविटी होगी। हमारे पलवल के अन्दर एक ऐलिवेटिड फलाईऑवर बन रहा है और पेलक गांव के अन्दर एक इंटर चेंज बनना था लेकिन उसमें पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक रूकावट आ गई। मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि पेलक गांव के अन्दर अगर इंटर चेंज बन जाए तो पलवल के अन्दर जो ऐलिवेटिड फलाईऑवर बन रहा है उसका काम भी तय समय में तेज गति से हो जाए और पलवल के लोगों की काफी समय से जो जाम की समस्या थी वह भी दूर हो जाएगी। हमारे यहां पलवल के पास से यमुना नदी बहती है लेकिन चाहे हमारा क्षेत्र है चाहे मेवात का क्षेत्र है वहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र से मेवात क्षेत्र को यथासंभव पीने का पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पानी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ नीचे चला जा रहा है। पीने के पानी के संबंध में पुराने जमाने में प्याऊ लगाने की एक परंपरा हुआ करती थी और उसी परंपरा के मद्देनज़र मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को अच्छी तरह से पानी सुलभ कराने तथा निरंतर गिरते जा रहे जल स्तर को उपर उठाने के लिए यमुना नदी पर बैराज बनाया जाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि मेरे क्षेत्र का जल स्तर उपर आ जायेगा और इससे न केवल हमारे क्षेत्र को बल्कि साथ लगते क्षेत्रों को भी पानी की पूर्ति संभव हो सकेगी। पानी की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में यह समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे पलवल में बैसलॉत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास पशुधन है और इसकी बदौलत यहां पर हमारे किसान भाई बहुत बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं और जगह–जगह जाकर उस दूध को बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। वास्तव में हमारे इस क्षेत्र में दूध बेचना रोजी–रोटी का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर इस क्षेत्र में एक चिलिंग प्लांट लगा दिया जाये तो इससे दूध उत्पादक किसानों को वहां पर अपना दूध रखने की अच्छी व्यवस्था हो जायेगी और इस प्रकार यदि दूध उत्पादक किसान दूध बेचने जाने में यदि लेट भी हो जायें तो भी चिलिंग प्लांट में उनका दूध खराब होने से बच जायेगा। निश्चित रूप से यह हमारे दूध उत्पादक किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा यहां एक खादर का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 14–15 गांव आते हैं। यहां पर पॉवर हाउस बनाने की पिछले काफी लंबे समय से एक

डिमांड थी। पिछली सरकारों के समय में इस बाबत की घोषणा भी हुई लेकिन नॉन फिजिबिलिटी की संज्ञा देकर इस कार्य को अंजाम नहीं दिया गया लेकिन जब हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मांग की तो यहां पर एक पॉवर हाउस बना दिया गया। वर्तमान में यह पॉवर हाउस चालू हो गया है जिसकी बदौलत आज सारे खादर क्षेत्र के अंदर बिजली की पूर्ति भरपूर मात्रा में की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मेरा एक निवेदन यह भी है कि यहां पर सी. एच.सी. बनाई जानी चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र शहर से बिल्कुल अलग–थलग पड़ने वाला क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में सी.एच.सी. बना दी जाती है तो इससे यहां के लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। यह क्षेत्र शहर से बीस किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में के.जी.पी. तथा के.एम.पी. भी बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया है इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में रेल कॉरिडोर बनाने का काम भी पूरे जोर–शोर से चालू है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की हर तरफ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है अगर यहां पर औद्योगिक क्षेत्र बन जाये तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र व आस पास के क्षेत्रों के लोगों को यहां पर पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध होंगे। यही नहीं हमारे पलवल जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नर्सिंग कॉलेज बनाने की घोषणा भी की थी और यह नर्सिंग कॉलेज अब बनकर तैयार हो गया है। हम चाहते हैं कि तय समयावधि में इस नर्सिंग कॉलेज में हमारी बच्चियां नर्स की कोचिंग/ट्रेनिंग लेकर नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी सेवायें देना शुरू कर दें। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शल्लागढ़ के नाम से एक एरिया है जहां पर दलित बस्तियां हैं। इस एरिया में अमरूत योजना के तहत सीवरेज व पीने के पानी की लाइनें डाली जा रही हैं। यहां पर एक अम्बेडकर पार्क भी है। अगर यहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त सामुदायिक केन्द्र बना दिया जाये तो 25–30 हजार की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, यह समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का समय है। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उससे तो विकास की कोई बात दिखाई नहीं देती तो ऐसी सूरत में वे

किस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का गुनगान कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन साथियों से भी आग्रह करता हूँ जिन्हें विकास दिखाई नहीं देता कि वे एक बार हमारे पलवल जिले में आयें तो उन्हें विकास संबंधी सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। मैं खुद उनके साथ चलकर पलवल जिले के विकास के कार्यों को दिखाने का काम करूंगा। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर काम करते हुए प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है और साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से शुगर मिल्ज के विषय पर चर्चा हुई है, इसलिए मैं भी इस विषय पर सिर्फ एक मिनट ही बोलना चाहता हूँ। श्री दीपक मंगला जी ने शुगर मिल्ज के बारे में काफी तारीफ की है। सहकारिता मंत्री सदन में उपस्थित हैं और वे काफी सुलझे हुए और ईमानदार व्यक्ति हैं। पलवल शुगर मिल के अंदर बॉयलर का साईज बढ़ाने के लिए पांच फीट खोई की बेल्ट को सरकाना था। उस खोई की बेल्ट सरकाने में लेबर की कॉस्ट 6–7 लाख रूपये आती है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की इन्क्वॉयरी करवायेंगे कि वास्तव में कितना खर्च हुआ है? हमारी सूचना के मुताबिक उस पर 72 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की इन्क्वॉयरी करवायेंगे?

डॉ0 बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, उस मैटर पर इन्क्वॉयरी बैठा दी गई है।

श्री सत्य प्रका□ा (पटौदी) (अ.ज.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पारदर्शिता को लेकर चर्चा हुई है। पारदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण शिक्षा का है। उसी कड़ी में हमारी सरकार ने 500 से ज्यादा अध्यापकों के स्थानांतरण ऑन–लाइन किए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 'मुख्यमंत्री समृद्धि योजना' शुरू की है। जिसमें 5 एकड़ तक के किसान या वह गरीब परिवार जिसकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है उसका पंजीकरण करके सालाना 6 हजार रुपये देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, किसानों और मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर

पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश की मंडियों व चीनी मिल्ज में 'अटल किसान–मजदूर कैंटीन' स्थापित की गई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आभार प्रकट करता हूँ। अभी सदन में माननीय सदस्यों ने के.एम.पी. और उसी के साथ जुड़ी हुई रेलवे लाइन के बारे में जिक्र किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मानेसर का मास्टर प्लान वर्ष 2031 का है और गुरूग्राम का मास्टर प्लान वर्ष 2021 का है। समय–समय पर एकाएक निजी स्वार्थ के लिए या उस क्षेत्र के किसानों को प्रताड़ित करने के लिए जो क्षेत्र पहले बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था उस क्षेत्र को एग्रीकल्चर घोषित करके उस क्षेत्र को एक्वायर और उसकी पेमैंट भी नहीं दी गई तथा न उनकी जमीन ली गई और न ही छोड़ी गई। आज हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो दुखी और परेशान हैं। मानेसर का बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर अलग–अलग तरह के कानूनी झगड़ें हैं। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि उस जमीन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर की भी पालना हो जाये और गरीब लोगों को भी न्याय मिल जाये। अपार्टमैंट वालों को अपार्टमैंट मिल जाये और जो जमीन बची हुई है जहां पर गरीबों ने अपने घर बना रखे हैं अर्थात् मानेसर के लोग रह रहे हैं अगर उस जमीन को छोड़ दिया जाये तो निश्चित तौर पर मानेसर उजड़ने से बच जायेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मेरी यह है कि 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों जैसे कि बी0पी0एल0 अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों/टपरीवास जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं तथा महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की अथवा उनकी बेटी की शादि के अवसर पर 11 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई का जमाना है । इस समय माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं । मेरा उनसे निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दिया जाए । इसी तरह से मकान बनाने/मरम्मत करने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दिया जाए । हमारा पंचगांव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी चारों तरफ से कनैक्टिविटी है और यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ईजी अप्रोच पर है तथा द्वारका एक्सप्रैस–वे के बिल्कुल बगल में है । अगर सरकार वहां पर व्यापारिक केन्द्र डिवैल्प करे तो उससे प्रदेश को निश्चित तौर पर लाभ होगा । उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की आय बढ़ेगी । अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बड़ी हाईराइज बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं । वहां पर जब एल.ओ.आई. (लैटर ऑफ इंडैंट)

दिया गया तो उसमें वहां के लिए 24 मीटर के रास्ते की चर्चा नहीं की गई । इस वजह से वहां पर बहुत–सी सोसाइटीज को कनैक्टिविटी नहीं मिल पा रही है । मेरा निवेदन है कि सरकार उनको 24 मीटर के रास्ते की कनैक्टिविटी उपलब्ध करवाये । इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में लगभग 15 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है । इसका कारण यह है कि पूर्व में हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है । हमारे क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचाया गया और उसको डार्क जोन घोषित कर दिया गया । इससे वहां का किसान बहुत परेशान है । वहां पर न तो फसलों के लिए पानी है और न ही पीने के लिए पानी उपलब्ध है । अतः मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की तरफ से अगर कोई नहर प्रस्तावित हो तो उसे टीयर ऑफ करके मेरे मानेसर क्षेत्र को उससे पानी दिया जाए । दूसरा, मेरा निवेदन है कि बादली और झज्जर पटौदी के नजदीक है । यहां से जो नहरें आती हैं उनका सारा पानी वहीं रोक दिया जाता है जिससे हमारी नहरों में बहुत ज्यादा रूकावट आती है । मेरा निवेदन है कि उनको साफ करके सभी नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों को वर्ष 2015 में पदोन्नति में आरक्षण दिया था । रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का केस हाई कोर्ट में अंडर लिटिगेशन होने की वजह से उस फैसले पर स्टे लगा हुआ था और उनके बैनीफिट को रोक दिया गया था लेकिन अब हाई कोर्ट से स्टे हट गया है । अतः मेरा निवेदन है कि रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए । धन्यवाद ।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। कथनी–करनी एक्कै ढ़ाल । वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की बात कही गई थी जिसमें नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सेवाएं प्रदान कौन करेगा ? हरियाणा के हर विभाग में 25–30–35 प्रतिशत या इससे भी अधिक

कर्मचारियों की कमी है । ये सेवाएं कौन देगा ? पिछले अभिभाषण में रिजर्व कैटेगरीज के लिए कोई स्थान था लेकिन इस बार अभिभाषण में उन्हें जगह ही नहीं मिल पाई । दुःख की बात है कि हरियाणा में 20 प्रतिशत जनसंख्या रिजर्व कैटेगरीज की है । आज जगह–जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदेश में भय का

माहौल है लेकिन आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है । हरियाणा में वर्ष 2015–2020 तक एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के कल्याण के लिए बजट का कुल आधा प्रतिशत खर्च किया गया है जबकि 29 राज्यों की औसत 2.7 प्रतिशत है । उनका कल्याण कैसे होगा और 'सबका साथ सबका विकास' कैसे सफल होगा ?

सर, इस अभिभाषण में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20 प्रतिशत का एक टारगेट रखा गया है कि आने वाले वर्षों में 20 प्रतिशत वन क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में होगा। सर, क्या हम जानते हैं कि आज हम कहां खड़े हैं ? जो रिपोर्ट आयी है उसमें देश के 29 राज्यों में सबसे न्यूनतम स्तर पर आज हरियाणा प्रदेश खड़ा है। इंडिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट्स की वर्ष 2019 की रिपोर्ट दिसम्बर में आयी है जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के वन क्षेत्र का एरिया घटकर 3.5 प्रतिशत पर रह गया है, जोकि पूरे देश में सबसे नीचे है। यह कितने दुःख की बात है। इसकी क्यों न इंक्वयारी करवायी जाए क्योंकि प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं ? प्रदेश में पौधा रोपण किया जा रहा है लेकिन वन क्षेत्र घट रहा है। क्यों न इसकी इंक्वयारी करवायी जाए ? अरबों रुपया सरकार का खर्च होता है और उसके बाद भी वन क्षेत्र घट जाता है। इसके अतिरिक्त खेतों में पानी पहुंचाने की बात की जा रही है कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार कहती है कि हर टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा लेकिन डॉर्क जोन एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए जो दादूपूर–नलवी नहर बनायी जानी थी, उसको बन्द कर दिया है। इस प्रकार से डॉर्क जोन एरियाज में पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कथनी–कथनी एकै ढ़ाल होनी चाहिए। माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह जी कह रहे थे कि मुफ्त की मानसिकता छोड़नी चाहिए। किसी गरीब का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनकी मुफ्त की मानसिकता का क्या मतलब है ? अगर कोई सरकार किसी गरीब को सहायता पहुंचाती है तो उसमें क्या गलत करती है और गलत है तो सरकार यह बात साफ करे कि हम किसी गरीब को सहायता नहीं देना चाहते ? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर बात कही है। इसको मैं कलैरिफाई करना चाहता हूं। मैंने मुफ्त की मानसिकता की बात की थी, वह किसी गरीब और अमीर के लिए नहीं कही। मैंने कहा था कि बिजली बोर्ड जो बिजली प्रदान करता है, उसमें जितनी बिजली हम कन्ज्यूम करते हैं

उसका हर आदमी को बिल भरके भुगतान करना चाहिए। मैं गरीब या अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसका गलत अर्थ न निकाला जाए।

श्री लीला राम (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसको पढ़ने के बाद यह आभास होता है कि सरकार का आने वाले वर्षों के लिए किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में हर क्षेत्र की तरक्की की जाए। यह सब दर्शाने का काम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले दोनों तरफ के सभी विधायकगणों ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपने–अपने विचार रख रहे हैं। मेरे साथी राव दान सिंह जी ने भी विकास कार्यों के बारे में तुलनात्मक दृष्टि से जिक्र किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राव साहब को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2,000 में हम इसी विधान सभा में साथ थे और उस समय चौधरी औमप्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उस दौरान वैट लगाया गया था। तब इनकी पार्टी विपक्ष में थी और ये वोट मांगने के दौरान प्रचार करते थे कि वैट हटा देंगे। हरियाणा की जनता ने करवट बदली और प्रदेश में इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी परन्तु इन्होंने वैट को जड़ से खत्म करने की बजाय वैट को 4 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया। चौधरी औमप्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी ने 60 वर्ष से ऊपर के बुजूर्गों को उनके मान–सम्मान के लिए कहा था कि उनकी सरकार आयेगी तो बुजूर्गों को पैंशन देंगे और साढ़े आठ लाख लोगों के लिए पैंशन की स्कीम लागू की थी। तब माननीय सदस्य विपक्ष में थे और प्रदेश में इनैलो की सरकार थी। जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार आते ही पहले महीने में पैंशन बढ़ाकर 500 रुपये कर देंगे, लेकिन इन्होंने साढ़े चार साल तक एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार के 4–5 महीने रह गये थे तब इन्होंने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम किया था। आज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार 2250 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री बिशन लाल जी भी उस वक्त इसी हाउस के सदस्य हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले राव साहब ने सड़कों का जिक्र किया था। मैं भी इनको कहना चाहता हूं कि हम भी हरियाणावासी हैं। मैं राव साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में हमारी सबसे ज्यादा रिश्तेदारियां हैं इसलिए हम सहारनपुर आते जाते रहते हैं। पहले सहारनपुर से

यमुनानगर में आने के लिए मात्र 24 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता था, उस वक्त कुमारी सैलजा जी लोकसभा की सांसद थी और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अध्यक्ष महोदय, एक बार पार्टी की नारनौल रैली के लिए प्रभारी के तौर पर मेरी ड्यूटी लगाई गई थी तब मैंने मेरे साथी की गाड़ी ली और गाड़ी से हम भिवानी से आगे निकल गये। मुझे मेरा साथी बीच रास्ते में कहने लगा कि मुझे गाड़ी से नीचे उतार दो, मैं पैदल ही आ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, हमने 100 किलोमीटर का सफर और तय करना था। मैंने अपने साथी से कहा कि क्या बात हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमें पहले 8–9 घंटे नारनौल से महेन्द्रगढ़ तक जाने में लगते थे क्योंकि इस रोड पर इतने गड्ढे थे और कई बार तो हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी इन गड्ढों में धंस जाती थी और कभी गाड़ी बंद भी हो जाती थी तो गाड़ी को बाहर निकालकर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रकार से प्रदेश में विकास कार्य करवाये थे। अध्यक्ष महोदय, आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी चले जायें। मान लो आप हिसार से चण्डीगढ़ के लिए आते हैं तो आप अढ़ाई से 3 घंटे में चण्डीगढ़ पहुंच जाओगे। अध्यक्ष महोदय, इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली और मुझ से प्रैस वाले साथियों ने पूछा कि आपके सामने बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और वे आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके सामने किस प्रकार से चुनाव लड़ोगे क्योंकि उन्होंने अपने हल्के में बहुत विकास कार्य करवायें हैं और वे कैबिनेट के बहुत बड़े नेता और मंत्री भी रहे हैं। मैंने प्रैस वाले साथियों से केवल एक ही बात कही थी कि आप अपने नेता से पूछना कि पहले जब भी वे कैथल से चण्डीगढ़ जाते थे तो वे वाया कुरूक्षेत्र या वाया पटियाला से क्यों जाते थे? आपको इसी बात से अंदाजा लग जायेगा कि कितना विकास कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाये हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि वे एक बार भी सीधा अम्बाला से चण्डीगढ़ नहीं आते थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में चार से पांच घंटे कैथल से चण्डीगढ़ आने में लगते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राव साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज कैथल से चण्डीगढ़ मात्र सवा घंटे में आ सकते हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा जी को कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़े नेता और हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लीला राम जी, प्लीज जल्दी से जल्दी बाईंडअप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

महोम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, यह समय आपस में बहस करने का नहीं है, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, इलियास जी भी उस समय हमारे साथी हुआ करते थे और ये मेरी साईड में खड़े होकर बोलते थे इसलिए मैं इलियास जी से कहना चाहता हूं कि ये अपने शासन काल की कुछ बातें याद कर लें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सहमति हो तो सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल शहर से डी.पी.एस., कैथल तक की रोड मंजूर की है। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि वह सड़क मंजूर हो चुकी है और उसके कार्य के टैण्डर भी लग चुके हैं लेकिन उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमैंट की कोई अड़चन है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि फॉरेस्ट डिपार्टमैंट की उस अड़चन को जल्दी से जल्दी दूर करवाकर इस सड़क का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***18.31 बजे**

(तत्प□चात् सभा मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)